चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

09 दिसंबर–15 दिसंबर 2013

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

जनलोकपाल

अन्ना का अनशन

» 10 दिसंबर से

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

संतोष भारतीय

ऐसा लगता है कि देश एक बार फिर दो साल पहले के घटनाक्रम का साक्षी बनने वाला है. अगस्त, 2011 में जनलोकपाल के लिए जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारे ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था, तब उनके समर्थन में सारा देश खड़ा हो गया था. सरकार ने अनशन के लिए जगह देने से मना कर दिया था और अन्ना हजारे को जेल में डाल दिया था. देशभर में गुस्से की लहर दौड़ गई. लोगों ने दिल्ली में तिहाड़ जेल को घेर लिया. उसके बाद सरकार को अन्ना हजारे को बिना शर्त जेल से रिहा करना पड़ा. अन्ना के जेल से छूटने की भी एक कहानी है. मजिस्ट्रेट ने अन्ना हजारे से कहा कि आप जमानत दे दें, तो मैं आपको रिहा कर दूंगा. अन्ना हजारे ने कहा कि मैं किस बात की जमानत दूं. मुझे शांति भंग करने के आरोप में आपने गिरफ्तार किया है, तो आप मुझे सज़ा दें. मैं जेल जाऊंगा. मजिस्ट्रेट ने सज़ा दे दी और अन्ना जेल चले गए. अन्ना थके थे, जेल में चादर बिछाकर लेट गए. कुछ देर बाद जेल के अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि आपको सरकार ने बिना शर्त रिहा कर दिया है. अन्ना ने कहा कि मुझे सज़ा हुई है, अभी तो मैं जेल आया ही हूं और तुरंत कैसे रिहाई का आदेश आ गया? यह सरकार है या बनिया की दुकान? अन्ना ने जेल से निकलने से मना कर दिया. अधिकारी चले गए. थोड़ी देर के बाद जेल के अधिकारी फिर से लौटकर आए और कहा कि आप से हमारे आईजी मिलना चाहते हैं. अन्ना आईजी से मिलने गए, तो आईजी ने कहा कि अब आप आज़ाद हैं. अन्ना ने कहा मैं क़ैदी हूं, तो मैं आज़ाद कैसे हूं. आईजी ने कहा कि हमने आपको छोड़ दिया है, आप जाएं. अन्ना ने कहा कि लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा. इस पर आईजी ने कहा कि अब आप जेल से बाहर आ गए हैं, इसलिए जेल नहीं जा सकते. जवाब में अन्ना ने कहा कि अगर मैं जेल के अंदर नहीं जा सकता, तो मैं यहीं आपके दफ्तर में ही धरना दूंगा. अन्ना वहीं आईजी के दफ्तर में तीन दिन धरने पर बैठे रहे. आईजी के दफ्तर में नहाने तक का कोई इंतज़ाम नहीं था. तीन दिन के बाद जब अन्ना बाहर निकले, तो बाहर इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा था, मानों पूरी दिल्ली सड़क पर उतर आई है. रामलीला मैदान से लेकर तिहाड़ जेल तक लोग ही लोग थे.

रामलीला मैदान में 13 दिन तक अन्ना का अनशन चला, लोकसभा बैठी और रात के बारह बजे के बाद संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें सरकार ने जनलोकपाल बिल पास करने के लिए हामी भरी. इसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ हाऊस कहा गया. अन्ना के पास स्वर्गीय विलासराव देशमुख प्रधानमंत्री का पत्र लेकर गए. पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है और आपको देश में बहुत काम करना है. अब संसद ने प्रस्ताव पास कर दिया है, तो आप अनशन त्याग दें. अन्ना ने संसद के सर्वसम्मत प्रस्ताव का सम्मान करते हुए अपना अनशन छोड़ दिया.

अनशन छोड़ने के बाद अन्ना तत्काल पूरे देश में घूमना चाहते थे. उन्होंने अपने साथियों से कहा भी था कि मैं सारे देश में लोगों के पास जाना चाहता हूं, पर उस समय के उनके साथियों ने देश में घूमने की अन्ना की इच्छा का सम्मान नहीं किया और अन्ना चुपचाप रालेगण चले गए. इसके बाद की कहानी एक सपने के टूटने की कहानी है. अन्ना के साथियों ने राजनीतिक दल बनाया. अन्ना साल भर तक रालेगण में चिंतन–मनन करते रहे और 2013 की 30 जनवरी को उन्होंने पटना के गांधी मैदान में हुंकार भरी. उस सभा में लगभग पौने दो लाख लोग थे और वहां अन्ना ने एक नये संगठन का ऐलान किया, जिसका नाम रखा जनतंत्र मोर्चा. अन्ना ने 31 मार्च से सारे देश में घूमना शुरू किया. शुरुआत उन्होंने जलियांवाला बाग से की. वहां पर उन्होंने शहीद भूमि की मिट्टी अपने माथे से लगाई और फिर 28 हज़ार किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें उन्होंने हर जगह जनता से व्यवस्था परिवर्तन, लोकसभा में अच्छे उम्मीदवार, गांवों को संपूर्ण अधिकार, मौजूदा अर्थनीति की जगह कृषि आधारित–गांव आधारित अर्थनीति लागू करने की बात की, ताकि बेरोज़गारी का संपूर्ण उन्मूलन हो सके, सबको शिक्षा मिल सके, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें. हर जगह अन्ना ने यही सवाल उठाए. अन्ना ने यह भी कहा कि जनलोकपाल के रूप जनता को भ्रष्टाचार से लड़ने वाला हथियार मिल सकता था, लेकिन संसद ने जनलोकपाल क़ानून बनाने का वायदा करके भी इसे पूरा नहीं किया. संसद से अन्ना का तात्पर्य कांग्रेस से भी होता था, भारतीय जनता पार्टी से भी होता था, साथ ही संसद में बैठे हर राजनीतिक दल से होता था.

इसके बाद अन्ना की तबियत ख़राब हुई और डॉक्टरों ने उन्हें घूमने से मना किया. उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ. अन्ना के दिमाग़ में इस दौरान लगातार मंथन चलता रहा और इस मंथन की शुरुआत ऑपरेशन के तत्काल बाद हुई, जब वो आइसीयू से निकलकर बाहर आए.

अन्ना ये सोच रहे थे कि सरकार जनलोकपाल नहीं ला रही है, विपक्ष इसे लाने के लिए दबाव नहीं डाल रहा है, जनता असहाय है क्योंकि जनता को जगाने का काम कोई कर नहीं रहा है. हर आदमी सत्ता में जाने का रास्ता तलाश रहा है और शायद अन्ना अपने पुराने साथियों से, जिन्होंने उन्हें छोड़कर राजनीतिक दल बना लिया था, बहुत ही ज्यादा दुखी थे. और अचानक एक रात अन्ना ने फ़ैसला किया कि मुझे शीतकालीन सत्र शुरू होने के पांच दिन के बाद दोबारा अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठना होगा. इसके पीछे एक ही कारण था कि 28 हज़ार किलोमीटर की यात्रा में हर जगह अन्ना ने ये कहा था कि जनलोकपाल लाए बिना मैं मरूंगा नहीं और जनलोकपाल के लिए जनता को लड़ने के लिए प्रेरित भी करता रहूंगा. उस लड़ाई का पहला सिपाही भी मैं ही बनूंगा. अगर शहीद भी होना है, तो पहला शहीद मैं होऊंगा. बनारस में जब अन्ना की यात्रा पहुंची, तो वहां के प्रेस क्लब के निमंत्रण पर अन्ना ने पहली घोषणा की कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन मैं रामलीला मैदान में अनशन के लिए बैठ जाऊंगा.

शीतकालीन सत्र की तारीख़ घोषित हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने अन्ना को दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं दी. तब अन्ना ने एक ऐसा फ़ैसला लिया, जिस फ़ैसले की उम्मीद न राजनीतिक दलों को थी, न देश की जनता को थी और न ही अन्ना के साथ रहने वाले लोगों को थी. अन्ना ने प्रधानमंत्री को एक ख़त लिखा (प्रधानमंत्री को लिखा अन्ना का पत्र पेज नं. तीन पर) और उस ख़त में ये कहा कि मैं दस दिसंबर से रालेगण सिद्धी यानी अपने गांव में पूज्य यादव बाबा के मंदिर पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करूंगा और अनशन आत्मक्लेश के लिए करूंगा. आत्मक्लेश से अन्ना का तात्पर्य उस झूठ का प्रायश्चित करना है, जो झूठ संसद ने इस देश के लोगों से बोला है. आत्मक्लेश से अन्ना का तात्पर्य उस वादाख़िलाफ़ी से है, जिसे सरकार नाम की संस्था ने इस देश से किया है.

अन्ना के अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा के साथ ही देश में हलचल शुरू हो गई. ये हलचल इस देश के राजनीतिक दलों के अलावा आम जनता में भी शुरू हुई. छात्र, नौजवान सिर्फ़ अन्ना की ओर देख रहे हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र सम्मेलन बीस नवंबर को होने वाला था. अपनी पूरी कोशिश के बाद भी अन्ना इसमें नहीं जा पाए, क्योंकि अन्ना की तबियत देखकर डॉक्टरों ने सख़्ती के साथ उन्हें जाने से मना कर दिया. क्या ये देश रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ जल, जंगल, ज़मीन, ग्रामसभा को अधिकार इन सारे सवालों पर एक बार फिर खड़ा होगा? इस सवाल को लेकर राजनीतिक दलों में बेचैनी इसलिए है, क्योंकि आज के नब्बे प्रतिशत

(शेष पृष्ठ 2 पर)

जनलोकपाल के लिए प्रधानमंत्री को अन्ना हजारे का पत्र 03

भाजपा-राजद ने निकाली नीतीश के दावों की हवा 04

कामयाबियों पर भारी एक ग़लती 07

साई की महिमा 12

जनलोकपाल : अन्ना का अनशन 10 दिसंबर से

पृष्ठ एक का शेष

राजनीतिक दल मौजूदा आर्थिक नीतियों के समर्थक हैं. और दो बड़े दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और दो बड़े नेता, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी इन्हीं आर्थिक नीतियों के पोषक हैं. नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस ने आर्थिक सुधार या बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था को ठीक से लागू नहीं किया, वो इसे ठीक से लागू करेंगे. अन्ना के पुराने साथी जो अन्ना का नाम लेकर दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं और जो अन्ना से भी झूठ बोल रहे हैं, जनता से भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी इन्हीं आर्थिक नीतियों के समर्थक हैं. विदेशी निवेश, किसानों की ज़मीन, गांवों को ताक़त न देना, समाज के ग़रीब व वंचित तबकों को जीवनसंघर्ष की लड़ाई में अवसर उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता नहीं है. यहीं अन्ना अपनी सारी बातचीत में एक नया तत्व जोड़ रहे हैं. अन्ना का कहना है कि सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार में सांप्रदायिकता ज्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अगर देश ही नहीं रहेगा, तो भ्रष्टाचार से लड़ेंगे कैसे? सांप्रदायिकता इस देश को तोड़ सकती है, ये अन्ना का विश्लेषण है. दूसरी बात, जिस बात पर अन्ना ज़ोर देते हैं वो यह है कि वो गांव को मुख्य इकाई मानना चाहते हैं, न्याय व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, स्कूल–कॉलेजों को वो बेरोज़गारों की फैक्ट्री नहीं बनाना चाहते. अन्ना गांव आधारित, रोज़गार आधारित अर्थव्यवस्था की नींव रखना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने इस देश के सारे राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र भी लिखा है. अन्ना ने अपने पत्र में यह कहा है कि जो हुआ सो हुआ, अब तो हमें कम से कम इस देश के लोगों को ध्यान में रखकर आर्थिक नीतियां बनानी चाहिए.

ये सारे सवाल रामलीला मैदान में नहीं थे. रामलीला मैदान में जनलोकपाल था, जिस जनलोकपाल को लेकर अन्ना को भी धोखा मिला और देश को भी. इसके बाद अन्ना ने राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर एक सवाल खड़ा किया और ये कहा कि इस देश के सारे राजनीतिक दल असंवैधानिक हैं. संविधान में कहीं पर राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है. लोकसभा में दलों के प्रतिनिधि असंवैधानिक तरीक़े से जा रहे हैं. अन्ना को इस बात पर आश्चर्य है कि इतने साल बीत गए, न सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया और न किसी नेता ने इस पर सवाल उठाया. ये देश अंग्रेज़ों की गुलामी से छूटा और बिना कोई प्रयत्न किए हुए पार्टियों ने इस देश को अपना गुलाम बना लिया. इस देश के लोग पांच साल में एक बार वोट देते हैं और उसके बाद पांच साल राजनीतिक दलों का, सरकार का या विपक्ष का चेहरा देखते रह जाते हैं.

अन्ना ने राजनीतिक दलों को लिखे पत्र में एक और ख़ास बात कही. उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि संसद में दलों के प्रतिनिधि नहीं जाने चाहिए, लेकिन चूंकि, 65 साल से यह पद्धति चलती चली आई है, यानी सन 1952 से जबसे पहले आम चुनाव हुए हैं, संसद में दलों के प्रतिनिधि ही जा रहे हैं, इसलिए हम इसके आदी हो गए हैं. अब हम ये भरोसा ही नहीं कर सकते कि जनता के प्रतिनिधि ही संविधान के अनुसार संसद में जाकर कुछ कर पाएंगे. संसद में अटपटे सवाल कि कैसे प्रधानमंत्री चुना जाएगा, कैसे सरकार बनेगी, वो लोग उठाते हैं जो अपने देश में प्रचीन काल में व्याप्त गणतंत्र की कार्यप्रणाली से परिचित नहीं हैं. अन्ना ने अपने ख़त में लिखा कि मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करता हूं कि वो कम से कम ये वायदा तो करें कि वो गांवों को अधिकार देंगे, वो रोज़गार सृजित करने के लिए नई अर्थव्यवस्था का वायदा करेंगे. मौजूदा अर्थव्यवस्था जिसने बेकारी, ग़रीबी बढ़ाई, जिसने लोगों के हाथ से विकास छीन लिया और जिस अर्थव्यवस्था ने विकास को ग़रीबों की पहुंच से बाहर कर दिया, उस अर्थव्यवस्था के ख़िलाफ़ एक नई अर्थव्यवस्था का वायदा राजनीतिक दल करें. लोग अन्ना से पूछ रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव में किसे वोट दें. अन्ना ने उस ख़त में सभी दलों से कहा है कि आप अगर अपनी नीतियां मुझे साफ़ करेंगे तो मैं जनता को ये बताऊंगा कि उन्हें इस चुनाव में किसे वोट देना चहिए.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

अन्ना हजारे दस दिसंबर से अपने गांव रालेगण सिद्धी में अनिश्चितकालीन अनशन करने जा रहे हैं. सारे देश से अन्ना के पास फोन, ई-मेल की लाइन लगी है. हर व्यक्ति अन्ना का साथ देना चाहता है. चुनौती उनके लिए है जो अन्ना को दूर से देखते थे और पिछले आंदोलन में अन्ना का साथ नहीं दे पाए थे. इस बार अन्ना भावनात्मक आंदोलन नहीं कर रहे हैं, भावनात्मक उपवास नहीं कर रहे हैं. इस बार अन्ना बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए उपवास कर रहे हैं, जिसका पहला बिंदु जनलोकपाल है.

ये वो मुद्दा है, जो मुद्दा देश में एक ऐसे लोकसभा के चुनाव की ओर संकेत कर रहा है जहां पर तीसरा विकल्प धुंधला ही सही, लेकिन नज़र आने लगा है. अन्ना जी एक ऐसे शख़्स के रूप में उभरे हैं, जिन पर देश का, हर तबके का आदमी भरोसा कर रहा है. अन्ना जब निकलते हैं तो लोग उन्हें देखना चाहते हैं और जहां से वो जाते हैं उनके पैरों की धूल वैसे ही छूते हैं, जैसे एक ज़माने में लोग गांधी जी की छूते थे. अन्ना में बहुत सारे लोग गांधी की छवि देखते हैं. अन्ना के सवाल भी गांधी के सवाल हैं. गांधी ने अंग्रेज़ों से सवाल किए थे. गांधी ने आज़ाद भारत की सरकार से सवाल किए थे. अन्ना भी वही सवाल आज के राजनीतिक दलों से कर रहे हैं और जनता से कर रहे हैं.

इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए अन्ना हजारे दस दिसंबर से अपने गांव रालेगण सिद्धी में अनिश्चितकालीन अनशन करने जा रहे हैं. सारे देश से अन्ना के पास फोन, ई–मेल की लाइन लगी है. हर व्यक्ति अन्ना का साथ देना चाहता है. चुनौती उनके लिए है जो अन्ना को दूर से देखते थे और पिछले आंदोलन में अन्ना का साथ नहीं दे पाए थे. इस बार अन्ना भावनात्मक आंदोलन नहीं कर रहे हैं, भावनात्मक उपवास नहीं कर रहे हैं. इस बार अन्ना बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए उपवास कर रहे हैं, जिसका पहला बिंदु जनलोकपाल है. जनलोकपाल क़ानून बनने से देश के भ्रष्टाचार में पचास से साठ प्रतिशत की कमी आएगी, ऐसा अन्ना का विश्वास है. अन्ना इस सारे परिवर्तन की कमान छात्रों और नौजवानों को देना चाहते हैं, महिलाओं को देना चाहते हैं. अन्ना देश में एक नया, संकल्पयुक्त, विश्वास से भरा हुआ अभियान चलाना चाहते हैं और दस दिसंबर से होने वाला अन्ना का अनशन किन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती साबित होता है, किन राजनीतिक दलों को सीख देता है और अन्ना के अनशन के समुद्रमंथन से कैसा विष निकलता है और कैसा अमृत निकलता है, ये भविष्य के गर्भ में हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य का गर्भ, भविष्य जैसा लंबा नहीं है. ये अमृतमंथन दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इस देश को एक नये भविष्य के दरवाज़े पर लाकर खड़ा कर देगा. ये देश सौभाग्यशाली है कि इस देश में अन्ना हजारे हैं, इस देश में छात्र नौजवान हैं, इस देश में महिलाएं हैं, किसान हैं, इस देश में ग़रीब हैं और ये सब किसी राजनीतिक दल के बंधुआ मज़दूर नहीं हैं. ये सब जब खड़े होंगे तो यह देश बदलेगा. दस दिसंबर एक नई शुरुआत का अनोखा दिन बनने जा रहा है. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 05 अंक 40
दिल्ली, 09 दिसंबर–15 दिसंबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

केजरीवाल से सवाल

कुछ ही लोगों को याद अब याद होगा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे. वास्तव में एक बड़े नाटकीय बदलाव के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया. केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी दिल्ली में भले ही बदलाव का दावा कर रही हो, लेकिन उनके पूर्व सहयोगी रहे अधिकारियों का एक वर्ग केजरीवाल के इस कदम को लेकर उत्साहित नहीं है. सूत्रों के मुताबिक इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन में केजरीवाल के उस वक्तव्य को लेकर रोष है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केजरीवाल देश की सेवा के लिए नौकरी छोड़ दी. यद्यपि वे चाहते तो बतौर इनकम टैक्स कमिश्नर वे करोड़ों रुपये कमा सकते थे. इस मसले को लेकर एसोसिएशन ने रोष प्रकट करते हुए कहा है कि ऐसा कह कर केजरीवाल ने पूरे इनकम टैक्स विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. एसोसिएशन ने यह मांग की है कि अपने राजनीतिक बयानों में अरविंद केजरीवाल को ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए. केजरीवाल ने इस मसले पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है. ■

गोवा में अधिकारियों की कमी

पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाने वाला राज्य गोवा पिछले दिनों इस बात को लेकर सुर्खियों में था कि राज्य में कानून व्यवस्था गिरती जा रही है. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को निशाना बनाते हुए विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस तटीय राज्य में अपराध का कारण वहां पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कमी होना है. इस मौजूदा समय में गोवा में आठ आईएएस अधिकारी तैनात किए गए हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर जगहों पर अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है. सूत्रों के मुताबिक मनोहर पर्रिकर ने इस संदर्भ में गृह मंत्रालय से कई बार मांग की है. लेकिन मंत्रालय उनकी पसंद के अधिकारियों को देने में असमर्थ रहा. राज्य के पुलिस प्रमुख किशन कुमार अक्सर स्वास्थ्यगत कारणों से गोवा की बजाए दिल्ली में ही रहते हैं. इस साल की शुरुआत से ही पुलिस महानिरीक्षक के साथ ही कई उप पुलिस महानिरीक्षकों के पद रिक्त हैं. यह अवरोध जारी है जिसकी वजह से राज्य को यह आलोचना झेलनी पड़ रही है.■

अधिकारियों की नियुक्ति में देरी

दो राज्यों की राजधानी होने के कारण कई प्रशासनिक मुश्किलें खड़ी होती हैं. संघीय प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासन, जिसे पंजाब और हरियाणा, दोनों ही राज्यों का कार्यभार संभालना होता है, पिछले एक साल से दो सचिव स्तर के अधिकारियों की रिक्तियों के भरने का इंतज़ार कर रहा है. पिछले साल सृजित इन दो पदों पर अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है, क्योंकि कई सारे रिमाइंडर भेजने के बाद भी दोनों राज्यों का प्रशासन अभी तक कोई पैनल नहीं भेज पाया है.

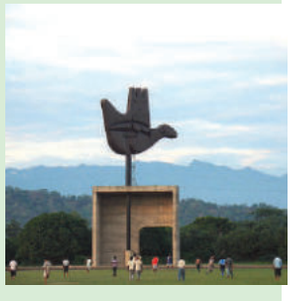

सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दोनों पदों को एक साल पहले ही सृजित किया था और चंडीगढ़ प्रशासनिक विभागों में पदों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन उन पर कोई नियुक्ति नहीं हो पाई. पहले यह व्यवस्था की गई थी कि असम–मेघालय–मणिपुर–त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी यहां पर तैनात किए जाएंगे, लेकिन यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई क्योंकि दोनों ही राज्य पुरानी चली आ रही 60–40 के अनुपात वाली व्यवस्था में बने रहना चाहते थे. पूर्व में भेजे गए पैनलों को उपयुक्त न पाने पर नए पैनल को भेजने के लिए प्रार्थना की गई थी. अगर दूसरी नियुक्यिों की बात करें तो 1992 बैच के आईएएस अधिकारी सर्वजीत सिंह और 1995 बैच के अधिकारी हसन लाल के अलावा इस संघीय प्रदेश के वित्त सचिव पद के लिए 1990 के आईएएस अधिकारी अनुराग अग्रवाल का नाम भी सुझाया गया था. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

राजीव निदेशक नियुक्त

सुरेश चन्द्र राजीव (आईटीएस–1997) को स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है. उनको (1990 आईआरएस –सी और सीई) दीपशिखा के स्थान पर नियुक्त किया गया है. दीपशिखा को अप्पा पाठ्यक्रम ट्रेनिंग के लिए नामित किया गया है.

मनीष अतिरिक्त महानिदेशक बने

1994 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस मनीष जैन को प्रसार भारती का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है. मनीष अभी अपने मूल कैडर के साथ कार्य कर रहे हैं.

कुमार एनएसजी में शामिल

1996 बैच के आपीएस अधिकारी आलोक कुमार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में उपमहानिरीक्षक के रूप में पद संभाला है. वह वर्तमान में चंडीगढ़ में उपमहानिरीक्षक के तौर पर कार्यरत है. आलोक मई 2010 में चंडीगढ़ (मुख्यालय और खुफिया) के एसएसपी के तौर पर शामिल हुए थे.

मीनाक्षी संयुक्त सचिव नियुक्त

1984 बैच की आईए और एएस मीनाक्षी गुप्ता को वित्तीय सलाहकार के रूप में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. अभी यह पद नया बना है.

वी.एल. रूई निदेशक बनीं

1998 बैच के मणिपुर त्रिपुरा कैडर की भारतीय वन सेवा अधिकारी वी.एल.रूई कुल्लै को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में अगला निदेशक नियुक्त किया गया है. 1985 बैच के भारतीय रक्षा सेवा इंजीनियर राजेश कुमार का कार्यकाल पूरा होने कारण यह पद खाली हुआ था.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

जनलोकपाल के लिए

प्रधानमंत्री को अन्ना हजारे का पत्र

अन्ना हजारे जनलोकपाल के लिए अब निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं. पिछली बार जब वे रामलीला मैदान में जनलोकपाल के लिए 13 दिन तक अनशन पर बैठे रहे, तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाने का आश्वासन अन्ना हजारे को दिया था. तब से अब तक दो वर्ष बीत गए, लेकिन यह सरकार जनलोकपाल के मुद्दे पर मौन है. इस दौरान अन्ना देश भर में जनतंत्र यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहे और अब इस लड़ाई को वे निर्णायक दौर में ले जाना चाहते हैं. अन्ना दस दिसंबर से अपने गांव रालेगण सिद्धी में अनशन करने जा रहे हैं. सही मायने में वे इस लड़ाई को निर्णायक बनाना चाहते हैं, इसकी बानगी अन्ना द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे इन पत्रों में स्पष्ट देखी जा सकती है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

कि. बा. हजारे (अण्णा)
K. B. alias Anna Hazare

राळेगण सिद्धी, तालुका पारनेर,
जिल्हा अहमदनगर (महाराष्ट्र)
पिन - ४१४३०२
☎ ०२४८८-२४०४०१/२४०२२७
www.annahazare.org

Ralegan Siddhi, Tal. Parner,
Dist. Ahmednagar (Maharashtra)
PIN - 414302
☎ 02488-240401/240227
Email: annahazareoffice@gmail.com

दि. 26.11.2013
भ्र.वि.ज.–35/2013–14

मा. श्री मनमोहन सिंह जी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार

विषय–आपके कार्यालय का दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 का पत्र हमें दि. 25 नवंबर, 2013 को प्राप्त हुआ, उस संदर्भ में...

महोदय,

आपके कार्यालय से वि. नारायनसामी जी का पत्र प्राप्त हुआ. पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ. दो साल से जनलोकपाल कानून बनवाने के लिए पत्र व्यवहार हो रहा है. लेकिन आपने और आपकी सरकार ने जनलोकपाल बिल लाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया है. दो साल में देश की जनता से बार–बार धोखाधड़ी की है. आपने अपने पत्र में लिखा है कि राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल की सिफारिश को देखते हुए केंद्र सरकार के सचिवालय को विधेयक संशोधित करने के लिए राज्यसभा में रखने की सिफारिश की थी.

यह बिल राज्यसभा के वित्तीय अधिवेशन में मान्यता के लिए पारित करने के लिए तय किया था, लेकिन उस अधिवेशन में बिल नहीं लाया गया. न लाने की वजह क्या थी, वह आपने अपने पत्र में नहीं लिखा. राज्यसभा के सेलेक्ट कमेटी ने अपना अह्वान 23 नवंबर, 2012 को सरकार को भेजा था. आज पूरा एक साल हो गया है. सेलेक्ट कमेटी का 23 नवंबर, 2012 का आह्वान आने के बाद वित्तीय अधिवेशन में बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया.

वर्षाकालीन अधिवेशन में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, न आने की कोई वजह नहीं थी. वर्षाकालीन अधिवेशन में बिल लाने के लिए आपने मुझे पत्र भेज कर वादा किया था, लेकिन वर्षाकालीन अधिवेशन में भी बिल नहीं आया. अब शीतकालीन अधिवेशन आ रहा है. आपके पत्र से शीतकालीन अधिवेशन में भी जनलोकपाल और लोकायुक्त बिल आने की संभावना कम दिखाई दे रही हैं. आप और आपकी पार्टी के नेता बार–बार यह आश्वासन देते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सशक्त लोकपाल होना चाहिए, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है. मात्र अमल में नहीं आ रहा है, यह दुर्भाग्य की बात है. सरकार जनलोकपाल और लोकायुक्त बिल लाने के लिए कटिबद्ध है, ऐसा आप सभी बार–बार कहते आए हैं, लेकिन दो साल हो चुके हैं. अभी तक बिल नहीं आया. राज्यसभा के सेलेक्ट कमेटी का आह्वान 23 नवम्बर, 2012 को आया था. अब सिर्फ राज्यसभा में चर्चा करना बाकी है, फिर भी एक साल से किस कारण चर्चा नहीं हो रही है, ये समझ में नहीं आता. आपने अपने पत्र में लिखा है कि इस विधेयक में दो रंग हैं. एक सपोर्ट करने वाला और दूसरा विरोध करने वाला.

ये दो रंग होते हुए भी आपकी सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, पेंशन बिल, जेल में बंद होते हुए भी चुनाव लड़ने की अनुमति वाला बिल, राष्ट्रपति पर का चुनाव इन सभी में सफलता पाई है. राज्यसभा में एम.पी. का सबसे बड़ा गुट आपकी पार्टी का है. सेलेक्ट कमेटी का अध्यक्ष आपकी पार्टी का है. सरकार ने यह बिल पास करना तय किया तो असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा न होने के कारण आप जनता की बार–बार दिशा भूल कर रहे हैं.

आपने पत्र में लिखा है कि यह महत्वपूर्ण विधेयक, जो राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है, उस पर लोकशाही पद्धति से सभा गृह में चर्चा करके अमल करना जरूरी है. यह बिल लोकसभा में एक दिन में सर्वसम्मति से पास होता है. स्थाई समिति में पास होता है और राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी बनाई जाती है और सेलेक्ट कमेटी अपना आह्वान 30 नवंबर, 2012 को भेज देती है और एक साल से वहां पर अटक जाता है. यह सरकार की मंशा का सवाल है. अब राज्यसभा में सिर्फ चर्चा करना बाकी है. इसके लिए एक साल का समय लगता है. इसका अर्थ स्पष्ट है कि यह बिल लाने की सरकार की मंशा नहीं है.

आप मुझे अपने द्वारा भेजे गए हर पत्र में लिखते हैं कि केंद्र सरकार लोकपाल और लोकायुक्त बिल जल्द से जल्द पारित करने के लिए प्रयत्नशील है. ऐसे झूठे आश्वासन देते–देते दो साल का समय बीत गया है, लेकिन जनलोकपाल और जनलोकायुक्त बिल अभी तक नहीं आया. मैंने पहले पत्र लिखा था कि सरकार जनलोकपाल बिल लाने में बार–बार धोखाधड़ी कर रही है, इसलिए मैं शीतकालीन अधिवेशन के पहले दिन से रामलीला मैदान में आंदोलन करूंगा.

मेरा ऑपरेशन हुआ है. तबियत ठीक नहीं है. डॉक्टर ने सफर करने से साफ मना किया है. इसलिए अब रामलीला मैदान की बजाय दूसरी जगह पर मेरा आंदोलन शुरू होगा. आगे के पत्र में वह जगह कहां होगी, वह भेज दूंगा.

भवदीय
आपका
कि.बा. अन्ना हजारे

कि. बा. हजारे (अण्णा)
K. B. alias Anna Hazare

राळेगण सिद्धी, तालुका पारनेर,
जिल्हा अहमदनगर (महाराष्ट्र)
पिन - ४१४३०२
☎ ०२४८८-२४०४०१/२४०२२७
www.annahazare.org

Ralegan Siddhi, Tal. Parner,
Dist. Ahmednagar (Maharashtra)
PIN - 414302
☎ 02488-240401/240227
Email: annahazareoffice@gmail.com

भ्र.वि.ज. 36/2013–14
दि: 28 नवंबर 2013

मा. श्री मनमोहन सिंह जी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार

विषय : जनलोकपाल कानून बनवाने का आपके द्वारा आश्वासन देकर उसका पालन न करने का विरोध करने के लिए मेरे द्वारा मेरे गांव रालेगण सिद्धी में संत श्री यादव बाबा मंदिर में 10 दिसंबर 2013 से अनशन करने हेतु...

महोदय,

जनलोकपाल बिल लाने के लिए मैंने रामलीला मैदान में 16 अगस्त से 13 दिन का अनशन किया था और देश विदेश की जनता भी इस आंदोलन में उतर गई थी. आपने मुझे 23 अगस्त, 2011 को अनशन छोड़ने के लिए एक पत्र लिखा था. वह पत्र आपकी जानकारी के लिए साथ में जोड़कर भेज रहा हूं. इसी तरह स्व. विलासराव देशमुख के हाथ आपने 27/8/2011 को मेरा अनशन छोड़ने के लिए एक पत्र मुझे भेजा था. उसमें नागरिक संहिता, निचले स्तर के अधिकारियों को लोकपाल के दायरे में लाने और हर राज्य में लोकायुक्त लाने की बात आपने मान ली थी. मैंने आपके पत्र पर विश्वास करके अपना अनशन समाप्त किया था. दो साल के बाद आज मुझे अनुभव हो रहा है कि आपने देश की जनता के साथ और मेरे साथ धोखाधड़ी की है.

दो साल से लगातार जनलोकपाल बिल आ जाए, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और आप बार–बार झूठे आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार दो साल में बार–बार आश्वासन देकर भी जनलोकपाल बिल नहीं लाई है. आपने जनलोकपाल के साथ अपने द्वारा लिखित तीन मुद्दों पर मुझे आश्वासन दिया, उसमें से एक भी मुद्दों पर दो साल में निर्णय नहीं हुआ. आज मुझे अनुभव हो रहा है कि देश में जो आंदोलन हुआ था, वह आंदोलन में शामिल जनता और मुझे चुप करने के लिए आपने मेरे साथ और देश की जनता के साथ, झूठे आश्वासन देकर धोखाधड़ी की है.

मेरे मन में ऐसी छवि थी कि आप एक अच्छे आदमी हैं. मैंने कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री जी एक अच्छे आदमी हैं. लेकिन आप सत्ता के लिए इतने झूठ बोल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास नहीं था. अगर पहले मुझे यह पता चलता कि देश की जनता के और मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो मैं रामलीला का अनशन नहीं छोड़ता. 27 अगस्त, 2011 को आपने तीन बातों पर लिखित आश्वासन दिया था. संसद सर्वसम्मति से तीन मुद्दों पर एकमत हुई थी. दो साल में आपकी सरकार ने उस आश्वासन को पूरा नहीं किया.

23 अगस्त, 2011 और 27 अगस्त, 2011 के पत्र में आपने क्या लिखा था, वह अब आपको याद नहीं होगा. आप भूल गए होंगे, इसलिए आपके पत्र की प्रति मैं आपको याद दिलाने के लिए भेज रहा हूं. वह पत्र पढ़कर आपको लगेगा कि आपने कुछ गलती की है. लेकिन सत्ता के नशे में इतनी बेहोशी होती है कि यह याद आना भी मुश्किल होता है. आपके मुताबिक श्रीमती सोनिया गांधीजी ने भी मुझे 24 जनवरी, 2013 को जनलोकपाल बिल लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा पत्र में लिखा है. इसी तरह आपके कार्यालय से श्री नारायणसामीजी के कई पत्र आए हैं. वे हर वक्त आपकी तरफ से आश्वासन देते रहे. उनका 03.09.2013 का एक पत्र जानकारी के लिए मैं भेज रहा हूं.

आपकी सरकार में ऐसे झूठ बोलने वाले लोग शामिल हैं. इनके कारण देश का क्या होगा, ऐसी चिंता होती है. क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग अगर देश चलाएं तो देश कभी तरक्की नहीं करेगा. सत्यमेव जयते हमारे देश का वेदवाक्य है. सत्य के मार्ग से ही देश की भलाई हो सकती है.

इन्सान कितनी भी बड़ी सत्ता में रहे, लेकिन उसमें बेईमानी पनपी तो एअरकंडिशन बंगले में भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है. यह आप अनुभव करते होंगे. फिर भी आप ऐसी गलती क्यों करते हैं? मेरे जीवन में मैंने करोड़ों रुपयों की योजना अपनाई, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा. कहीं पर भी बैंक बैलेंस नहीं रखा है, न कभी झूठ बोला. कहीं सत्ता हाथ में नहीं है. लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि लखपति, करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता है, वह आनंद मैं जनता और देश की सेवा में पा लेता हूं. कारण कि मैंने झूठ का छोटा–सा भी दाग जीवन में नहीं लगने दिया. मुझे आश्चर्य होता है कि आपकी सरकार में इतने झूठ बोलने वाले लोग कैसे इकठ्ठा हो गए हैं. शुरू में तो मुझ पर भी झूठे आरोप लगाते रहे. पहले ज्वाइंट कमिटी बनाते समय झूठ, ज्वाइंट कमेटी की, मीटिंग हो गई, उसमें झूठ, जनलोकपाल लाने में झूठ, आजतक इतने पत्र व्यवहार श्री नारायणसामीजी ने किए, लेकिन उन पत्रों में सच का अभाव रहा.

जनलोकपाल बिल लोकसभा में एक दिन में सर्वसम्मति से पास हुआ, स्थायी कमेटी ने पास किया, राज्यसभा में जांच के लिए सिलेक्ट कमेटी बनाई गई. उस कमेटी का अहवाल 23.11.2012 को आ गया था. अब सिर्फ राज्यसभा में चर्चा करना बाकी था, लेकिन एक साल पूरा हो गया है, अब तक चर्चा नहीं हो रही है. कारण आपके सरकार की नीयत साफ नहीं है.

आपकी तरफ से आपके पत्र में कहा गया था कि हम वित्तीय अधिवेशन में बिल लाऐंगे, लेकिन बिल नहीं लाया गया. फिर कहा गया वर्षाकालीन अधिवेशन में बिल लाऐंगे, लेकिन वर्षाकालीन अधिवेशन में भी बिल नहीं आया. अब शीतकालीन अधिवेशन आ रहा है.

एक साल राज्यसभा में चर्चा के अभाव में जनलोकपाल बिल पड़ा हुआ है. इतना समय बीतने का कोई खास कारण नहीं था. लोकपाल बिल लाने की नीयत साफ न होने के कारण इतना समय गया. राज्यसभा में 71 सदस्य आपकी पार्टी के हैं, लेकिन झूठी नीति के कारण बिल नहीं आ रहा है. आपने कई पक्ष और पार्टियों का विरोध होते हुए भी फूड सिक्योरिटी बिल, भूमि अधिग्रहण बिल, पेन्शन बिल, जेल में होते हुए चुनाव लड़ने वाला बिल, राष्ट्रपति पद का चुनाव इन सब में सफलता पाई है, लेकिन आपकी सरकार जनलोकपाल बिल नहीं ला रही है. इसका क्या कारण है? दिन–ब–दिन बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कारण जनता का जीना मुश्किल हो गया है. महंगाई बढ़ने के कारण हर व्यक्ति आजिज आ गया है.

देश की जनता पर आपकी सरकार की तरफ से जनलोकपाल बिल नहीं लाकर अन्याय किया जा रहा है. इसलिए मैं शीतकालीन अधिवेशन शुरू होने के पहले दिन से रामलीला मैदान में अनशन करूंगा, ऐसा मेरे पहले पत्र में मैंने लिखा था. लेकिन मेरा ऑपरेशन होने के कारण, तबियत ठीक न होने के कारण डॉक्टर ने सफर करने से मना किया है. इसलिए मैंने तय किया है कि मेरे गांव रालेगण सिद्धी के यादव बाबा मंदिर में मेरा अनशन 10 दिसंबर से शुरू कर रहा हूं.

जनलोकपाल बिल आने से अन्ना हजारे का व्यक्तिगत क्या लाभ है? देश में सशक्त जनलोकपाल आने से भ्रष्टाचार पर रोक लग जाएगी. देश के सामान्य लोगों को लाभ मिले, इसलिए जीवन में प्रयास कर रहा हूं. दूसरी बात यह है कि सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी होने के कारण सरकार को ऐसे कानून बनाने जरूरी हैं. जीवन में मैंने हमेशा अहिंसा मार्ग अपनाया है. कभी हिंसा नहीं की, लेकिन इस पत्र में मैंने शाब्दिक हिंसा की है. इसे मैं जानता हूं. इसके लिए सरकार की गलती है. सरकार ने एक तरफ गरीब लोगों का भ्रष्टाचार की वजह से जीना मुश्किल किया है और दूसरी ओर जनलोकपाल बिल कारण न होते हुए राज्यसभा में अटका कर रखा है. यह सरकार की गलती है. मजबूर होकर शाब्दिक हिंसा करनी पड़ी और समाज और देश की भलाई के लिए ऐसी हिंसा करने को मैं दोष नहीं मानता.

भवदीय
आपका
कि.बा. अन्ना हजारे

भाजपा से अलगाव के बाद सरकार लगातार कमज़ोर होती गई. ऐसी कई घटनाएं हुईं, जिसपर नीतीश मज़बूत स्टैंड लेने की बजाय लगातार मौन ही साधे रहे. नीतीश का मौन विपक्ष को लगातार मौक़ा देता रहा. अलगाव के कुछ दिनों बाद ही पहली घटना होती है बगहा गोली कांड. पुलिस की गोली से छह आदिवासी मारे गए, लेकिन अपनी हर यात्रा की शुरुआत बगहा से करने वाले नीतीश ने वहां जाना उचित नहीं समझा.

भाजपा-राजद ने निकाली नीतीश के दावों की हवा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया तो विपक्षी दलों ने भी नीतीश की असफलताओं का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया. भाजपा, राजद, कांग्रेस व लोजपा सहित सभी दलों ने मिलकर नीतीश सरकार के दावों की हवा निकाल दी. सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस ने भी 17 पन्ने की रिपोर्ट जारी कर कहा है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है. केंद्र से बिहार को विभिन्न योजना मदों में करोड़ों रुपये की राशि मिलने के बावजूद भी न्याय के साथ विकास का नारा पूरी तरह विफल रहा है.

सरोज सिंह/शशि सागर

नीतीश सरकार ने आठ साल पूरे कर लिए. इस दौरान सरकार के कामकाज पर आधारित रिपोर्ट कार्ड–2013 भी जारी किया गया. रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए नीतीश कुमार ने हर बार की तरह इस बार भी अपनी पीठ थपथपाई और विकास कार्यों की सराहना की. उन्होंने इस दौरान कहा भी कि विधि–व्यवस्था, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में काम हुआ है. लेकिन मुख्य विरोधी दल भाजपा, राजद, कांग्रेस व लोजपा सहित सभी दलों ने भी रिपोर्ट कार्ड जारी कर सरकार के दावों की हवा निकाल दी. अन्य दलों की बात अगर छोड़ भी दें, तो सदन में समर्थन दे रही कांग्रेस ने भी 17 पन्ने की रिपोर्ट जारी कर कहा है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है. कांग्रेस ने इस दौरान यह आरोप भी लगाया कि केंद्र से बिहार को विभिन्न योजना मदों में करोड़ों रुपये की राशि मिलने के बावजूद भी न्याय के साथ विकास का नारा पूरी तरह विफल रहा. बहरहाल, आरोप–प्रत्यारोप से अलग अगर वास्तविक आंकड़ों पर नज़र डालें तो नीतीश सरकार के रिपोर्ट कार्ड–2013 की लफ्फाजी सामने आ जाती है.

भाजपा ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर सूबे की जनता को यह बताना चाहा है कि नीतीश सरकार बस झूठे वादे और दावे कर रही है. भाजपा का कहना है कि गुड गवर्नेंस और बेहतर लॉ एंड आर्डर को नीतीश सरकार की ख़ासियत बताई जाती रही है. लेकिन हाल के कुछ महीनों में यह बुरी तरह चरमरा गई है. बगहा गोली कांड से लेकर पटना विस्फोट तक ऐसी कई घटनाएं हुईं, जिसने सरकार की लचर प्रशासनिक व्यवस्था को सामने ला दिया. जिस आठ साल के विकास की चर्चा नीतीश ने अपने रिपोर्ट कार्ड में की है, उसके बारे में भाजपा सहित लोजपा का भी कहना है कि यह अकेले नीतीश के जदयू का विकास नहीं है, इसमें भाजपा को भी श्रेय देना चाहिए. राजद का कहना है कि नीतीश सरकार जितनी जल्दी जाए, उतना ही बिहार के लिए बेहतर होगा. आठ साल पूरे होने पर यह भी चर्चा है कि नीतीश पर काम का बोझ बढ़ा है. इस वजह से क्रियान्वयन में

समस्याएं आ रही हैं. न्याय के साथ विकास के आठ साल का दावा जो सरकार करती है, उसकी कुछ मुख्य ख़ामियों को जान लेना आवश्यक है. प्रेक्षकों का मानना है कि ऐसे में इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि आख़िर क्या वजह रही कि अचानक से सरकार की लोकप्रियता पर ग्रहण लगना शुरू हो गया.

बताते चलें कि बिहार में पहली बार आतंकी घटना बोधगया में हुई. इसे सरकार की विफलता माना गया. वजह यह कि घटना के बारे में सरकार को पहले से सूचना थी. बोधगया ब्लास्ट के कुछ माह पहले ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को आईएम के आतंकी ने पूछताछ के दौरान बताया था कि बोधगया में महाबोधि मंदिर आतंकियों के निशाने पर है. इस बाबत ख़ुफ़िया एजेंसियों ने राज्य सरकार को घटना से कुछ महीने पहले ही सूचना भी दी थी. इसी तरह की आतंकी घटना जब हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान में होती है, तो घटना के दिन ही शाम छह बजे मुख्यमंत्री नीतीश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उन्हें पहले से केंद्रीय ख़ुफ़िया एजेंसी व राज्य ख़ुफ़िया एजेंसी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई थी. लेकिन नीतीश का झूठ उसी समय सामने आ गया. मुख्यमंत्री के ऐसा कहने के कुछ देर बाद ही आईबी ने इसका खंडन किया और कहा कि हमने एक अक्टूबर और 23 अक्टूबर को ही बिहार सरकार को हुंकार रैली के दौरान आतंकी घटना को लेकर आशंका जताई थी. आईबी की सूचनाओं को अगर परे भी रख दें तो रैली के दिन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज भी सवाल उठते रहते हैं. भाजपा के नेताओं के साथ ज़िला प्रशासन की जो बैठक हुई थी और उस दौरान सुरक्षा के जिन इंतज़ामात को लेकर चर्चा की गई थी, प्रशासन ने वह भी मुहैया नहीं करवाया था.

बहरहाल, भाजपा से अलगाव के बाद सरकार लगातार कमज़ोर होती गई. ऐसी कई घटनाएं हुईं, जिनपर नीतीश मज़बूत स्टैंड लेने के बजाय लगातार मौन ही साधे रहे. नीतीश का मौन विपक्ष को लगातार मौक़ा देता रहा. अलगाव के कुछ दिनों बाद ही पहली घटना होती है बगहा गोली कांड. पुलिस की गोली से इस घटना में छह थारू आदिवासी मारे जाते हैं, साथ ही दर्जन भर आदिवासी घायल भी होते हैं. हैरत की बात यह है कि अपनी हर यात्रा की शुरुआत बगहा से करने वाले नीतीश ने फारबिसगंज की तरह वहां भी जाना उचित नहीं समझा. बिहार सरकार के जिस गुड गवर्नेंस की तारीफ़ करवाई जाती है, उसकी कलई मशरख मिड डे मिल की घटना के बाद ही खुल गई थी. घटना में छपरा ज़िले के मशरख में हुई इस घटना में एक सरकारी स्कूल के 23 बच्चे विषाक्त भोजन खाने से मारे गए. इस घटना के बाद भी मुख्यमंत्री ने वहां जाने की और उपचाराधीन बच्चों से मिलने की जहमत नहीं उठाई. लगातार कहा जाता रहा कि सीएम बीमार हैं. लेकिन इस दौरान सीएम कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहे. इस घटना में सीएम और उनके सिपहसालार असंवेदनशील ही रहे. घटना के बाद सत्तापक्ष लगातार कहता रहा कि घटना के पीछे राजनीतिक साज़िश है, लेकिन अबतक इस तरह की किसी साज़िश को सरकार सिद्ध नहीं कर सकी है. अब सवाल उठ रहे हैं कि आख़िर सरकार ने अब तक कमिश्नर के रिपार्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया है और उस जांच का क्या हुआ जो एसआईटी कर रही थी. सरकार बनने के बाद नीतीश और उनकी सरकार की तारीफ़ इसलिए की जाने लगी थी कि सूबे में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई. सफलता भी हाथ लगी. बेहतर लॉ एंड आर्डर के लिए सरकार को सुशासन की सरकार का तमगा भी मिला, लेकिन यह तिलिस्म भी धीरे–धीरे टूटता नज़र आ रहा है. अन्य घटनाओं को छोड़ भी दें तो पिछले कुछ महीनों में नक्सली घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है. गत महीने औरंगाबाद के खुदवां थाना के पिसाय गांव में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर एक गाड़ी को उड़ा दिया, जिसमें सात लोग मारे गए. इससे भी पहले जमुई में नक्सलियों ने ट्रेन पर हमला कर आरपीएफ के एक जवान सहित तीन लोगों की हत्या कर दी. बताया जाता है कि औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, गया सहित सूबे के 32 ज़िलों में फिर से नक्सलियों की सक्रियता बढ़ने लगी है. बताया जाता है कि पिछले पांच महीने में 45 लोगों की हत्याएं नक्सलियों ने कर दीं, जिसमें 13 पुलिस और सुरक्षाबल के जवान थे. नक्सली घटनाओं से इतर भी सूबे में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ी हैं. बिहार पुलिस की वेबसाइट को ही देखें तो पता चलता है कि 2013 के सितंबर माह तक सूबे में हत्या के 2628 मामले दर्ज हुए हैं. वहीं चोरी के 16,187 मामले दर्ज किए गए हैं. नारी सशक्तीकरण और सम्मान की बात करने वाली सरकार की वास्तविक स्थिति यह है कि इस साल के सितंबर माह तक सूबे में बलात्कार के कुल 879 मामले दर्ज किए गए हैं. सरकार पर यह आरोप वाजिब ही लगता है कि सूबे में बलात्कार के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. वैशाली के विदुपुर प्रखंड के दो गांवों में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना ने सनसनी फैला दी. अब भी पूरा इलाक़ा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डरा सहमा रहता है. गत जुलाई माह में रामनगर–नरकटियागंज रेलखंड पर चलती ट्रेन में एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है, वहीं अरवल में एक युवती के साथ बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आता है. ये तो कुछ चर्चित मामले हैं जो सामने आ गए हैं, लेकिन इतने के बाद भी प्रशासन कोई सख़्त क़दम उठाने को तैयार नहीं दिखता है. सूबे की प्रशासनिक क्षमता लगातार कमज़ोर होती जा रही है. इसी का परिणाम है कि सूबे में एक बार फिर से साम्प्रदायिक और जातीय हिंसा अपना पांव जमा रही है. साम्प्रदायिक तनाव का ही नतीजा था कि गत महीने नवादा में कर्फ्यू लगाना पड़ा. नवादा में दो समुदायों के बीच कई दिनों तक हिंसक घटनाएं होती रहीं. बताया जाता है कि नवादा की स्थिति अभी समान्य नहीं हुई है. कुछ यही हाल बेतिया में होने वाला था. अखाड़े के जुलूस को लेकर दो सम्प्रदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. बेतिया में भी कई दिनों तक तनाव कायम रहा. हाल ही में रोहतास का बड्डी गांव जातीय हिंसा का गवाह बना. पिछले 15 अगस्त को दलित समुदाय के एक व्यक्ति की सवर्णों के द्वारा पीट–पीट कर हत्या कर दी गई, इसमें 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे.

बात अब यह भी चर्चा में है कि नीतीश अपने पास 18 विभाग रखे हुए हैं. विभागों के बंटवारे नहीं होने की वजह से क्रियान्वयन और कार्यकुशलता में कमी आई है. लेकिन नीतीश इन बातों से इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं. नीतीश कहते हैं कि यह बोझ नहीं है, हमारा कर्तव्य है और हमारा यही काम ही है. चुनौतियां जितनी भी होंगी, हम उसका मुक़ाबला करेंगे. लेकिन नीतीश के इस बड़े–बड़े बोल और हक़ीक़त में काफी अंतर है. कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की ज़िद के कारण ही सूबे के 33 ज़िलों को डेढ़ महीने विलम्ब से सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया. जबकि चार अगस्त 13 को ही मुख्यमंत्री ने दानापुर से पश्चिम चम्पारण तक का हवाई सर्वेक्षण कर कहा था कि सूबे में बाढ़ से ज्यादा सूखे की स्थिति भयावह है. बताया जाता है कि डीजल अनुदान के लिए 769 करोड़ रुपये वितरित किए जाने थे, लेकिन सरकार ने मात्र 147 करोड़ ही बांटे. सूखे के साथ–साथ बिहार का भोजपुर, सारण, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और कटिहार बाढ़ की वजह से कई हफ्ते तक परेशान रहा. आंकड़े बताते हैं कि इस साल बाढ़ से 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न ज़िलों में डूबने से 208 लोगों की मौत भी हुई है. साथ ही 104 करोड़ की फ़सल का नुकसान हुआ है. बावजूद इसके विपक्ष का आरोप है कि राहत के नाम पर खानापूर्ति ही की गई. मुख्यमंत्री नीतीश लगातार परेशानी में घिरते ही जा रहे हैं. दावे और वादे वे जो भी कर लें, लेकिन सच यही है कि अब उनकी ही कार्यशैली से उनके लोग भी ख़फ़ा होने लगे हैं. मुख्यमंत्री भले इस बात को न स्वीकारें कि उनपर कामकाज का बोझ बढ़ा है और साथ ही अफसरशाही भी बढ़ी है. लेकिन उनके ही मंत्री नरेंद्र सिंह ने यह आरोप लगाया है कि सीएम काम के बोझ तले दबे हुए हैं और ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली निराशाजनक है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने से जनता नाख़ुश है और लोगों के बीच ग़लत मैसेज जा रहा है. नरेंद्र सिंह अकेले नहीं हैं जिन्होंने यह आरोप लगाया है. रमई राम भी सरकार की कार्यशैली से नाराज़ नज़र आते हैं, वहीं जदयू के चिंतन शिविर में सांसद शिवानंद तिवारी ने भी नीतीश की कार्यशैली की जमकर आलोचना की. सूत्र बताते हैं विरोध करने वाले ये चेहरे तो सामने आ गए हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नीतीश की कार्यशैली से नाख़ुश हैं और उनका विरोध भी नीतीश को जल्द ही झेलना पड़ सकता है. भाजपा नेता सुशील मोदी कहते हैं कि हमने अपनी रिपोर्ट में यह आंकड़ों के साथ साबित कर दिया है कि बिहार में अब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है. मुख्यमंत्री के पास वक्त नहीं है और विकास वक्त खोजता है, लिहाज़ा विकास के सारे काम ठप हैं और लोगों के दिलों में एक बार फिर डर समाने लगा है. जल्द ही इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो फिर पटरी पर आई बिहार की गाड़ी बेपटरी हो सकती है. ■

नीतीश लगातार परेशानी में घिरते जा रहे हैं. दावे अब उनकी ही कार्यशैली से उनके लोग भी ख़फ़ा होने लगे हैं. मुख्यमंत्री भले इस बात को न स्वीकारें कि उनपर कामकाज का बोझ बढ़ा है और साथ ही अफसरशाही भी बढ़ी है. लेकिन उनके ही मंत्री नरेंद्र सिंह ने यह आरोप लगाया है कि सीएम काम के बोझ तले दबे हुए हैं और ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली निराशाजनक है. मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने से जनता नाख़ुश है और लोगों के बीच ग़लत मैसेज जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

जब शिक्षित, बौद्धिक और समाज की गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति महिला की स्थिति को कमतर आंकता है, अपनी ही संस्था में कार्यरत स्त्री की दैहिक और मानसिक अवमानना करता है तो यह उस स्त्री वर्ग के भविष्य पर करारा तमाचा है जो यह सोचता है कि महिलाओं की समानता और संभावनाओं का रास्ता तभी खुलेगा, जब पुरुष शिक्षित होगा और उसकी समाज शास्त्रीय समझ उसे महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाएगी. हमारे यहां पुरुषों का एक बड़ा वर्ग घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर काम करने वाली स्त्रियों के प्रति दुराग्रह से ग्रस्त हैं. इस दिशा में स्त्री के प्रति एक गंभीर सामाजिक नज़रिये के साथ एक बड़े सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है.

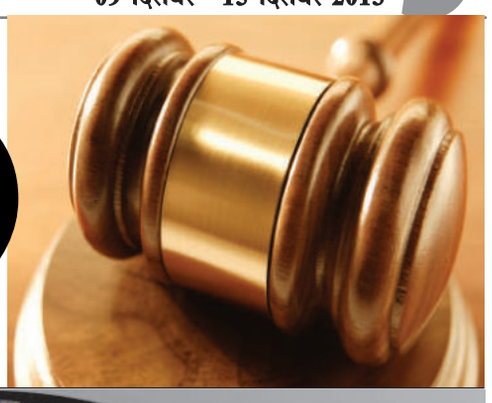

तरुण तेजपाल प्रकरण

न्याय के नायक ही अपराधी हुए

अपनी भंडाफोड पत्रकारिता के लिए मशहूर तहलका पत्रिका के मुख्य संपादक तरुण तेजपाल पर जूनियर सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया तो समाज का हर वर्ग स्तब्ध रह गया. ऐसे सवाल उठे कि जो लोग राजनीतिक और सामाजिक शुचिता के लिए झंडे उठाए फिरते हैं, अगर महिलाओं के प्रति वे ही अपराध करने पर उतर आएं, तो महिलाएं क्या करें? ऐसे लोगों के प्रति कैसा सलूक किया जाए? हमने इस प्रकरण पर समाज के विभिन्न वर्ग की महिलाओं के बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश की–

कृष्णकांत

तमाम महिलावादी संगठन यह आरोप लगाते हैं कि समय और समाज बदलने के साथ महिलाओं के शोषण के तरीके भी बदल गए हैं. महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर खड़े होने के अवसर तो ख़ूब दिखते हैं, लेकिन ये अवसर आभासी हैं. नई बाज़ारवादी संस्कृति में शोषण के तमाम न दिखने वाले स्तर और अदृश्य औज़ार मौजूद हैं, जिनके बहाने जो शक्तिशाली है, वो कमज़ोर का शोषण करता है. अवसर, तरक्की और विकास के माध्यम ही शोषण का साधन बनते हैं, जिसका शिकार ज्यादातर महिलाएं होती हैं.

जाने–माने पत्रकार तरुण तेजपाल पर जब उनकी महिला सहकर्मी ने यौन हमले का आरोप लगाया, तो जिसने सुना वह सन्न रह गया. हमने हर वर्ग की महिलाओं से जब इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया लेनी चाही, तो स्त्रियों की सोच इस रूप में सामने आई कि पुरुष समाज हमेशा स्त्री समाज से अलग खड़ा है और स्त्री अपने को न सिर्फ़ असुरक्षित पाती है, बल्कि पुरुष के रवैये से बेतरह निराश भी है. इस मामले में तरुण तेजपाल समेत तमाम लोग ऐसे भी हैं जो लड़की पर ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ऐसी घटनाओं के लिए सिर्फ़ पुरुषों को ज़िम्मेदार मानती हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में अंग्रेजी परास्नातक की छात्रा सृष्टि कहती हैं कि मैं तहलका पढ़ती रही हूं. वे लोग इन चीज़ों का जमकर विरोध करते थे. बलात्कार पर भी मैंने तरुण तेजपाल का एक लेख पढ़ा था जो बहुत अच्छा लगा था. लेकिन जब उनके बारे में ऐसा सुना, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ. यह बेहद स्तब्धकारी है कि आप ग़लत बातों का विरोध करते–करते ख़ुद ही ग़लत कर बैठे. जो भी ऐसा करे, उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए.

बीएचयू में हिंदी विभाग में शोध छात्रा और लेखिका **क्षमा सिंह** इस घटना के संदर्भ में कहती हैं कि नैतिकता का झंडा बुलंद करने वाले जब इस तरह का कोई काम करते हैं, तो ये समाज के लिए झटका होता है. तेजपाल के केस में भी यही हुआ. तेजपाल ने पहले तो गुपचुप तरीक़े से लड़की से माफ़ी मांगी. तहलका से ख़ुद ही इस्तीफ़ा दिया. अब वे ख़ुद को 'पॉलिटिकल विक्टिम' बता रहे हैं. वे अपनी ग़लती को राजनीतिक रंग दे रहे हैं. लिखित माफ़ीनामे का अर्थ वे समझते होंगे. उसके बाद वे लड़की पर सवाल उठा रहे हैं. तीन दिन में अलग–अलग बयान उन्हें ही संदिग्ध बनाता है. ऐसी किसी घटना में आरोपी कितनी भी ऊंची पहुंच वाला हो, सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए. ताकि फिर कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके. इस केस में लगता नहीं कि लड़की ने किसी लाभ के लिए ऐसा किया है. फिर भी ऐसी घटनाओं में अगर आरोप ग़लत साबित हों, तो आरोप लगाने वाले को भी सख़्त सज़ा होनी चाहिए, जिससे क़ानून का दुरुपयोग न हो.

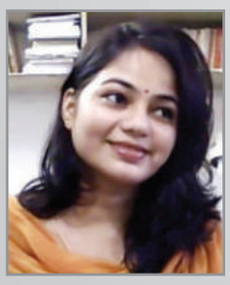

जेएनयू में हिंदी की शोध छात्रा **सुरभि त्रिपाठी** कहती हैं कि जब महिलाएं घर के भीतर थीं, तब पुरुष उनपर घर में घुसकर, अपहरण करके या राह चलते आक्रमण करता था. अब वे उनके साथ, घर से बाहर सड़क से दफ्तर तक काम कर रही हैं. वह कभी उन्हें लालच देता है, कभी उनपर अनुचित दबाव डालता है और समझौते करने के लिए तरह–तरह से मजबूर करने की कोशिश करता है. तेजपाल के मामले में लड़की की कोई ग़लती नहीं दिखती. यह एक प्रबुद्ध आदमी की फिसलन है कि वह अपराध में लिप्त हो गया. कड़ी सज़ा ही एकमात्र रास्ता है. इस प्रकरण पर छात्रा **अनिंध्या तोगड़े** कहती हैं कि गलती किसकी थी, यह बाद की बात है. अहम यह है कि उन्होंने अपराध किया, इसलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए. जब तक छोटे–बड़े हर किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, यह सब नहीं रुकने वाला. सज़ा मिलने से लोगों में संदेश जाएगा कि अपराधी कोई भी हो, बच नहीं सकता.

महिलाओं के लिए काम करने वाले एक गैर–सरकारी संगठन की कार्यकर्ता **संध्या द्विवेदी** की राय है कि लड़की को क़ानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि शुरू भी हो चुकी है, लेकिन पीड़िता की मुश्किल यह है कि वह इतने बड़े संस्थान से लड़ रही है, जहां हर कोई उसपर ही उंगली उठाएगा, क्योंकि लोगों के अपने–अपने हित हैं. पहले लड़की पर दबाव बनाया गया. अब उसी पर आरोप भी लगा रहे हैं. मामले की महिला सेल से निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और लड़की को सपरिवार सुरक्षा देनी चाहिए. संध्या का कहना है कि कई बार लड़कियों पर यह भी आरोप लगते हैं कि वे आगे बढ़ने के लिए संबंधों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन यह सोचने की बात है कि ऐसा माहौल क्यों बनाया जाए कि एक लड़की को ग़लत तरीक़ों के बारे में सोचना पड़े? यह भी पुरुष की बनाई महिला विरोधी व्यवस्था का नतीजा है. हालांकि, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई लड़की अपने करियर के लिए इस तरह के समझौते करे. इससे उसे कुछ हासिल नहीं होता.

दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी की छात्रा स्वप्निल कहती हैं कि महिलाओं के प्रति पुरुषों की या कहें पूरे समाज की सोच अब तक बदली नहीं है. हम बदल नहीं रहे हैं. हम सिर्फ़ शोर मचाते हैं लेकिन जब बदलाव की बारी आती है, तब हम ख़ुद अपराधी बन जाते हैं. स्वप्निल इसे कड़े कानूनों का अभाव और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की कमी मानती हैं. उसी विभाग की मीनाक्षी ऐसी घटनाओं को सामाजिक ढांचे से जोड़कर देखती हैं. मीनाक्षी का कहना है कि स्त्रियों की प्रताड़ना समाज में पारंपरिक रूप में मौजूद है. ऐसे अपराधों को पारिवारिक स्तर पर ही बढ़ावा मिलता है. क्या कोई मां–बाप कभी अपने लड़के को शिक्षा देता है कि घर से बाहर जाना तो किसी लड़की को परेशान मत करना? ऐसे अपराधों के लिए बहुत कड़े क़ानूनों की ज़रूरत है. उनकी बात पर ज़ोर देते हुए स्नातक की छात्रा अंजलि कहती हैं कि इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किस हैसियत का है. यह महिलाओं के प्रति अपराधिक सोच का परिणाम है. क़ानूनों को और कड़ा किया जाना चाहिए और अपराधियों को सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए. डीयू में अंग्रेज़ी की छात्रा अंजलि गुप्ता कहती हैं कि तरुण तेजपाल बार–बार अपने बयान बदल रहे हैं, जबकि दफ़्तर में किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत अपराध है. उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. बड़े लोगों को सज़ा मिलती है तो इससे अपराध करने से पहले दस बार सोचेंगे.

डीयू में हिंदी से एमए कर रही नेहा बेहद निराशा जताते हुए कहती हैं कि ऐसे मामलों में 70 प्रतिशत जानने वाले या रिश्तेदार होते हैं. पारिवारिक रिश्ते ही ज्यादातर अपराध को अंजाम देते हैं. यदि हम तरुण तेजपाल का बचाव करेंगे तो यह हर अपराधी का बचाव करना होगा. अंग्रेज़ी एमए की छात्रा सूजैन कहती हैं कि मेरी एकमात्र राय है कि तरुण तेजपाल को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. बीए तृतीय वर्ष की छात्रा निधि कड़ी निंदा करते हुए कहती हैं कि इस प्रकरण से साफ है कि न्याय के लिए लड़ने वाले भी महिलाओं के प्रति अन्याय ही करते हैं. यह कितना शर्मनाक है. उनकी क्लासमेट कीर्ति ने कहा, यह कितना भयावह है. यह बेहद तंग करने वाली बात है कि एक लड़की अपने जानने वाले के पास भी सुरक्षित नहीं है. मैं ऐसे मामलों में और कड़े क़ानून और बेहद सख़्त सज़ा की मांग करती हूं. युवा लेखिका **इंदुमति सरकार** कहती हैं कि पहले ऐसी हरकतें करना फिर दुनिया भर की दलीलें देना हैरान करने वाला है. आप जिन मसलों पर दूसरों को ग़लत कहते हैं, वही काम ख़ुद करके उसे सही ठहराने के कोशिश करते हैं. ऐसे में ये चीज़ें कैसे रुकेंगी? आपको सिर्फ़ नारे नहीं लगाना है. आपको अपने आदर्श व्यवहार में भी उतारना होगा. महिलाओं पर हमले की प्रवृत्ति पुरुषवादी सोच से जुड़ी है, जिसे बदलने की ज़रूरत है. एक तो लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वे महिलाओं के प्रति सहानुभूति रख सकें, दूसरे ऐसा करने वालों को सख़्त से सख़्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक नज़ीर कायम हो.

जेएनयू में जर्मन सेंटर की छात्रा शिप्रा कहती हैं कि एक इंटरनल समिति बने, जैसा कि जेएनयू में भी होता है, वह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की छानबीन करे. ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके. कोई स्वतंत्र बॉडी ही मामले की सही जांच कर पाएगी. अगर तरुण तेजपाल ने ग़लत किया है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए. जेएनयू के ही लैंग्विस्टिक इंपावर सेंटर में सहायक अध्यापक अपर्णा कहती हैं कि तरुण तेजपाल या अन्य किसी ऐसे मसले में बहस का तो कोई मुद्दा ही नहीं है. इसमें दूसरा पक्ष नहीं हो सकता. वे लड़की के लिए पारिवारिक सदस्य की तरह हैं, और उन्होंने जो किया, वह जघन्य अपराध है. उन्हें कठोर सज़ा मिलनी चाहिए. समाज विज्ञान केंद्र की छात्रा आस्था की भी राय कुछ ऐसी है कि ग़लत चीज़ों का कोई बचाव नहीं हो सकता. किसी जूनियर को लैंगिक प्रताड़ना देना अपराध है और अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए. जेएनयू भाषा सेंटर की छात्रा नमिता कहती हैं कि देश में हर मिनट कहीं न कहीं बलात्कार हो रहा है और कहीं कुछ नहीं होता. 16 सितंबर जैसा कांड होने के बाद भी दिल्ली में यह सब लगातार जारी है. ज़रूरत है कि सरकार बदले जो कड़ा स्टैंड ले. लोगों की सोच बदले जो ऐसी घटनाओं के विरोध में हो तभी बात बनेगी.

मैत्रेयी कॉलेज की अध्यापिका **डॉ. ममता धवन** की स्पष्ट राय है कि जब शिक्षित, बौद्धिक और समाज की गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति महिला की स्थिति को कमतर आंकता है, अपनी ही संस्था में कार्यरत स्त्री की दैहिक और मानसिक अवमानना करता है तो यह उस स्त्री वर्ग के भविष्य पर करारा तमाचा है जो यह सोचता है कि महिलाओं की समानता और संभावनाओं का रास्ता तभी खुलेगा, जब पुरुष शिक्षित होगा और उसकी समाज शास्त्रीय समझ उसे महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाएगी.

हंसराज कॉलेज में सहायक प्रोफेसर **डॉ. सुनीता** ने कहा, महिला समाज के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें इतनी जटिल हो चुकी हैं कि आमतौर पर लोग मुंह नहीं खोलना चाहते हैं. बहुतेरे मामलों में कभी–कभी सही व्यक्ति भी फंस जाता है और कभी–कभी दोषी इंसान भी बच जाता है. मेरे ख़्याल से इस मामले में तह तक जाए बिन कोई भी बात कहना जल्दबाज़ी होगी. बहुत बार ऐसा होता है कि अपना हित साधने हेतु हम सब बहुतेरे हथकंडे अपनाते हैं, जब मामला गंभीर होने लगता है, तब पहलू बदल लेते हैं. हालांकि, तहलका के तरुण तेजपाल के मामले में दस्तावेज़ी सबूत हैं. बावजूद इसके निष्पक्ष जांच की ज़रूरत जान पड़ती है.

जामिला मिलिया इस्लामिया में शोध छात्रा **तबस्सुम जहां** का कहना है कि पुरुषप्रधान समाज का सबसे बड़ा दोष है कि वह अपने ऐसी हरकतें करके महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है. तरुण तेजपाल मामले से ये ज़ाहिर होता है कि वह दोषी हैं और अब वह भी मामले पर लीपापोती करना चाहते हैं. दफ़्तर में यौन प्रताड़ना जैसी स्थिति का सामना अधिकतर महिलाओं को करना पड़ता है, पर बहुत कम मामले सामने आ पाते हैं. जो आते भी हैं उन्हें रफा–दफा करने की कोशिश की जाती है, या उल्टे लड़की पर ही दोषारोपण कर दिया जाता है कि उसने कामयाबी पाने के लिए ऐसा किया है.

छात्रा **सैयद सना** का कहना है कि तहलका जैसी सम्मानित पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल से तो बिल्कुल ऐसे कृत्य की उम्मीद नहीं की जा सकती. उन्हें सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए. लेकिन ये वक़्त किसी के क़िरदार पर बहस करने से ज़्यादा उस सोच पर बहस करने का है जो कहीं न कहीं आपकी प्रगतिशीलता पर सवाल खड़े कर रहा है. महिलाओं को अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, तुरंत प्रतिक्रिया आपको ऐसे अपराधों से बचा सकती है. युवा पत्रकार रिम्मी शर्मा कहती हैं कि ऐसी घटनाओं के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों ज़िम्मेदार हैं लेकिन अनुपात 80 और 20 का है. 80 फ़ीसद मामलों में पुरुष अपनी पॉवर और पोज़ीशन का इस्तेमाल करता है और शोषण करता है. 20 प्रतिशत मामलों में लड़कियां इसे करियर ग्रोथ और आगे बढ़ने के नाम पर जान–बूझकर ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं. अंतत: सब पैसे के साथ खड़े होते हैं. तरुण तेजपाल ने पहले भी ऐसा किया होगा, लेकिन इस बार लड़की ने विरोध का साहस दिखाया.

कवियित्री और लेखिका **विपिन चौधरी** का कहना है कि ज़ाहिर है यदि कोई लड़की इस तरह संबंध कायम करने की इच्छुक होगी तो कभी शिकायत नहीं करेगी. जब भी कोई पढ़ी–लिखी लड़की नौकरी के लिए अपने घर से बाहर निकलती है तो अपने आत्मविश्वास के बूते, कोई लड़की कभी इस तरह के संबंधों के लिए तैयार नहीं होती. यदि एक दो प्रतिशत लड़कियां अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए संबंध कायम करती हैं तो भी उन्हें देर–सवेर उसे अपने किए पर ग़ौर करना ही पड़ता है और इन सबसे बाहर निकलने के लिए वह परेशान हो उठती है. हर रोज़ यौन उत्पीड़न की शिकायतें इसलिए सामने आ रही हैं, क्योंकि लडकियां अपने आप को शिकार नहीं बनने देना चाहतीं. हाल ही में तरुण तेजपाल वाले प्रकरण में मैंने स्वयं कई पुरुषों से सुना की लड़की गई ही क्यों थी उसके साथ. अब इस मूर्खतापूर्ण बात का क्या जवाब दिया जाए. दूसरी तरफ स्त्री को ही दोषी मानने वाले पुरुषों की संख्या हमारे समाज में बहुतायत में है. हमारे यहां पुरुषों का एक बड़ा वर्ग घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर काम करने वाली स्त्रियों के प्रति दुराग्रह से ग्रस्त हैं. इस दिशा में स्त्री के प्रति एक गंभीर सामाजिक नज़रिये के साथ एक बड़े सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

समय-समय पर नेतृत्व को भितरघातियों से सतर्क करते रहना, हवा-हवाई नेताओं को उनकी औकात बताना, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ जाने से नहीं हिचकिचाना, सरकार और संगठन के मसलों को सुलझाते रहना, पार्टी के विधायकों और सांसदों की मदद करना, जनता के बीच अधिक से अधिक समय देने की आदत जैसी तमाम ख़ूबियों के चलते कुशल वक्ता नहीं होने के बाद भी शिवपाल अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं.

शिवपाल के कंधों पर मुलायम का भार

अजय कुमार

सपा प्रमुख मुलायम सिंह के अनुज शिवपाल सिंह यादव हैं. जो सपा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की आहुति दे रहे हैं. एक तरफ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, आज़म ख़ां जैसे नेता अपनी लच्छेदार बातों से समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हैं तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव पर्दे के पीछे से मोर्चा संभाले हुए हैं, जो कार्य काफी दुरूह है. वैसे तो शिवपाल अखिलेश कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके पास कई विभागों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन चुनावी जंग में वह आम कार्यकर्ता की तरह जुटे हुए हैं. राजनीतिक पंडितों का कहना है संगठन और कार्यकर्ताओं में मज़बूत पकड़ के कारण शिवपाल मुलायम की ताक़त बने हुए हैं.

फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

समाजवादी पार्टी के छोटे-बड़े सभी नेता एकजुट होकर मुलायम सिंह को तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का बीड़ा उठाए हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर सपा के बड़े नेताओं में यह विश्वास नहीं दिखाई देता है. यही वजह है कि सूबे में आज मुख्यमंत्री तो एक ही है, लेकिन उनके ऊपर सुपर मुख्यमंत्रियों की लाइन लगी है, जो अपने आप को मौजूदा सीएम अखिलेश यादव से कई मायनों में बेहतर समझते हैं. यह वह नेता हैं जो मुलायम के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके अधीन काम करने में तो अपने आप को असहज नहीं महसूस करते थे, लेकिन अखिलेश के अधीन काम करने में वे सहज नहीं हैं. ये नेता अपने आप को चतुर चालाक और अखिलेश को राजनीति के नये खिलाड़ी से अधिक महत्व नहीं देते हैं. पार्टी के कद्दावर नेता आज़म ख़ां, राम गोपाल यादव और स्वयं मुलायम सिंह खुले तौर पर तो सपा के अन्य कुछ बड़े नेता मौक़ा पड़ने पर युवा सीएम को यह एहसास कराने में पीछे नहीं रहते हैं कि अनुभव के हिसाब से वह उनसे बीस हैं. अगर ऐसा न होता तो उक्त नेता मौके-बेमौके यह जुमला बोलने का साहस नहीं जुटा पाते कि अगर मैं सीएम होता तो दंगा न होता, सरकारी कर्मचारियों को ठीक कर देता, नौकरशाहों की लगाम कस के रखता आदि-आदि. सीएम को इन नेताओं के बड़बोलेपन और बयानबाजी के कारण अक्सर दबाव में देखा जा सकता है. इसी के चलते वह कोई महत्वपूर्ण फैसला अपने दम पर लेने से हिचकते हैं कि कहीं कथित सुपर सीएम द्वारों उनकी गर्दन न पकड़ ली जाए. सपा के बड़े नेता अखिलेश को भाव नहीं देते हैं. इसका ख़ामियाज़ा यह होता है कि विपक्ष को भी अखिलेश की क़ाबिलियत पर सवाल खड़ा करने का मौका मिल जाता है. ऐसी परिस्थितियों में किसी भी सीएम के लिए शासन करना आसान नहीं होता है. अखिलेश सरकार की नाकामी की जब-जब बात होगी तो इसके लिए सुपर मुख्यमंत्रियों पर भी उंगलियां ज़रूर उठेंगी.

आज स्थिति यह है कि पार्टी के दिग्गज नेता, अखिलेश सरकार और समाजवादी संगठन के लोग मुलायम के मिशन-2014 को पूरा करने के लिए तो पूरी तरह से हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन इस बात की चिंता किसी को नहीं है कि अगर वह सीएम को कमजोर करेंगे तो इसका विपरीत प्रभाव दिल्ली मिशन पर पड़ेगा. खैर, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच एक नेता ऐसा भी है जो कभी सीएम की दौड़ में मुलायम के बाद सबसे आगे हुआ करता था, लेकिन अखिलेश की राजनीति में इंट्री होने और सीएम बनने के बाद भी उसने अपना आपा नहीं खोया और हालात से समझौता करना बेहतर समझा. यह नेता और कोई नहीं, सपा प्रमुख मुलायम सिंह के अनुज शिवपाल सिंह यादव हैं. जो सपा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की आहुति दे रहे हैं. एक तरफ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, आज़म ख़ां जैसे नेता अपनी लच्छेदार बातों से समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हैं तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव पर्दे के पीछे से मोर्चा संभाले हुए हैं, जो कार्य काफी दुरूह है. वैसे तो वह अखिलेश कैबिनेट के कद्दावर मंत्री हैं, उनके पास कई विभागों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन चुनावी जंग में वह आम कार्यकर्ता की तरह जुटे हुए हैं. राजनीतिक पंडितों का इस संबंध में अलग ही नज़रिया है. उनका कहना है संगठन और कार्यकर्ताओं पर मज़बूत पकड़ के कारण शिवपाल यादव सपा सुप्रीमो की ताक़त बने हुए हैं. संगठन से जुड़े मसले हों या फिर अन्य विवादित मुद्दे, नेताजी उन्हें सुलझाने के लिए शिवपाल को आगे करते हैं. शिवपाल अपनी बात बेधड़क कहते हैं. चाहे मामला पार्टी के हित का हो या फिर आज़म ख़ां जैसे नेताओं के विरोध का. उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया. आज भी आज़म ख़ां को लेकर शिवपाल की त्योरियां चढ़ रहती हैं, बावजूद इसके, वह जानते हैं कि खां साहब सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के सबसे अजीज़ बने हुए हैं. शिवपाल यादव जितने समय तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज़म ख़ां की सपा में वापसी नहीं हो पाई.

समय-समय पर नेतृत्व को भीतरघातियों से सतर्क करते रहना, हवा-हवाई नेताओं को उनकी औकात बताना, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ जाने से नहीं हिचकिचाना, सरकार और संगठन के मसलों को सुलझाते रहना, पार्टी के विधायकों और सांसदों की मदद करना, जनता के बीच अधिक से अधिक समय देने की आदत जैसी तमाम ख़ूबियों के चलते कुशल वक्ता नहीं होने के बाद भी शिवपाल अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं. मुलायम सिंह यादव 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर शिवपाल से अक्सर ही गंभीर मंत्रणा करते रहते हैं. सपा प्रमुख को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आज अगर सपा सत्ता में है तो इसके लिए शिवपाल यादव के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है. बसपा के सत्ता में रहते शिवपाल ही थे, जिन्होंने माया पर दनादन हमलों की रणनीति बनाकर उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया था. शिवपाल माया पर हमला बोलने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ते थे तो बीते दिनों सपा के एक कार्यक्रम में उन्होंने मंच से ही पार्टी आलाकमान को पार्टी के विभीषणों से सचेत रहने की हिदायत देकर जता दिया था कि उनके लिए पार्टी के हितों से ऊपर कोई नहीं है.

समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल आज की तारीख़ में पार्टी के लिए बहुउपयोगी नेता हैं. मुज़फ़्फ़रनगर में दंगा हुआ. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़ितों का हाल लेने के लिए दंगा प्रभावित इलाकों में गए तो वहां उन्हें दंगा पीड़ितों की नाराज़गी झेलनी पड़ी, काले झंडे दिखाए गए. स्थिति यह है कि आज तक सपा प्रमुख दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. मुलायम को डर सताता रहता है कि अगर उनका विरोध हो गया तो उनकी मुल्ला मुलायम वाली छवि पर ग्रहण लग सकता है. यहां तक कि आज़म ख़ां तक दंगा पीड़ितों का हालचाल लेने जाने का साहस नहीं कर सके. इस सब के बीच शिवपाल यादव ऐसे नेता थे जो वहां जाकर दंगा पीड़ितों से मिले और उनके जख्मों पर मरहम भी लगाया, बिना किसी विवाद के उनकी यात्रा पूरी हो गई. वह सभी कौमों के दंगा पीड़ितों से मिले, उनका दुख दर्द बांटा. दंगों के कारणों को पहचाना. इसी तरह से बीते दिनों कुछ प्रत्याशियों का लोकसभा का टिकट काटे जाने पर पार्टी में विरोध शुरू हुआ तो नेताजी ने शिवपाल के कंधों पर ही हालात संभालने की ज़िम्मेदारी डाली. चीनी मिल मालिकों और गन्ना किसानों के बीच का मतभेद दूर करने के लिए भी वह आगे आने में नहीं हिचकिचाए.

बहरहाल, सपा नेता शिवपाल यादव में जहां कई ख़ूबियां हैं तो कई बार अपने व्यवहार और जुबान फ़िसलने के कारण वह विवादों में भी फंस जाते हैं. कभी वह अपने विभाग के कर्मचारियों को डकैती नहीं थोड़ी-बहुत चोरी करने की हिदायत देने के कारण, तो कभी अधिकारियों द्वारा उनका पैर छूने के कारण फंस जाते हैं. वह बेनी प्रसाद को नशेड़ी और तस्कर घोषित कर देते हैं. सपा की पिछली सरकार के समय हुए निठारी कांड पर उनकी प्रतिक्रिया थी कि 'इस तरह के छोटे-मोटे कांड होते रहते हैं.' शिवपाल को लेकर परिवार में मनमुटाव की ख़बरें भी आती रही हैं, लेकिन आज भी शिवपाल सपा सुप्रीमो मुलायम की गुड लिस्ट में शामिल हैं. अपने कंधे का तमाम भार शिवपाल के कंधों पर डाल कर नेताजी अपने आप को महफ़ूज़ समझते हैं, तो यह शिवपाल की ख़ूबी ही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

जम्मू-कश्मीर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में घोटाला

मोहम्मद हारून
feedback@chauthiduniya.com

राजनीतिक शक्तियां भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने का काम करती हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक यहां सैंकड़ों राजनीतिज्ञ और नौकरशाहों को भ्रष्टाचार के आरोप में सज़ा मिल चुकी होती. राज्य भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुका है और उसको बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार को ही कुछ करना होगा. केन्द्रीय जांच एजेंसियों को काम पर लगाया जाना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार के तालाब में पड़े मगरमच्छों को पकड़ा जा सके.

जम्मू-कश्मीर में बोर्ड ऑफ़ प्रोफेशनल एंट्रेन्स परीक्षा के पूर्व चेयरमैन द्वारा मेडिकल कॉमन एंट्रेन्स परीक्षा पत्रों को बेचे जाने का सनसनीख़ेज़ मामला सामने आने से एक बार फिर यह साबित हो गया कि राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरा चुकी हैं. भ्रष्टाचार का यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी राज्य में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके हैं. कुछ दिनों पहले खाद्य आपूर्ति विभाग में 10 हज़ार क्विंटल चावल का घोटाला भी सामने आया है. कई साल पहले भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने देशभर में एक सर्वे करके पता लगाया था कि देशभर में बिहार के बाद जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार के मामले में दूसरे नंबर है. अर्थात बिहार में पिछले कई वर्षों के दौरान स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में इसे ख़त्म करने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया गया है. इसलिए निश्चित ही आज जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार के मामले में देश में नंबर वन है.

बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेन्स परीक्षा के पूर्व चेयरमैन मुश्ताक़ पीर के द्वारा मेडिकल कॉमन एंट्रेन्स प्रश्न-पत्र बेचे जाने के मामले के बारे में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार मुश्ताक़ पीर ने वर्ष 2012 की कॉमन एंट्रेन्स परीक्षा से पूर्व प्रश्न-पत्र दलालों को 65 लाख रुपये में बेचे थे. इस घोटाले में अवैध और अनैतिक रूप से पास होने वाले चालीस छात्र-छात्राओं को चिन्हित किया जा चुका है. इस घोटाले ने कितनी तबाही मचाई, इसका अनुमान इससे ही होता है कि प्रश्न-पत्र ख़रीदने वाले रईसज़ादों और रईसज़ादियों में अधिकतर वही लोग शामिल थे, जो मूल रूप से इस परीक्षा को देने के लिए अयोग्य थे. उदाहरणस्वरूप 12वीं में चार बार फेल होने वाली एक छात्रा ने यह प्रश्न-पत्र ख़रीदे और इन दिनों यह लड़की डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है.

क्राइम ब्रांच ने मुश्ताक़ पीर और उनके साथियों के विरुद्ध सभी सबूत जमा कर लिए हैं और उनके बैंक खातों को भी ज़ब्त कर लिया है. मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है. दरअसल, पुलिस बड़ी तेज़ी से इस मामले की तह तक पहुंचने में सफल हो गई है, क्योंकि प्राथमिक जांच के दौरान ही इस घोटाले के एक आरोपी ने सरकारी गवाह बनते हुए पुलिस को सारी जानकारियां उपलब्ध करा दीं. अब जबकि पूरा मामला लगभग खुलकर सामने आ गया है, राज्य में वर्ष 2012 में हुए कॉमन एंट्रेन्स टेस्ट के रिज़ल्ट पर प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है. अगर ऐसा हुआ तो गेंहू के साथ घुन भी पिस जाएगा. अतीत में भी इस प्रकार की एक और मिसाल देखने को मिली थी. वर्ष 2003 में जब एमडी एंट्रेन्स टेस्ट का एक प्रश्न-पत्र लीक हो गया था, तो सरकार ने परीक्षा को ही रद्द कर दिया था.

कहा तो यह भी जा रहा है कि इस सनसनीख़ेज़ घोटाले में कुछ राजनीतिज्ञ भी लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि सबको चौंकाते हुए घोटाले के मुख्य आरोपी मुश्ताक़ पीर की कार्य अवधि में सरकार ने बिना किसी औचित्य के विस्तार कर दिया था. विपक्ष ने इस सिलसिले में सरकार पर तीखे वार शुरू कर दिए हैं. सरकार पर खुलेआम आरोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी समेत कई दलों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस घोटाले के सामने आने के बाद इस्तीफ़ा देने की मांग की है.

विपक्ष की नेता महबूबा मुफ्ती ने चौथी दुनिया को बताया कि वह समझती हैं कि मुख्यमंत्री इस घोटाले के लिए ज़िम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला अपना दामन नहीं झाड़ सकते और उन्हें बताना होगा कि रिटायरमेंट के बाद मुश्ताक़ पीर की कार्य अवधि में सरकार ने विस्तार क्यों किया था? महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है. प्रश्नपत्र बेच कर योग्य और होनहार छात्र-छात्राओं के अधिकारों का हनन किया गया है. इस मामले की गहराई तक जांच होनी चाहिए. यह जानना आवश्यक है कि कहीं इस घोटाले को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है.

इस पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष इस मामले में सरकार के साथ सहयोग करने के बजाए प्रोपेगेंडा कर रही है. बीते सप्ताह घाटी के तराल क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रश्नपत्र घोटाले में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाने की बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार दोषियों को नहीं बख़्शेगी. इस दौरान राज्य में सिविल सोसायटी, राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों और छात्रों की ओर से कॉमन एंट्रेन्स टेस्ट के प्रश्नपत्र बेचे जाने के इस घोटाले में लिप्त लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिए जाने की मांग ज़ोर पकड़ रही है. जब से यह घोटाला सामने आया है, घाटी में आए दिन धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं.

निश्चित ही कॉमन एंट्रेन्स टेस्ट के प्रश्नपत्रों को बेचे जाने के घोटाले के आरोपियों को सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन समस्या केवल इसी घोटाले की नहीं है, बल्कि जम्मू-कश्मीर के समाज में भ्रष्टाचार के बढ़ते कल्चर की है. सिर्फ पिछले पांच सालों में भ्रष्टाचार के दर्जनभर मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हक़ीक़त तो यह है कि इन मामलों में शामिल लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इन कुछ वर्षों के दौरान जो बड़े घोटाले सामने आए, उनमें यौन उत्पीड़न, रोशनी भूमि घोटाला, फर्जी स्टेट सब्जेक्ट घोटाला, श्रीनगर में मास्टर प्लान का हुलिया बिगाड़ने का घोटाला, चावल घोटाला, सेना की ओर से जम्मू-कश्मीर के मंत्रियों को फंड मुहैया कराने का घोटाला, फ़र्ज़ी नियुक्तियों का घोटाला, नकली दवाएं बाज़ार में पहुंचाने का घोटाला और इन जैसे अन्य दर्जनों घोटाले शामिल हैं, लेकिन यह बात विश्वास के साथ कही जा सकती है कि इन घोटालों में आरोपी किसी भी व्यक्ति को अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली है और न ही इन मामलों की उस प्रकार से जांच की गई है, जिस प्रकार होनी चाहिए. जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जवाबदेही आयोग, पुलिस क्राइम ब्रांच और सतर्कता आयोग में वर्तमान और पूर्व मंत्रियों व नौकरशाहों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार और धांधलियों के 700 से अधिक केस दर्ज हैं, लेकिन इन केसों की सुनवाई कछुए की चाल की तरह हो रही है. यही हाल जवाबदेही आयोग का भी है.

युवा पत्रकार अज़हर रफ़ीक़ी का कहना है कि राजनीतिक शक्तियां भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने का काम करती हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक यहां सैंकड़ों राजनीतिज्ञ और नौकरशाहों को भ्रष्टाचार के आरोप में सज़ा मिल चुकी होती. अज़हर का कहना है कि राज्य भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुका है और उसको बाहर निकालने के लिए केन्द्र सरकार को ही कुछ करना होगा. केन्द्रीय जांच एजेंसियों को काम पर लगाया जाना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार के तालाब में पड़े मगरमच्छों को पकड़ा जा सके. अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिस्थितियां बदतर हो जाएंगी और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होगी कि केन्द्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को विकास कार्यों के लिए मिलने वाले अरबों रुपये की राशि का बड़ा हिस्सा जनता के हित में प्रयोग हो रहा है या राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की तिजोरियों में पहुंच रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

धर्म के नाम पर हो रही राजनीति केवल सांप्रदायिकता तक सीमित नहीं है, यह अब फासीवाद का रूप ले रहा है. सांप्रदायिक राजनीति सबसे पहले दूसरे धर्म को मानने वालों के प्रति नफरत फैलाती है. धर्म लोगों को जोड़ता है जबकि धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति लोगों को बांटने का काम करती है. उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत लोग सूफी संतों द्वारा फैलाए गए इंसानियत के पैगाम और उनके आचार–विचार से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म के अनुयायी बने हैं. धर्म में नफरत और ज़ोर–ज़बरदस्ती का कहीं काई स्थान नहीं है.

कामयाबियों पर भारी एक ग़लती

तरुण तेजपाल ऐसे पत्रकार हैं, जिन्होंने राजनीतिक दलों और सरकारों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बड़े-बड़े ख़ुलासे किए, जिसने सरकारों के लिए मुश्किलें खड़ी कीं. उन्होंने खेलों में मैच फिक्सिंग और रक्षा सौदे जैसे बड़े घोटालों का पर्दाफ़ाश किया. लेकिन अब वही तरुण तेजपाल ख़ुद एक ऐसे मामले में फंसे हैं, जिसके पक्ष में स्वयं उनके पास भी कोई तर्क नहीं है. क्या दूसरों का भंडाफोड़ करने वाले तेजपाल को अपनी ही कमियां दिखना बंद हो गईं?

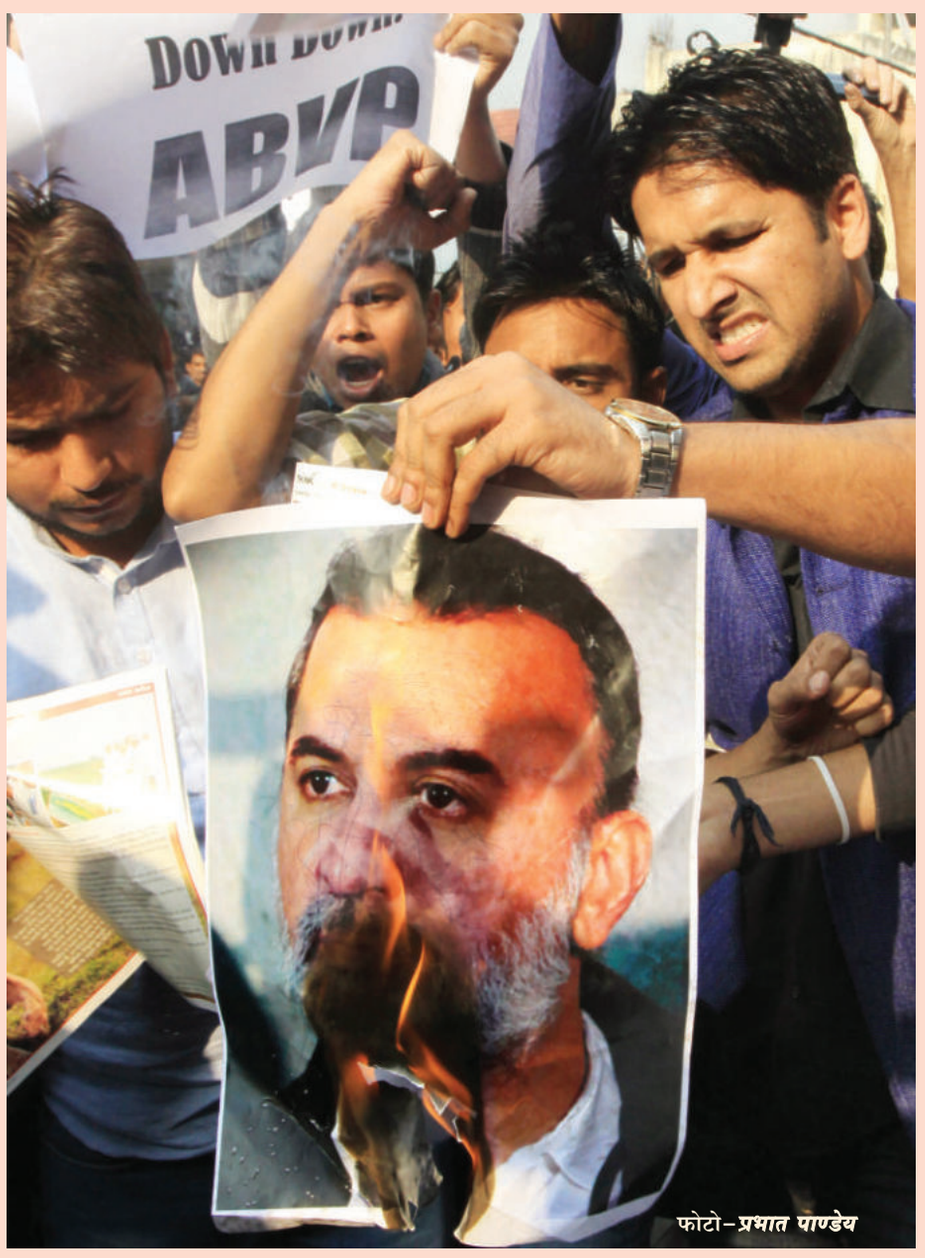

फोटो– प्रभात पाण्डेय

अरुण तिवारी

कई भाजपा नेता बंगारू लक्ष्मण को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने वाले तरुण तेजपाल ने एक सहकर्मी के साथ यौनशोषण का आरोप लगने के बाद छह महीने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया. बंगारू को पिछले साल चार वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा दे दी गई, अब बारी तरुण की है. स्टिंग आपरेशन कर देश की पत्रकारिता को नई ऊंचाई देने वाले तेजपाल अब ख़ुद गर्त की ओर हैं. जैसे-जैसे समय बीत रहा है उन पर आरोपों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है. उनपर चौतरफा हमले हो रहे हैं. वे बचाव की मुद्रा में आ गए हैं. उनके विरोधी मुखर हो रहे हैं. जो लोग कभी तेजपाल के स्टिंग आपरेशनों में फंसे थे अब वे तेजपाल को आईना दिखाने के लिए तैयार हैं.

साल 2000 में आउटलुक मैगजीन छोड़कर तहलका की स्थापना करने वाले तरुण तेजपाल ने पहली बार सुर्ख़ियां तब बटोरी थीं जब उनके साथी अनिरुद्ध बहल ने क्रिकेटर मनोज प्रभाकर के साथ मिलकर 40 घंटों का एक टेप बनाया था. मैच फिक्सिंग को लेकर बनाए गए इस टेप की वजह से उस समय काफी बवाल मचा था. उसी साल मई में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था फालेन हीरोज : द बिट्रायल ऑफ द नेशन. इस डॉक्यूमेंट्री का देशभर में काफी असर हुआ जिसकी वजह से मामले में सीबीआई जांच हुई जिसमें तीन भारतीय खिलाड़ियों को दोषी पाया गया.

साल 2001 में तहलका ने अपना सबसे बड़ा स्टिंग 'आपरेशन वेस्ट इंड' किया. तहलका के दो पत्रकारों, मैथ्यू सैमुअल और अनिरुद्ध बहल ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का स्टिंग आपरेशन किया. ये दोनो आर्म डीलर बनकर इन अधिकारियों के पास गए थे और अधिकारियों को रिश्वत दी, जिसे अधिकारियों ने स्वीकार भी कर लिया. इस स्टिंग आपरेशन में वरिष्ठ भाजपा नेता बंगारू लक्ष्मण भी फंसे थे. पिछले साल कोर्ट ने उन्हें इस मामले में सज़ा सुनाई है. मामले में उस समय समता पार्टी की नेता जया जेटली भी फंसी थीं. उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. तत्कालीन रक्षा मंत्री ने भी इस मामले में इस्तीफा दिया था लेकिन बाद उन्हें फिर से इस पद पर बहाल कर दिया गया था. पूरे मामले को लेकर एनडीए के घटक दल तृणमूल कांग्रेस ने सरकार से समर्थन खींच लिया था. जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेई की सरकार मुश्किलों में फंस गई थी. इसके बाद विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में सरकार ने सदन में पूर्ण बहुमत साबित कर दिया था.

इसके बाद एनडीए सरकार ने तहलका फाइनेंसर समेत कई रिपोर्टर पर कार्रवाई भी की. तहलका के ऑफिस की जांच की गई. इसे लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक वी एस नायपॉल तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मिले थे. उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि तहलका के साथ जो कुछ हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए भी चिंताजनक है. इस पूरे प्रकरण को लेकर पत्रकार मधु त्रेहान ने साल 2009 में एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था द तहलका मेटाफर.

साल 2007 में तहलका ने कुछ और वीडियो फुटेज जारी किए, जिसे राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा मिली. ये वीडियो फुटेज 2002 गुजरात दंगों के समय के थे, जिसमें यह दिखाया गया था कि किस तरह भाजपा नेताओं ने मिलकर मुस्लिमों की हत्या करवाई. वीडियो में बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को दिखाया गया था, जिसके नेतृत्व में नरोदा पाटिया में 91 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई थी.

साल में 2009 में जब मणिपुर की पुलिस ने इस बात की घोषणा की कि उसने एक आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराया, तब तहलका ने 12 फोटोग्राफ जारी कर लोगों के बीच यह ख़बर पहुंचाई थी कि यह एक फ़र्ज़ी मुठभेड़ थी. इन फोटोग्राफ में पुलिस को एक आदमी फार्मेसी के भीतर धकेल कर ले जाते दिखाया गया था. बाद में पुलिस फार्मेसी से उस आदमी की लाश लेकर बाहर निकली. इसके बाद मणिपुर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. विशेष रूप से ये प्रदर्शन अर्धसैनिक बलों को विशेष अधिकार देने वाले क़ानून अफस्पा के विरोध में थे. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे. कई इलाक़ों में कर्फ्यू लगा दिया गया था. साल 2010 में तहलका ने दक्षिणपंथी संगठन श्री राम सेना के नेता प्रमोद मुतालिक का वीडियो जारी किया था. वीडियो में तहलका के एक रिपोर्टर ने संगठन को एक कला प्रदर्शनी पर हमला करने के लिए धन लेते हुए दिखाया था. इसे लेकर भी काफी बवाल हुआ था और राजनीतिक सुर्ख़ियां मिली थीं.

अब सवाल यह है कि देश में क्या नेता, क्या नौकरशाह, सभी का पर्दाफ़ाश करने वाले तरुण तेजपाल बिना किसी स्टिंग आपरेशन के ही क्यों फंस गए? उन पर जिस तरह का आरोप लगा है वह किसी भी रूप में उन आरोपों से कमज़ोर नहीं है, जिसके लिए वे दूसरों को स्टिंग करते रहे हैं. उनके साथ काम करने वाली एक युवा सहकर्मी ने उन पर गोवा में थिंकफेस्ट के दौरान यौनशोषण का आरोप लगाया. वह युवती तरुण की बेटी टिया की दोस्त भी है. वह तहलका मैगजीन में काम करती थी और उसने तरुण पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया. क्या ऐसा है कि दूसरों का भंडाफोड़ करने वाले तरुण तेजपाल को अपनी ही कमियां दिखना बंद हो गईं. उन्होंने अपनी बेटी जैसी सहकर्मी का एक बार नहीं, बल्कि दो बार यौनशोषण किया. इसके बाद स्वयंभू कमांडर की तरह पश्चाताप के आंसू बहाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया. क्या तहलका के स्वर्णिम युग के अंत का समय आ गया है? अगर ऐसा है तो इसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ़ वही तरुण होंगे, जिन्होंने इसे शीर्ष पर पहुंचाया था. ■

फासीवाद के ख़िलाफ़ एकजुट हो रहे बुद्धिजीवी

अशरफ अस्थानवी

राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि जब सियासत लड़खड़ाती है, तो साहित्य ही उसे संभालता है. दिनकर की कही हुई यह बात आज सच साबित हो रही है. आज जहां कुछ लोग देश की राजनीति को प्रदूषित कर मानव समाज को तोड़ने और धर्म, संप्रदाय तथा जात-पात में बांटकर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के प्रयास में संलिप्त हैं, वहीं अनेकता में एकता की अवधारणा पर आधरित हमारे इस महान गणतांत्रिक देश को नापाक इरादों से बचाने की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं. इस मुद्दे पर साहित्यकारों, पत्रकारों, समाजसेवियों और सामाजिक सौहार्द एवं समरसता के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास रखने वाले बुद्धिजीवियों की एकजुटता भी अब धीरे-धीरे सामने आने लगी है. वैसे देश का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य इतना भयावह है कि आम लोगों के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि देश का भविष्य गांधी के पदचिन्हों पर चलेगा, या गोडसे की विचारधारा का अनुसरण करेगा. राष्ट्रीय स्तर पर दो विरोधभासी राजनीतिक विचारधाराओं के सीधे टकराव के दरम्यान पूरा देश स्तब्ध है.

देश में सिर चढ़कर बोल रही धर्म की राजनीति ने बिहार के संवेदनशील लोगों को भी हिला कर रख दिया है. स्थिति की गंभीरता के मद्देनज़र राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी यह कहने की आवश्यकता पड़ गई है कि बिहार की जनता सजग और सतर्क है, अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो इसे निपटने के लिए समाज तैयार है. राज्य सरकार के साथ-साथ कई सामाजिक संगठनों ने भी देश में धार्मिक उन्माद पैदा कर सत्ता के शिखर पर पहुंचने का सपना देखने वालों से होशियार रहने और हर हाल में सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए अघोषित जनचेतना अभियान शुरू कर दिया है. इस अभियान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके सांस्कृतिक सलाहकार पवन कुमार वर्मा भी हैं. सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता को चुनावी जंग का हथियार बनाकर देश के सिंहासन पर बैठने की योजना के दौरान भाजपा के अचानक बिहार की सत्ता से बेदख़ल होने की घटना से भी राज्य की आम जनता, ख़ासकर सामाजिक संगठनों में उत्साह का माहौल है और गांधीवादी तथा गोडसेवादी विचारधराओं के बीच एक प्रकार की अघोषित जंग का ऐलान हो चुका है.

पिछले दिनों पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम 'जहान-ए-ख़ुसरो' का आयोजन करके रूमी फाउंडेशन ने यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की गंगा-जमुनी तहज़ीब को कोई मिटा नहीं सकता है. कार्यक्रम का उदघाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया. इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा 'जहान-ए-ख़ुसरो' का सफ़र लखनऊ से शुरू होकर जयपुर और ब्रिटेन की राजधानी लंदन तक पहुंचा है. इस कार्यक्रम के माध्यम से इंसानियत का पैगाम अवाम तक बड़ी ख़ूबसूरती के साथ पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को पटना में आयोजित करने की हमारी पहल को 'उमराव जान' जैसी मक़बूल फिल्म के रचनाकार और जाने-माने फिल्म निर्माता जनाब मुज़फ़्फ़र अली साहब ने स्वीकार किया. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 'जहान-ए-ख़ुसरो' का

पटना संस्करण शुरू होने पर हमें हार्दिक ख़ुशी है और इस वक़्त हज़रत अमीर ख़ुसरो के पैगाम-ए-इंसानियत को सार्वजनिक किए जाने की भरपूर ज़रूरत है. पूरी दुनिया में असंतोष का वातावरण है. इससे निजात पाने की आवश्यकता है. अमीर ख़ुसरो की शायरी और उनका पैग़ाम दिलों को जोड़ कर ख़ुदा से रिश्ता कायम करने वाला है. 20 नवंबर, 2013 को पटना में आयोजित कार्यक्रम के आयोजन से पहले फिल्म निर्माता मुज़फ़्फ़र अली ने कहा कि 'जहान-ए-ख़ुसरो' हजरत अमीर ख़ुसरो से प्रेरित होकर तैयार किया गया है. विषम परिस्थितियों में भी ख़ुसरो ने इंसानियत के मार्ग को नहीं छोड़ा. वे अरबी, हिंदुस्तानी, ब्रज भाषा, अवधी जैसी कई भाषाओं के मिश्रण से एक ऐसी भाषा का निर्माण करते थे जो सबके दिलों में उतर जाती थी. 'जहान-ए-ख़ुसरो' कार्यक्रम में सूफी गीत और संगीत के माध्यम से न केवल श्रोताओं का मनोरंजन किया गया, बल्कि ख़ुसरो के पैग़ाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई.

कुछ ऐसा ही कार्यक्रम महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण के नरकटियागंज में 16 नवंबर, 2013 को आयोजित किया गया. साझी संस्कृति और साझी विरासत पर फोकस करने वाली इस संगोष्ठी तथा कवि सम्मेलन का आयोजन सांस्कृतिक संगठन बज्म-ए-कहकशां ने किया था. इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चार तथा तिलावत-ए-कलामे पाक के साथ हुआ. संगोष्ठी के माध्यम से यह बात सामने आई कि साझी संस्कृति ज़िंदा है और रहेगी. क्योंकि दिलों को जोड़ने वाले लोग हर दौर में रहे हैं और रहेंगे. चंपारण को सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की धरती बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि इसी सरज़मीन ने गांधी जी को वह शक्ति दी कि वह मोहनदास कर्मचंद गांधी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो गए. यह अलग बात है कि दिलों को तोड़ने वाले लोग भी हर दौर में रहे हैं, मगर उनकी साज़िशों से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है. संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रो. बबुआ जी सिंह ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो इस देश की सांस्कृतिक परंपरा के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, वह कभी कामयाब नहीं होंगे. वरिष्ठ कवि दिनेश भ्रमर ने भी अपने अध्यक्षीय संबोधन में साझी संस्कृति और साझी विरासत की वकालत की और कहा कि यह हमारे पूर्वजों की अमानत है. यदि हमने इसे सहेज कर अगली पीढ़ी के सुपुर्द नहीं किया तो इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं कर पाएगा. साहित्यकार अर्पणा सिंह बहुरानी, 'इंक़लाब' पटना के संपादक अहमद जावेद, प्रो. भागवत उपाध्याय, डॉ. अब्दुस्सलाम मजहरी, मुन्ना त्यागी, इम्तियाज़ करीम आदि ने संबोधित किया. संगोष्ठी के बाद कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ. डा अब्दुस्सलाम मजहरी, अजीज रब्बानी, कमरुज्जमा कमर, डॉ. नसीम अहमद नसीम, अरुण गोपाल और अंत में दिनेश भ्रमर ने गीतों और गजलों के माध्यम से साझी संस्कृति की रोशनी बिखेरी.

इसी बीच राजधानी पटना की संस्था नवरस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के तत्वावधन में, मीर तकी मीर की याद में स्थानीय प्रेमचंद रंगशाला में, साज़ो-आवाज़ की एक शानदार महफ़िल सजाई गई. इस मौक़े पर मीर तकी मीर की गज़लों को ख़ुशबू ख़ानम और रौशन भारती ने अपनी आवाज़ से श्रोताओं को भावविभोर कर दिया. हिंदी और उर्दू में मीर की ग़ज़लों वाले बड़े-बड़े होर्डिंग्स यह बता रहे थे कि मीर तकी और के क़द्रदान वे लोग भी हैं, जिनकी तालीम उर्दू में नहीं हुई. कार्यक्रम के एंकर और प्रसार भारती के वरिष्ठ पदाधिकारी एस.के.झा ने बताया कि हिन्दुस्तानी साहित्य में मीर तकी मीर का वही मुकाम है जो हिन्दुस्तान में गंगा का है. उन्होंने कहा कि मीर हमारे उन साधु-संतों में से एक थे जो धार्मिक कट्टरता और आडंबर में विश्वास नहीं करते थे. अमीर ख़ुसरों की तरह वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे.

अनेकता में एकता के प्रहरी केवल सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन ही नहीं हैं. वर्तमान राजनीतिक माहौल को चुनौती देने के लिए राजनीतिक पार्टी जदयू भी सामने आ गई है. पटना के सब्ज़ीबाग में पिछले 21 नवंबर को आयोजित एक मिलन समारोह में धार्मिक कट्टरता पर प्रहार करते हुए वरिष्ठ नेता और सांसद आर.सी.पी. सिंह ने कहा कि भाजपा की घृणित राजनीति से पूरा देश आतंकित है. दुनिया के सबसे बड़े और लोकतांत्रिक देश में धार्मिक कट्टरवाद के लिए कोई जगह नहीं है. इस कार्यक्रम में सभी धर्म और संप्रदाय के हज़ारों लोग शरीक थे.

देश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने तथा साझी विरासत को बनाए रखने के उद्देश्य से 'नागरिक पहल' की ओर से 26 नवंबर, 2013 को पटना में साझी विरासत और राष्ट्रीय एकता विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई. संगोष्ठी के मुख्य वक्ता व आईआईटी मुंबई के प्रो राम पुनियानी ने कहा कि धर्म के नाम पर हो रही राजनीति केवल सांप्रदायिकता तक सीमित नहीं है, यह अब फासीवाद का रूप ले रहा है. सांप्रदायिक राजनीति सबसे पहले दूसरे धर्म को मानने वालों के प्रति नफ़रत फैलाती है. धर्म लोगों को जोड़ता है जबकि धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति लोगों को बांटने का काम करती है. उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत लोग सूफी संतों द्वारा फैलाए गए इंसानियत के पैगाम और उनके आचार-विचार से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म के अनुयायी बने हैं. धर्म में नफ़रत और ज़ोर-ज़बरदस्ती का कहीं काई स्थान नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

जनलोकपाल का वादा सरकार को पूरा करना चाहिए

अन्ना हजारे ने हाल ही में जनलोकपाल बिल पास करने की अपनी मांग को दोहराते हुए प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा. दो वर्ष पहले समूचे देश की जनता अन्ना हजारे के लोकपाल की मांग को अपना समर्थन देते हुए सड़कों पर उतर आई थी. तब सरकार ने यह वादा किया था कि वह एक लोकपाल बिल लाएगी, जो कि हो सकता है कि बिल्कुल ही वैसा न हो, जैसा कि अन्ना हजारे और उनके समर्थक चाहते हैं, लेकिन फिर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बड़े पैमाने एक व्यवस्था ज़रूर बनाई जाएगी. लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इसे दो वर्ष बीत गए और अब तक इस दिशा में कोई भी क़दम नहीं उठाया गया है.

अन्ना ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को लिखा कि संसद में कई अन्य विषयों से जुड़े बिल पास हुए, लेकिन जिस बिल से पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हैं, उस जनलोकपाल बिल को लेकर सरकार मौन है. संभव है कि कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किल आ रही हो कि इस संदर्भ में पहले से मौजूद व्यवस्थाओं में बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए एक नई व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए. लेकिन जब सरकार इस बाबत देश की जनता से यह वादा कर चुकी है तो उसे लोकपाल के रूप में एक व्यवस्था को स्थापित करना ही चाहिए. वास्तव में अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो अगले लोकसभा चुनावों में उसे इसकी भारी क़ीमत चुकानी पड़ सकती है. ऐसा इसलिए, क्योंकि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश होनी चाहिए, यह आज भी एक बड़ा मुद्दा है.

यह भी सच्चाई है कि न तो भाजपा और न ही किसी अन्य दल ने इस समस्या के हल के लिए कोई विकल्प सुझाया. लेकिन सरकार देशवासियों और अन्ना हजारे से वादा करने के बावजूद भी अगर इस दिशा में कोई क़दम नहीं उठा रही है तो यह कांग्रेस पार्टी और देश की जनता दोनों के लिए ही दुखद है.

कम से कम सरकार को ऐसा करने के लिए एक कमेटी तो गठित ही करनी चाहिए. चाहे वह ऑल पार्टी कमेटी हो या फिर सिविल सोसाइटी के लोगों की हो, जो यह सुझाव दे भ्रष्टाचार के ख़ात्मे का सबसे उपयुक्त तरीक़ा क्या हो.

अन्ना हजारे ने जो सुझाव दिया है, हो सकता है कि उसको पूरी तरह लागू करने में मुश्किलें आएं. ऐसा इसलिए, क्योंकि अन्ना हजारे, लाखों सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाना चाहते हैं. ऐसा करने पर समानांतर रूप से एक और अधिकारी तंत्र स्थापित हो जाएगा.

सरकार को चाहिए कि वह एक वैकल्पिक प्रस्ताव लेकर आए, जिसके माध्यम से मंत्रियों के भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके. इस व्यवस्था के तहत इस बात का संकट भी ख़त्म हो जाएगा कि हज़ारों लोगों की निगरानी कैसे हो पाएगी, क्योंकि यह केवल मिनिस्टीरियल करप्शन पर लगाम लगाएगा. इसकी ताक़त जनलोकपाल की तरह ही होगी, जो गंभीर आरोपों की जांच करेगा और जो आरोप अप्रासंगिक होंगे, उन्हें अस्वीकार कर सकेगा. देखते हैं कि प्रधानमंत्री इस पत्र के जवाब में क्या कहते हैं. यह उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ सकारात्मक परिणाम निकलकर आएंगे.

दूसरा सवाल, जोकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की चिंता बढ़ा सकता है, वह यह कि उनके साढ़े नौ वर्ष के कार्यकाल के बाद उन्होंने क्या हासिल किया और क्या अधूरा रह गया? निश्चित तौर पर उनके कुछ व्यक्तिगत एजेंडे होंगे और कुछ प्राथमिकताएं होंगी जो उन्होंने अपने पहले और फिर दूसरे कार्यकाल के दौरान तय की होंगी.

मुझे यह भी यक़ीन है कि प्रधानमंत्री जब भी कभी अकेले में सोचते होंगे, तो यह ज़रूर महसूस करते होंगे कि उन्होंने कई मौक़ों को खो दिया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भले ही वह मौक़ा पाकिस्तान से जुड़ा हो, चीन से जुड़ा हो, संयुक्त राष्ट्र से या फिर ईरान से.

राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में देखें तो यहां भी प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर असफल रहे हैं. अर्थव्यवस्थाा के मसले पर मैं प्रधानमंत्री को अधिक दोष इसलिए नहीं दे सकता, क्योंकि अर्थव्यवस्था का अपना एक चक्रीय क्रम होता है. लेकिन क़ानून–व्यवस्था के मसले पर, माओवाद के मसले पर व दूसरे कई ऐसे मुद्दे हैं, जिसपर सरकार को सार्थक क़दम उठाने चाहिए थे. माओवाद, दरअसल क़ानून और व्यवस्था की कमी से उपजी समस्या है और इसका निदान पुलिस और सेना के माध्यम से खोजकर यह सरकार वास्तव में नरेंद्र मोदी की सोच को ही और बल दे रही है. आरएसएस और भाजपा इसी विचारधारा में विश्वास करती हैं. वे बातचीत में विश्वास नहीं करते, मतभेद बनाए रखने में विश्वास करते हैं. चाहे वह मुसलमानों के मामले में हो या सांप्रदायिकता के संदर्भ में या फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान के संदर्भ में.

वास्तव में ये लोग अमेरिका से प्रेरित हैं. अमेरिका भले ही हज़ारों मील दूर बैठा है, लेकिन अपनी ताक़त से उसकी पहुंच यहां तक है. अमेरिका जिस स्वतंत्र और निजी औद्योगिक व्यवस्था में विश्वास करता है, वही औद्योगिक नीति जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की भी है. आख़िर आरएसएस का काडर क्या है? उसके काडर छोटे व्यापारी हैं. चाहे वे दिल्ली के चांदनी चौक में हों, मुंबई के काल्बा देवी में या उसी तरह से दक्षिण भारतीय बाज़ारों में. यही वजह है कि उनके सभी मेनीफेस्टो में जो सबसे मुख्य मुद्दा होता है, वह सेल टैक्स में सुधार का होता है, क्योंकि यह उनके काडर से जुड़े लोगों को प्रभावित करता है.

हाल के दिनों देश का कॉरपोरेट जगत भी नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतर आया है. हालांकि, जो भी प्रधानमंत्री बनता है, यह वर्ग उनके समर्थन में दिखाई देने लगता है, इसलिए यह कोई चिंता का विषय नही हैं. असली चिंता है केवल मुश्किलें गिनाना और उनका हल न खोजना. भले ही भाजपा के पास कोई एजेंडा न हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ही एक नेशलन एजेंडा बनाकर चलती रही है, लेकिन अब वह भी इससे भटक रही है. प्रधानमंत्री को इन सभी मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी. अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए केवल छह महीने बचे हैं. अगर अभी भी प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बात करते हैं तो यह देश के लिए भी बेहतर होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए भी. ■

feedback@chauthiduniya.com

अन्ना ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को लिखा कि संसद में कई अन्य विषयों से जुड़े बिल पास हुए, लेकिन जिस बिल से पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हैं, उस जनलोकपाल बिल को लेकर सरकार मौन है. संभव है कि कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किल आ रही हो कि इस संदर्भ में पहले से मौजूद व्यवस्थाओं में बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए एक नई व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए. लेकिन जब सरकार इस बाबत देश की जनता से यह वादा कर चुकी है तो उसे लोकपाल के रूप में एक व्यवस्था को स्थापित करना ही चाहिए.

सरकार को चाहिए कि वह एक वैकल्पिक प्रस्ताव लेकर आए, जिसके माध्यम से मंत्रियों के भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके. इस व्यवस्था के तहत इस बात का संकट भी ख़त्म हो जाएगा कि हज़ारों लोगों की निगरानी कैसे हो पाएगी, क्योंकि यह केवल मिनिस्टीरियल करप्शन पर लगाम लगाएगा. इसकी ताक़त जनलोकपाल की तरह ही होगी, जो गंभीर आरोपों की जांच करेगा और जो आरोप अप्रासंगिक होंगे, उन्हें अस्वीकार कर सकेगा.

राष्ट्रीय संकट का निवारण कैसे हो

ठाकुर दास बंग

राष्ट्रीय संकट के संदर्भ में उत्प्रेरित अनुक्रिया राष्ट्रीय तथा स्थानीय दोनों स्तरों पर सक्रिय होगी. इस मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन खंड होंगे.

1–जिसे गांधी जी रचनात्मक प्रवृत्ति कहते थे उसके द्वारा लोगों को सक्रिय बनाना.

2–स्थानीय अथवा राष्ट्रीय प्रश्नों पर स्थानीय एवं राष्ट्र स्तरीय प्रतिरोधात्मक आंदोलन करना.

3–राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप.

राष्ट्रीय अनुबंधनात्मक एकता तथा लोकतंत्री चेतना के बचाव के लिए परिस्थिति की प्रबल मांग है कि विभिन्न जाति, भाषा और संप्रदाय वाले लोग एक–दूसरे के साथ आत्मसम्मान और सौहार्द के साथ जीवन बिताने के अभ्यासी बनें, ताकि आम लोगों के बीच उत्पन्न होने वाली अशांति के लिए राज्य को अपनी सैनिक और पुलिस की सशस्त्र शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता समाप्त हो सके. सामाजिक अथवा व्यवसायिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों–यथा भेदभाव, उचित मजदूरी की मांग, बंधुआ मजदूर प्रथा, सांप्रदायिक तथा जातिगत तनाव के निराकरण के लिए समझाने–बुझाने अथवा सत्याग्रह का उपाय काम में लाया जाए. गांव और नगर के नागरिक केवल सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस अथवा सैन्य बल के भरोसे ही अपना जीवन जी सकें, यह स्थिति बदलनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके बदले राष्ट्रीय संकट का स्थायी निवारण हो नहीं सकता.

वस्तुत: इस दिशा में हमारा प्रयास तो और अधिक दूरगामी होना चाहिए. स्थान–स्थान के समूह छोटे–छोटे लोकतंत्री समाज के रूप में एकजुट होकर जीना सीखें, ताकि उनके आधार पर एक विकेन्द्रित समाज–व्यवस्था का रूप निखर सके. इस प्रकार का एक संगठित समूह अपने–आप को अपने बीच के नवोदित गुंडातत्व के चंगुल से भी मुक्त रख सकेगा. अपने क्षेत्र में एक नए ढंग की अर्थव्यवस्था खड़ी करना रचनात्मक कार्य का मुख्य लक्ष्य रहेगा. राष्ट्र से निवेदन में जिस दिशा का संकेत है, उसी की ओर यह प्रयास उन्मुख होना चाहिए. कृषि की ऐसी योजना बनानी होगी कि बाज़ार के साथ उसकी निर्भरता कम हो और वह अधिकाधिक आत्मनिर्भरता की लक्ष्य–पूर्ति में सहायक हो सके. ग्रामीण उद्योग भी खड़े करने होंगे. गांव में रहने वाले लोगों को यह संकल्प लेना होगा कि उनके गांव का कोई भी स्वस्थ आदमी बेरोज़गार नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं होगा और न कोई बिना घर के होगा. यह असंभव नहीं है. कहा जाता है कि चीन के तमाम कम्यून्स (सामुदायिक ग्रामीण समूह) में ऐसा हुआ है.

गांव के लोग बड़े–बड़े उद्योगों द्वारा तैयार की जाने वाली ऐसी चीज़ों के बहिष्कार का भी निर्णय लें सकते हैं जो उनके गांव अथवा पास पड़ोस में तैयार होती हैं. व्यक्तिगत स्तर पर लोग संकल्प पत्र भरकर सामूहिक निर्णय के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं. भारत और इंडिया के बीच प्रच्छन्न मुक़ाबले की जो वस्तुस्थिति मौजूद है, उसकी प्रत्यक्ष जानकारी लोगों के सामने अनायास ही उपस्थित होगी, जब वे खेती की उपज का उचित मूल्य तय करते समय खेती में लगने वाली लागत (बीज, उर्बरक, कीटनाशक, बिजली, डीजल आदि के ख़र्च) का हिसाब लगाएंगे और पाएंगे कि इंडिया यानी बड़े–बड़े संगठित उद्योगों वाला क्षेत्र किस प्रकार भारत यानी कृषि क्षेत्र को लगातार चूस रहा है. ऐसे प्रश्न और प्रसंग गांव के लोगों को देश की गंभीर समस्याओं से परिचित कराएंगे. वर्तमान संदर्भ में गांव की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, यह उन्हें समझना होगा. विकेंद्रीकरण के विचार को समझने के साथ–साथ ही उन्हें सबसे अलग–अलग कटकर रहने के ख़तरे से भी बचना होगा. इस प्रकार की जागरूकता का एक राष्ट्र–स्तरीय अभिक्रम भी चलाना होगा. जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा लागू होने वाले कार्यक्रम और उसकी पृष्ठभूमि में निहित नीतियों पर निगरानी रखी जाए और कार्यक्रम का जो अंश आम लोगों के हित के विरुद्ध हो, उसके प्रति जनमत तैयार किया जाए. यदि आवश्यक और संभव हो तो उसके विरुद्ध सत्याग्रह भी किया जाए.

संघर्ष–

संघर्ष राष्ट्र के वर्तमान संकट से उबरने की अनुक्रिया का एक अविच्छिन्न भाग होगा. यह संघर्ष स्थानीय और राष्ट्रीय प्रश्नों से जुड़ा होगा. यदि स्थानीय संघर्ष समुचित ढंग से चलाया जाए तो उससे लोगों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन इसके संदर्भ में एक विशेष सावधानी भी रखनी होगी. जो भी स्थानीय कार्यक्रम अपनाया जाए, उसके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को भी अच्छी तरह लोगों के ध्यान में लाया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय परिस्थिति प्रेक्ष्य के अभाव में अनेक सफल स्थानीय संघर्ष केवल सीमित क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा सके यानी कुल मिलाकर उनके द्वारा लोकशक्ति के लिए कोई देन प्राप्त नहीं हो सकी. निकट भविष्य में ही स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मुद्दे को लेकर जन–आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता होगी. ये मुद्दे ठीक–ठीक किस रूप में उभरेंगे, समय के साथ यह स्पष्ट होगा, लेकिन अभी इतना तो माना ही जा सकता है कि रोटी और स्वतंत्रता के साथ उसका अविच्छिन्न संबंध होगा. छोटे–छोटे स्थानीय मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में व्यापक जन–आंदोलन छेड़ने होंगे. सर्वसेवा संघ के अध्यक्ष की मान्यता है कि कृषि–उपज की उचित मूल्यनीति लागू करने के लिए समूचे भारत के किसानों को राष्ट्र–व्यापी हड़ताल करनी होगी. उसका स्वरूप कुछ इस ढंग का हो सकेगा कि यदि कृषि–उपज खलिहान से किसान के घर पहुंचने तक बाज़ार में पैदावर का उचित मूल्य न मिले तो किसान दो महीने तक अपनी उपज बाज़ार में नहीं बेचेगा. गांव के भीतर के लोगों के लिए आपस में तय किए गए मूल्य पर उपज बिकती रहेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

यह संघर्ष राष्ट्र के वर्तमान संकट से उबरने की अनुक्रिया का एक अविच्छिन्न भाग होगा. यह संघर्ष स्थानीय, क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों से जुड़ा होगा. यदि स्थानीय संघर्ष समुचित ढंग से चलाया जाए, तो उससे लोगों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन इसके संदर्भ में एक विशेष सावधानी भी रखनी होगी.

पाठकों की दुनिया

बदलनी होगी मानसिकता

महिलाओं के खिलाफ दिन–प्रतिदिन अपराध बढ़ता ही जा रहा है. दिल्ली में पिछले साल दिसंबर में हुई बलात्कार की घटना के बाद जैसे लगता है कि भारत में ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई है. मासूम लड़कियां प्रतिदिन बलात्कार का शिकार हो रही हैं. इस वर्ष नवंबर तक दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग 1435 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2012 में केवल लगभग 706 मामले दर्ज हुए थे. इसे देखकर लगता है कि महिलाएं पहले से जागरूक हुई हैं या ऐसी घटनाओं में पहले से बढ़ोतरी हुई है. यदि घटनाएं बढ़ी नहीं हैं, तो इससे एक बात साफ जरूर हुई है कि महिलाएं पहले अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन कर रहीं थी. अभी फिलाहल तहलका प्रकरण से एक तस्वीर जो सामने निकल कर आ रही है, उससे यही लगता है कि महिलाओं का नौकरी के नाम पर भी उत्पीड़न किया जाता है. यह सामाजिक मूल्यों का पतन है. मानसिकता बदलने की दुहाई देने से केवल समाज नहीं सुधरेगा. हमें समाज के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी होगी.

पीयूष, दरभंगा

मुसलमानों का पिछड़ापन

2014 लोकसभा चुनाव की आहट पाते ही तमाम राजनीतिक दल अपने–अपने तरीके से मुसलमानों के हितैषी बनने एवं उनमें व्याप्त, अशिक्षा, बेकारी एवं पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तमाम तरह के झूठे वादे कर रहे हैं. नादान, अशिक्षित एवं समाज के दबे–कुचले समुदाय में से मुसलमान प्रत्येक चुनाव की भांति इस वर्ष किसी झूठे दल पर विश्वास करके खूब तबियत से वोट कर देंगे और जीत जाने के बाद विकास का दावा करने वाले दल इंद्रधनुष की भांति गायब हो जाएंगे एवं नादान मुसलमान हर बार की तरह इस बार भी हाथ मलकर और पछताकर घरों में दुबक जाएंगे एवं अगले चुनाव के इंतजार में लग जाएंगे. अपने पिछड़ेपन के लिए मुसलमान खुद जिम्मेदार है, क्योंकि अपना विश्वास अपने हाथ किया जाता है. राजनीतिक दल तो माध्यम है. जब तक मुसलमानों में शिक्षा का स्तर नहीं उठेगा, तब तक उनका विश्वास कोरी कल्पना ही सिद्ध होगी. यदि मुसलमानों को विकास की सीढ़ी पर चढ़ना है, तो उन्हें शिक्षित बनना होगा, तभी उनका विश्वास संभव है

जावेद अंसारी, देवरिया

आप भी मंडली में शामिल

आम आदमी पार्टी जिस नारे के साथ चुनाव में उतरी थी, उससे लोगों को एक आशा दिखाई दी, लेकिन धीरे–धीरे उसके चेहरे से नकाब उतर गया. आम आदमी पार्टी के सात नेताओं के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासा किया गया और स्टिंग में जो सच्चाई लोगों ने देखी, उसने आप की नींव हिलाकर रख दी. आप के नेता जवाब नहीं दे पा रहे थे और इस पार्टी ने लोगों का विश्वास तोड़ा है. अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी से लेकर अनिल अंबानी तक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी. भाजपा ने नितिन गडकरी को दोबारा अपना अध्यक्ष नहीं बनाया और कांग्रेस के मंत्रियों को भी आरोप लगने के बाद अपनी कुर्सी गवांनी पड़ी, लेकिन केजरीवाल तो सबसे भ्रष्टाचारी निकले. उनकी पार्टी के नेताओं पर जब आरोप लगे तो आप के प्रवक्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि हम 24 घंटों में जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे. समय बीतने के बाद एक नौटंकी की गई कि यह स्टिंग एक साजिश है, जो कांग्रेस ने की है. सभी पार्टियों ने आरोप लगने पर कार्रवाई की है, तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप के नेता दूसरी पार्टियों से ईमानदार बताते फिरते हैं. आम आदमी पार्टी अपने नेताओं पर कार्रवाई करती, तब लोगों को लगता कि आप सबसे अलग है, लेकिन आप भी उन्हीं मंडली शामिल हो गई और उनसे भी एक कदम आगे निकल गई.

सत्येंद्र, गोरखपुर

मीडिया में तहलका

तहलका वही पत्रिका है, जिसने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई थी. इस पत्रिका ने 2001 में एनडीए के शासन काल में ही भाजपा के अध्यक्ष के खिलाफ स्टिंग आपरेशन के जरिये तहलका मचाया था. जब मीडिया कॉरपोरेट के चकाचौंध में खोता जा रहा था, तब तरुण तेजपाल एक रोशनी बनकर उभरे थे, लेकिन अब तरुण तेजपाल की सारी नैतिकता कहां गई और उनके सामाजिक मूल्य कहां गए, जिसकी वह दुहाई देते थे. लोगों को शायद पता नहीं था कि उनके इस चेहरे के पीछे एक शैतान भी है, जो मौका पाकर किसी लड़की पर वार करेगा. शायद उस लड़की को भी यह पता नहीं रहा होगा. लोगों का मीडिया से पहले से ही भरोसा हटता जा रहा था और अब तहलका के संपादक द्वारा अपने सहकर्मी के यौन उत्पीड़न से लोगों का भरोसा मीडिया से उठेगा. तरुण तेजपाल अब कहते हैं कि मैं छह महीने के लिए अपने पद से हटकर प्रायश्चित करूंगा. क्या इससे पीड़ित को न्याय मिलेगा? शोमा चौधरी ऐसे मामलों पर लंबी–चौड़े भाषण देती थीं, अब उनकी नैतिकता कहां गई? उन्होंने भले ही दबाव में आकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन उन्होंने उस लड़की का चरित्र हनन किया है. सारी नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की वकालत करने वाले लोगों की नैतिकता अब कहां गई?

सुरूर, रांची

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई–मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

चुनाव को मनोरंजन का ज़रिया न बनने दें

यह यही चुनाव का जादू है. हमारे देश के लोग किसी भी चुनाव में चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों या देश के चुनाव हों, तमाशा देखने में लग जाते हैं. अजूबे की तरह नेताओं के भाषण सुनते हैं और भाषणों को सुनकर कोई सवाल नहीं उठाते हैं. वो ये भी ध्यान नहीं देते कि जो सवाल कॉरपोरेशन के चुनाव में उठाने चाहिए, वो विधानसभाओं में कैसे उठते हैं? उनके वायदे विधानसभाओं में कैसे होते हैं? और जिन सवालों को लोकसभा के चुनावों में उठना चहिए, उन सवालों को विधानसभाओं के ज़रिये कैसे हल किया जा सकता है. लेकिन हमारा देश पिछले 65 साल से तमाशा देखने का आदी है, तमाशा देख रहा है और तमाशा देखता रहेगा. लोग शायद चुनावों को मनोरंजन का एक ज़रिया मानते हैं.

लोकसभा चुनाव की बात करें. देश में महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, ख़राब शिक्षा, ख़राब स्वास्थ्य, ख़राब इन्फ्रास्ट्रक्चर, लोगों के काम में न आने वाला विकास जैसे सवाल, देश जब से आज़ाद हुआ, तबसे उठते रहे. सवालों के जवाब में हर चुनाव में बाज़ीगरी हुई. बाज़ीगरी का ये तमाशा लोगों ने ख़ूब देखा. लोगों ने इस सवाल पर ध्यान ही नहीं दिया कि इन सबकी जड़ में क्या है. 2014 का चुनाव भी एक ऐसे ही ग्रैंड स्केल पर भव्य तमाशा बनने वाला है. कोई भी ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि इन सबकी जड़ में देश की आर्थिक नीति है. आर्थिक नीति ही तय करती है कि उत्पादन कैसा होगा, कौन लोग उत्पादन में शामिल होंगे, कौन विकास की धारा में जाएगा, सड़कें कहां बनेंगी, स्कूल कहां खुलेंगे, अस्पताल कहां खुलेंगे, या नहीं खुलेंगे? आर्थिक नीति ही तय करती है कि कितने प्रतिशत लोगों को ग़रीबी के दायरे से निकालना है और कितने प्रतिशत लोगों को ग़रीबी के दायरे में बढ़ाना है, और लाना है? पर आर्थिक नीति पर कभी भी कोई दल, जो केंद्र में सरकार बनाना चाहता है, अपने पत्ते नहीं खोलता है.

इस बार तो हालत और मज़ेदार है. कांग्रेस उदारीकरण की नीति, खुले बाज़ार, खुली अर्थव्यवस्था की नीति पिछले 22 सालों से लागू किए जा रही है. बीच में सरकारें आईं, देवेगौड़ा की सरकार आई, गुजराल साहब की सरकार आई, अटल जी की सरकार आई, किसी ने भी आर्थिक नीति के बारे में एक भी सवाल नहीं खड़ा किया. सबने उसी आर्थिक नीति को आगे बढ़ाया. अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस उदारीकरण की नीति को ठीक से लागू नहीं कर रही है. हम इस नीति को ठीक से लागू करेंगे. यानी कांग्रेस के द्वारा ग़लत ढंग से लागू की गई उदारीकरण की नीति ने अगर बेरोज़गारी का, खेती के अलाभकारी होने का, विदेशी कंपनियों के पास जल, जंगल, ज़मीन के जाने का जितना आंकड़ा है, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उसे ठीक से लागू करेगी और उनके पास ये सारी चीज़ें और आंकड़े और बढ़ेंगे. इसका मतलब देश में विकास सबके लिए नहीं, कुछ ख़ास के लिए होगा. देश में ग़रीबों की संख्या बढ़ेगी. देश में अपराध बढ़ेगा.

ये स्थिति लोगों के समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि लोग देश को नहीं, ख़ुद को प्यार करते हैं. अक्सर कहते हैं जनता कभी ग़लत फ़ैसला नहीं देती, लेकिन जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है. वो फ़ैसला दे, तो क्या दे. जब सारे दल, सरकार बनाने का दावा करने वाले बड़े दल या उनकी दुम बनने की हसरत रखने वाले छोटे दल, ये सभी दल जब एक ही तरह की आर्थिक नीति की वकालत करें, तो जनता फ़ैसला दे तो क्या दे? बीच में कुकुरमुत्ते की तरह कुछ छोटे दल आए, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव म्युनिसिपैल्टी के सवालों पर लड़ा. लोगों ने तालियां बजाईं और कहा कि हमने सबको देख लिया, अब इनको भी देख लें. ये हमारे देश में एक कमाल की चीज़ है कि हमने इनको देख लिया, इनको देख लिया, अब इनको भी एक बार देख लें. देखें शायद कुछ अच्छा हो. और पांच साल का वक़्त बीतने के बाद हम अपना सिर पीटते हैं कि अरे हम तो बेवकूफ़ बन गए. किसने बेवकूफ़ बनाया?

मैं गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की एक पुस्तक पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर देश के सामान्य आदमी के मनोविज्ञान का वर्णन किया है. वो कहते हैं कि हमारा देश अजीब है. हम जब पांच रुपये का घड़ा ख़रीदने जाते हैं तो उसे दस जगह ठोंक बजा कर देखते हैं कि कहीं वो चटका हुआ तो नहीं है. उसके बाद हम उसका मोलभाव करते हैं. चार दुकानों पर जाते हैं, तब हम घड़ा ख़रीदते हैं. पंडित श्रीराम शर्मा आगे कहते हैं कि जब हमारे देश का सामान्य जन अपनी बेटी या बहन की शादी करने जाता है तो वो सौ तरह से पता लगाता है कि जिसके यहां वो शादी कर रहा है वो परिवार कैसा है, उसका चाल–चलन कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी नेकनामी या बदनामी कैसी है और तब वो शादी के बारे में फ़ैसला करता है. पर हमारे देश के लोग महान हैं, जो देश की क़िस्मत पांच साल के लिए जिसके हाथ में देते हैं, उसके बारे में इतना भी पता नहीं करते कि जिसके हाथ में वो क़िस्मत दे रहे हैं, क्या वो क़िस्मत देने लायक हैं. उसकी आर्थिक नीतियां क्या हैं? उसके नेता दागी तो नहीं है, अपराधी तो नहीं हैं? जीतने के बाद वो जनता के पास आएंगे भी या नहीं आएंगे? इतना ही नहीं, पूछते भी नहीं कि भाई तुमको हम वोट देने के बारे में फ़ैसला करें तो कम से कम ये तो वादा करो कि तुम हमारे पास आओगे. हमारे दुख–दर्द, तकलीफ़ें सुनोगे. और जहां भी उसका निदान हो सकता है, वहां पर कम से कम सिफ़ारिश कर दोगे. ये नहीं देखते कि उस दल में या उस व्यक्ति में ये क्षमता है कि वो देश के भविष्य को सुधारने वाले सवालों पर समझ रखता भी है या नहीं रखता है. हम जाति धर्म भाषा क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर वोट दे देते हैं और फिर अपना सिर पीटते हैं.

पिछले 65 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है. काश! संविधान के अनुसार चुनाव होते, तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि संसद में, विधानसभाओं में न जाते. संविधान के अनुरूप चुनाव न होने से जितने प्रतिनिधि संसद में जाते हैं, वे एक बड़े माफ़िया ग्रुप की तरह काम करते हैं. राजनीति के माफ़ियाओं की तरह से. चुने जाने के बाद उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं होती. उन्हें परवाह होती है सिर्फ़ विभिन्न प्रकार से आने वाले पैसों के स्रोतों को बढ़ाने की. और जब सरकार नीतियां बनाने के लिए मीटिंग करती है, तो उनमें भी ये सांसद नहीं जाते. आज किसी भी सांसद की सोच का दायरा अपने क्षेत्र और अपने ज़िले से बड़ा नहीं है, जबकि सांसद की सोच के दायरे में पूरा देश आना चाहिए.

2014 का चुनाव आ रहा है और हमने इस चुनाव में एक नई चीज़ देखी. वो नई चीज़ है कि कुछ नये राजनीतिक दल बने हैं, जो विधानसभा या लोकसभा में जाने से पहले ही राजनीतिक माफियाओं की तरह व्यवहार करने लगे हैं. उनका सबसे बड़ा नेता भी वहीं भाषा बोलता है. उनके दाएं खड़ा रहने वाला चाटुकार भी वही भाषा बोलता है. उनके बाएं खड़ा होने वाला बुद्धिजीवी भी वहीं भाषा बोलता है और उनके उम्मीदवार चुने जाने से पहले ही ज़मीन क़ब्ज़ा करने की बात, पैसे लेने की बात, एक कंपनी के हितों के मुक़ाबले दूसरी कंपनी के हितों को बढ़ाने में सहयोग देने की बात करते दिखाई देते हैं. ये किसी विधायक या सांसद का काम नहीं है कि दो कंपनियों की लड़ाई में वो किसी एक का साथ दे, पर पैसे के बदले सब कुछ संभव है. अगर 2014 के लोकसभा चुनावों में भी यही सब होने वाला है, तो फिर ये लोकतंत्र किस काम का? इसका एक वाक्य में अर्थ निकालें कि क्या हमने आज़ादी का मतलब समझा है? क्या हमने देश का मतलब समझा है? क्या हमने लोकतंत्र का मतलब समझा है? अगर नहीं समझा है तो ये मानना चाहिए कि हमारे सामने एक अलग तरह का भविष्य खड़ा है. बहुत सारे देश हैं, जहां लोकतंत्र आया, लेकिन लोकतंत्र की जगह बहुत जल्दी ही तानाशाही आ गई. फ़ौज़ की तानाशाही. और फ़ौज़ की तानाशाही से उन देशों में लंबी लड़ाई हुई और वहां फिर लोकतंत्र, लड़खड़ाते हुए ही सही, लेकिन आ रहा है. हमारे देश में जहां लोकतंत्र सबसे मज़बूत था, जहां वाणी की स्वतंत्रता है, कर्म की स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है, वहां पर हमारी इन कमज़ोरियों की वजह से, देश के लोगों की कमज़ोरियों की वजह से ऐसे लोग पार्टियों के नाम पर फल–फूल रहे हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को तबाह करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं. चलिए, सोचें कि हम सोएंगे या कम से कम 2014 के चुनाव में जागकर एक नई सुबह का आग़ाज़ करेंगे. ■

editor@chauthiduniya.com

मुश्किल में महिलाएं

मेघनाद देसाई

हाल में सामने आया तरुण तेजपाल का मामला बहुत ही दुखद और सदमा पहुंचाने वाला है. यह दुखद इसलिए है, क्योंकि वह एक प्रतिभावान लेखक और पत्रकार हैं. मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं और एक दोस्त के रूप में देखता हूं. तहलका उस समय पहली बार प्रकाश में आया था, जब उन्होंने भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के समय में रक्षा मंत्रालय में घोटाले का भंडाफोड़ किया था.

आख़िर भारतीय महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में ऐसा क्यों है कि उन्हें अजनबी ही नहीं, बल्कि वे लोग भी प्रताड़ित करते हैं, जिन्हें वे जानती हैं और भरोसा करती हैं? निर्भया केस दोनों ही मामलों में सदमा पहुंचाने वाला था. चाहे वह शारीरिक पीड़ा की बात हो या दुष्कर्मियों द्वारा उसके प्रति की गई निर्दयता. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इस मामले के बाद भी लगातार महिलाओं के साथ छेड़छाड़, पीछा करने, दुष्कर्म करने, मार दिए जाने जैसी ख़बरें आती रहती हैं. और ज्यादातर मामलों में ऐसा उनके जानने वालों के द्वारा ही किया जाता है.

चुनावी बुखार के इस मौसम में यौन शोषण पर दावों–प्रतिदावों का मुख्य केंद्र अब पीड़ित नहीं है, बल्कि पूरा मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के बीच झगड़े में तब्दील हो गया है. लेकिन हाल में प्रकाश में आईं दो घटनाएं यदि सत्य हैं तो ये वर्तमान में भारत में स्त्रियों के बारे में एक वीभत्स कहानी कहती हैं.

हाल में सामने आया तरुण तेजपाल का मामला बहुत ही दुखद और सदमा पहुंचाने वाला है. यह दुखद इसलिए है, क्योंकि वे एक प्रतिभावान लेखक और पत्रकार हैं. मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं और एक दोस्त के रूप में देखता हूं. तहलका उस समय पहली बार प्रकाश में आया था, जब उन्होंने भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के समय में रक्षा मंत्रालय में घोटाले का भंडाफोड़ किया था. इस मामले ने सरकार को पंगु बना दिया और सरकार को इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वह किसी बड़े सुधार की दिशा में आगे बढ़ सके. इसके बाद सरकार ने अपनी दिशा खो दी.

तहलका पर कांग्रेस के मुखपत्र की तरह काम करने के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में ऐसी ख़बरों पर विराम लग गया. रक्षा मंत्रालय का भंडाफोड़ करने के बाद भी तहलका ने लगातार और कई ख़ुलासे किए. वास्तव में तरुण के हालिया मामले को भी किसी और ने नहीं, बल्कि तहलका ने ही सबके सामने रखा.

यह मामला और दुखदायी इसलिए है, क्योंकि पीड़िता और तरुण के बीच पिता–पुत्री की तरह संबंध थे. इस मामले में यह सिद्ध हो चुका है कि पिता भी कभी–कभी ख़ुद ही परभक्षी साबित हो जाते हैं. उक्त महिला के यौन शोषण का प्रयास एक बार नहीं, बल्कि दो बार किया गया. इसका मतलब है कि अचानक नहीं हुआ था और न ही किसी समय के आवेग में किया गया था. यह पूर्वनियोजित था. इसके बाद हुई घटनाएं और भी ख़राब हुईं. इसके बाद संस्थान की तरफ़ से यह प्रयास किया गया कि पीड़िता मामले की कोई शिकायत न करे. इसके अलावा अपनी ग़लती का एहसास करते हुए छह महीने के लिए अपना पद छोड़ने जैसा क्षीण प्रयास भी तरुण के द्वारा किया गया. इस घटना की और भी निंदा इसलिए की जानी चाहिए, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि ऐसी न जाने कितनी और महिलाएं हैं, जिनपर इस तरह का दबाव पड़ता है और यह भी पता लगाने की ज़रूरत है कि इस तरह के कितने परभक्षियों ने ऐसा काम किया और पकड़े नहीं गए.

अगर भारत को प्रगति करनी है तो उसे अपने सम्मान देने के तर्कों को उलटना होगा. अब सिर्फ़ नेता, उम्रदराज़ व्यक्तियों और पिताओं को ही नहीं, बल्कि भारत के नौजवान युवक और महिलाओं को इज़्ज़त दी जानी चाहिए, जो भविष्य में भारत की ज़िम्मेदारी संभालने वाले हैं. विशेष रूप से उन्हें अपने से बड़े और पिताओं के द्वारा सम्मान दिया जाना चाहिए.

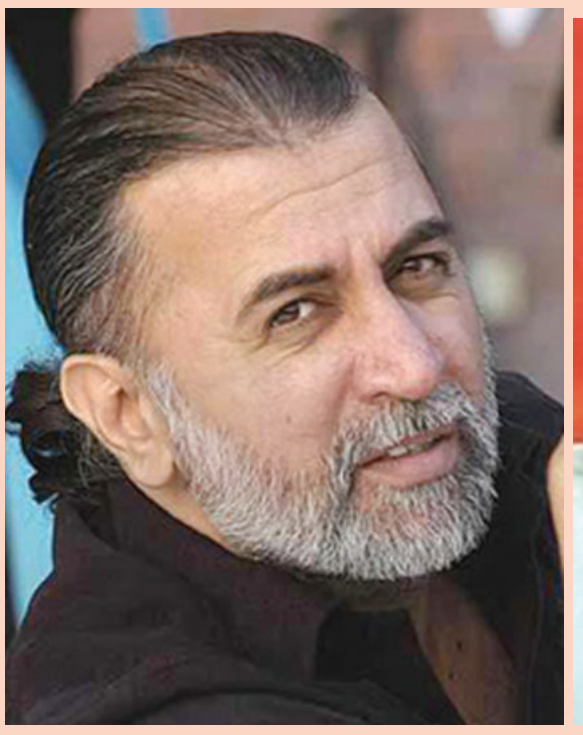

तहलका नवीन भारतीय मीडिया का हिस्सा है और इसे लोकतंत्र में जगह भी दी गई. लेकिन गुजरात सरकार और भाजपा ने क्या किया. अगर हमलोग साहिब टेप्स पर भरोसा भी करें, हालांकि अभी इसकी प्रमाणिकता सिद्ध होनी बाकी है, तो यह एक और मामला है, जहां एक महिला का पीछा किया गया और जासूसी की गई. भाजपा के अनुसार, ऐसा उस लड़की के पिता के आग्रह के बाद किया गया. भाजपा की कहानी के अनुसार, उस लड़की के पिता ने गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आग्रह किया था कि लड़की पर निगाह रखी जाए. ऐसा कहा जाता है कि वह संघ का आदमी है. इस वजह से शायद उसके सीधे व्यक्तिगत संबंध सीएम से रहे होंगे. उस लड़की के पिता के अनुसार, वह ऐसे काम कर रही थी जिसकी इजाजत उन्होंने उसे नहीं दी थी.

यह मामला ग़ैरक़ानूनी ज्यादा है और इसमें शारीरिक प्रताड़ना कम है, लेकिन यह किसी भी रूप से कम गंभीर नहीं है. यह मामला वह क़ानूनी आधार है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति पर सर्विलांस लगाया जाता है. भारत में इसके नियमों को लचीला बनाकर गुपचुप तरीक़े से इसकी शक्ति का प्रयोग किया जाता है. हम इसे सीबीआई के क्रियाकलापों के ज़रिये देख सकते हैं कि कैसे वह नेताओं के ख़िलाफ़ के केस दायर करती है और फिर पीछे हट जाती है. बड़ा कार्य यह है कि ऐसी घटना पर निगाह रखा जाना, जो इसे गड़बड़ बनाता है और ऐसा सोचना कि सर्विलांस अकेला पूरे भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकता है, यह शक्ति का दुरुपयोग है. साधारणतया इसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारी बच जाते हैं, लेकिन अगर मामला खुलता है तो उनकी भी जांच की जानी चाहिए. शक्ति का दुरुपयोग नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए धन के घोटालों से ज्यादा भयावह हैं.

अगर भारत को प्रगति करनी है, तो उसे अपने सम्मान देने के तर्कों को उलटना होगा. अब सिर्फ़ नेता, उम्रदराज़ व्यक्तियों और पिताओं को ही नहीं, बल्कि भारत के नौजवान युवक और महिलाओं को इज़्ज़त दी जानी चाहिए, जो भविष्य में भारत की ज़िम्मेदारी संभालने वाले हैं. विशेष रूप से उन्हें अपने से बड़े और पिताओं के द्वारा सम्मान दिया जाना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार का पेंच

चौथी दुनिया ब्यूरो

अभी तक हमने आपको तीसरे पक्ष और न्यायालय की अवमानना के बारे में बताया कि कैसे इन शब्दों का ग़लत इस्तेमाल करके लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर देते हैं. इस अंक में हम आपको ऐसे ही एक और शब्द से परिचित करा रहे हैं. इस बार हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में. कैसे और कब फंसता है संसदीय विशेषाधिकार का पेंच. सबसे पहले एक उदाहरण से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं. अमेरिका से एटमी डील के दौरान यूपीए सरकार को जब सदन में विश्वास मत हासिल करना था, उसके कुछ घंटे पहले सदन में भारत के संसदीय इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना घटित हुई. भाजपा के तीन सांसदों ने सदन में नोटों की गड्डियां लहराते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि यह नोट उन्हें सरकार के पक्ष में विश्वास मत के दौरान वोट देने के लिए घूस के रूप में मिले हैं, जिसे एक मीडिया चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अपने कैमरे में कैद कर लिया था और उसे लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को सौंप दिया था.

बाद में कुछ ग़ैर सरकारी संगठनों और लोगों ने जब सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करके वीडियो टेप सार्वजनिक करने की मांग की तो लोकसभा ने उन टेप को सार्वजनिक करने से मना कर दिया. लोकसभा ने बताया कि वीडियो टेप अभी संसदीय समिति के पास है और जांच की प्रक्रिया चल रही है. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस सूचना के सार्वजनिक करने से धारा 8 (1) (सी) का उल्लंघन होता है. इस धारा में बताया गया है कि ऐसी सूचना, जिसके सार्वजनिक किए जाने से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है, उसे सूचना के अधिकार के तहत दिए जाने से रोका जा सकता है.

ऐसा ही एक मामला और है, जिसमें वर्तमान केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासनिक विभाग से मुख्यमंत्री राहत कोष में मुंबई ट्रेन धमाकों के बाद प्राप्त अनुदानों के ख़र्चों का ब्यौरा मांगा था. उन्हें यह कह कर सूचना देने से मना कर दिया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष एक निजी ट्रस्ट है और सूचना क़ानून के दायरे में नहीं आता, जबकि शैलेश का मानना था कि राहत कोष एक पब्लिक बॉडी है और आयकर छूट का लाभ उठाती है. मुख्यमंत्री जनता का सेवक होता है, इसलिए इस सूचना के सार्वजनिक होने से विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन नहीं

होता है. एक मासिक पत्रिका से जुड़े रमेश तिवारी ने उत्तर प्रदेश के स्पीकर और स्टेट असेंबली के साचिव के पास एक आवेदन किया था. आवेदन के माध्यम से यह जानना चाहा था कि क्या कोई लेजिसलेटर अपने आप से कोई सरकारी ठेका ले सकता है और यदि ऐसा ठेका लिया गया है तो क्या ऐसे सदस्य की असेंबली से सदस्यता रद्द की जा सकती है?

असेंबली से रमेश को जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह मामले को उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष ले गए. आयोग के तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त एम ए ख़ान ने स्पीकर और सचिव को सूचना के अधिकार क़ानून के तहत नोटिस जारी कर दिया. नोटिस पाते ही सबसे पहले तो रमेश का

आवेदन ख़ारिज़ कर दिया गया और उसके बाद असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसके माध्यम से सूचना आयोग को चेतावनी दी गई कि आयोग का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और इस तरह की सूचना मांगे जाने से और आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने से विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है. आयोग को आगे से ऐसे मामलों में सावधान रहने की चेतावनी दी गई.

राहुल विभूषण ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और तीन सांसदों के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि मांगी थी. दरअसल, एक पेट्रोल पंप को अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करने के कारण बंद कर दिया गया था. इस पेट्रोल पंप को दोबारा खुलवाने के लिए तीन सांसदों ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा था. राहुल ने इस पत्र के जवाब की प्रतिलिपि मांगी थी, जिसे यह कहकर देने से मना कर दिया गया कि इसे दिए जाने से संसद के विशेषाधिकारों को हनन होता है. आयोग में सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त ने माना कि सांसद द्वारा लिखे गए पत्र का संसद या संसदीय कार्रवाई से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और इस सूचना के सार्वजनिक किए जाने से संसद के किसी विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं होता है. आयुक्त ने मांगी गई सूचना को 15 दिनों के भीतर आवेदक को सौंपे जाने का आदेश दिया. कुल मिलाकर देखें तो ज़्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकार की आड़ में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ा नहीं होता है. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

शादी करने के लिए लड़की ने देश छोड़ा

प्यार को कैद नहीं किया जा सकता. सउदी अरब में एक घटना से यह बात सिद्ध होती दिखाई दी. महिलाओं को कम अधिकार देने वाले सउदी अरब में एक युवती यमन में रह रहे अपने प्रेमी से निकाह करने के चक्कर में जेल पहुंच गई और अब उसने अदालत से मदद की गुहार लगाई है. 22 साल की हुडा अल निरान ने देश के दकियानूसी कानून और उसके अंजाम की परवाह किए बगैर देश से फरार होकर सना में शरण ली है. वह अपने प्रेमी अराफात मोहम्मद ताहर से निकाह करने के लिए अदालत की मदद ले रही है. दोनों देशों के लोग इस युवती के साहस को देखकर हैरान हैं. हुडा इस वक्त जेल में है और उस पर देश में अवैध तरीके से घुसने पर मामला चल रहा है. दोषी पाए जाने पर हुडा को सउदी वापस भेजा जा सकता है. हुडा ने यमन की अदालत में गुहार लगाई है

कि उसे वहां रहने दिया जाए और ताहर से निकाह की अनुमति भी दी जाए. अदालत में उसने सउदी अरब दूतावास की ओर से मुहैया कराए गए वकील की मदद लेने से भी इन्कार कर दिया. उसे डर है कि उस पर सउदी वापस लौटने का दबाव डाला जा सकता है. उधर, मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वाच भी इस मामले पर लगातार निगाह रखे हुए है. संगठन ने 19 नवंबर को यमन से अपील की थी कि हुडा को वापस सउदी नहीं भेजा जाए, क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा हो सकता है. गौरतलब है कि सउदी अरब और यमन दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, जहां महिलाओं के पास कुछ ही अधिकार हैं और वहां महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं. ■

जब कब्र से निकला ज़िंदा इंसान

कहा जाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है. मरता तो सिर्फ शरीर है. जब कोई आत्मा इस संसार में अपना जिस्म छोड़ती है, तो उसे मरा हुआ ही समझा जाता है, क्योंकि जिस तरह जीवन एक सच्चाई है, उसी तरह मौत भी एक अटल सत्य है. इस सत्य को प्रत्येक मनुष्य मानता है. ब्राजील में एक औरत अपने किसी रिश्तेदार की कब्र पर फूल चढ़ाने गई तो उसने एक कब्र में अजीबोगरीब हलचलें महसूस किया. उसे ये महसूस हुआ कि किसी कब्र से धीमे-धीमे कोई आवाज आ रही है. कोई बहुत बैचेन है और बाहर आने की कोशिश कर रहा है. इतना ही नहीं, जब उसने देखा कि कब्र में से एक हाथ बाहर आ रहा है, तो वह काफी डर गई और वहां से भाग गई, लेकिन फिर उसे लगा कि हो सकता है कि किसी को उसकी मदद की जरूरत हो. जब वो हिम्मत करके वापस वहां गई, तब उसने देखा कि सच में उस कब्र में से किसी आदमी की आवाज आ रही है. यह सब देखने के बाद उसने कब्रिस्तान के कार्यालय में जाकर इसके बारे में बताया. पहले तो वहां

के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उस औरत के काफी आग्रह पर कर्मचारियों ने जब वहां जा कर देखा, तो सच में एक आदमी कब्र से बाहर हाथ निकाल कर मदद मांग रहा था. वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला. तब पता चला कि वह कोई मृत व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवित व्यक्ति है. उसे वहां से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया. होश आने पर उसने सारी बात बताई, तो सभी हैरान रह गए. उसने बताया कि कुछ मनचले लड़कों ने उसके सामान को छीनने की कोशिश की थी. जब वह इसका विरोध करने लगा, तब उन लोगों ने उसके सिर पर वार किया और वह बेहोश हो गया. वे लोग उसे मरा हुआ समझ कर टूटी-फूटी कब्र में दफना गए होंगे, क्योंकि आगे की कहानी उस व्यक्ति को याद नहीं थी. जब उसे होश आया, तो उसने खुद को कब्र में पाया और फिर वहां से निकलने के लिए मदद मांगने लगा. सौभाग्यवश उसी वक्त एक औरत की नजर उस पर पड़ी और एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया ■

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
संतान संबंधी तनाव हो सकता है. तनाव से बचें. किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होंगे. नौकरी में स्थानान्तरण से सम्बंधित सूचना मिलेगी. क्रोध से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. इस सप्ताह खर्च पर नियंत्रण रखें. कोई भी कार्य करने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद लें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
यात्रा पर जाने से बचें. विदेश से शुभ समाचार मिलेगा. इस सप्ताह संपत्ति खरीदने की योजना बनाएंगे, जिसमें आप सफल होंगे. आप कटु सत्य बोलने से बचें. पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा. विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह बनते कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है. आप व्यक्तिगत संबंधों में तनाव महसूस करेंगे और जीवन में उत्साह की कमी रहेगी. स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. वाहन से संबंधित खर्च होगा. व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करेंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
पैतृक संपत्ति से सम्बंधित अच्छी खबर मिलेगी. आपको मिश्रित फल प्राप्त होगा और आप उत्साहित रहेंगे. व्यवसायी कानूनी मामलों से बचें. विद्यार्थी अपनी शिक्षा के लिए प्रयासरत रहेंगे और सफल होंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
कोई भी लेन-देन सावधानी से करें, अन्यथा धोखे का शिकार हो सकते हैं. आप नये कार्यों के संपन्न होने से प्रसन्न रहेंगे. इस सप्ताह व्यापारी वर्ग और नौकरीपेशा दोनों आमतौर पर प्रसन्न रहेंगे. शत्रु हावी रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. किसी के दबाव में आकर कोई कार्य न करें.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह पारिवारिक रूप से आप उत्साह में रहेंगे और सामूहिक कार्यक्रम की योजना भी बनेगी. इस सप्ताह आपके संघर्ष में कमी होगी और आप आगे के लिए अग्रसर रहेंगे. व्यर्थ के खर्च से बचें. कोई स्थायी संपत्ति के क्रय से सम्बंधित बात होगी और आप उसमें सफल रहेंगे. संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आप कोई भी जोखिम उठाने से बचें. इस सप्ताह लंबित कार्य संपन्न करने में आप सफल होंगे. किसी भी जमीन-जायदाद से सम्बंधित मामलो में बचें, अन्यथा तनाव हो सकता है. आप किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
आप अपनी छवि को सुधारने के लिए अधिक प्रयास न करें और इसकी चिंता छोड़ दें कि लोग क्या बोलते हैं. किसी नये स्थान पर आप पूंजी का निवेश करें. भावुक होकर कोई भी निर्णय लेने से बचें. इस सप्ताह नई योजनाओं और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
भावना और धन में आप भावना को ज्यादा महत्व देंगे. आप चिड़चिड़ेपन से बचें. इस सप्ताह अधिक ज्ञान अर्जित करें, बजाय इसके कि आप अपनी अभिव्यक्ति पेश करें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. कर्ज देने से बचें. इस सप्ताह परिवार के साथ समय व्यतीत करें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
शत्रुओं से बचें, क्योंकि वह पुराने मामले उठा सकते हैं. यह सप्ताह आपके लिए परिवर्तन वाला रहेगा. नौकरीपेशा वाले लोग चिंतित रहेंगे और व्यापारी फायदे के लिए भ्रमण करेंगे. विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि घटेगी. बड़ा निवेश करने से बचें. स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
परिवार से तालमेल बनाकर चलें. किसी विषय-वस्तु के बारे में सोचकर आप भय महसूस करेंगे. कोई मित्र आपके नुकसान का कारण होगा. इस सप्ताह धर्म कार्यों में रुचि बढ़ेगी. व्यापारी व्यवसाय के लिए नई संपत्ति खरीदेंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
आर्थिक रूप से आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन आर्थिक लेन-देन करते समय सावधानी बरतें. आप अपने साथ कार्यरत लोगों से सावधान रहें. कोई कर्मचारी आपकी शिकायत अधिकारी से कर सकता है. इस सप्ताह पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको अच्छी खबर प्राप्त होगी.

वापस मिली 50 साल पहले गायब हुई बाइक

अमेरिका में एक व्यक्ति की खुशी का उस समय कोई ठिकाना नहीं रहा, जब 50 साल पहले चोरी हुई उसकी बाइक उसे वापस मिल गई. अब इस बाइक की कीमत बाजार में तीस गुना बढ़ गई है. यह मामला सामने आया है अमेरिका के मध्य पश्चिमी प्रांत नेब्रास्का में, जहां ओमाहा शहर

में रहने वाले व्यक्ति डोनाल्ड डीवाल्ट को अपनी 50 साल पहले चोरी हुई बाइक वापस मिल गई. कैलिफोर्निया प्रशासन ने उसकी बाइक को लॉस एंजलिस के बंदरगाह से बरामद किया. प्रशासन ने बताया कि बाइक को जापान भेजने की तैयारी जा रही थी, लेकिन अधिकारियों ने समय रहते पता लगा लिया. इस बाइक की चोरी की रिपोर्ट फरवरी 1967 में दर्ज की गई थी. 1967 में इस बाइक की कीमत 300 डॉलर थी, जो अब बढ़कर नौ हजार डॉलर हो चुकी है. डीवाल्ट के पास इसके अलावा हार्ले डेविडसन और काव-ासाकी की बाइक भी हैं. ■

> सउदी अरब की यह आशंका किसी हद तक सही भी हो सकती है, क्योंकि रेज़ा शाह पहलवी के कार्यकाल में अमेरिका सउदी अरब के बजाए ईरान से अधिक नज़दीक था, लेकिन इसके बाद ईरान में कट्टर इस्लाम को मानने वालों के हावी होने से अमेरिका धीरे–धीरे ईरान से दूर और सउदी अरब से क़रीब होता गया.

परमाणु ऊर्जा समझौता

भारत कितना लाभान्वित

अमेरिका के साथ मिलकर ईरान ने अन्य राष्ट्रों के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता किया है. इस समझौते से विश्व के देशों को मंदी की मार से उबरने में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी. इस समझौते से भारत जैसे देश को भी प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा होता दिख रहा है. भारत ने इस समझौते का स्वागत भी किया है. हालांकि विश्व के कुछ देश समझौते का विरोध भी कर रहे हैं. अब यह देखने वाली बात होगी कि इस समझौते के क्या दूरगामी परिणाम होंगे.

वसीम अहमद

अमेरिका के नेतृत्व में विश्व के छह शक्तिशाली देशों के साथ ईरान ने परमाणु ऊर्जा समझौता किया है. ऐसा कर वह अपने आर्थिक संकट को समाप्त करने के लिए एक सकारात्मक क़दम उठाया है. इस समझौते के महत्वपूर्ण बिंदुओं में ईरान को मध्यम औसत के 20 प्रतिशत यूरेनियम संवर्धन की अनुमति प्राप्त होगी, लेकिन वह इससे परमाणु हथियार नहीं बना सकेगा. इसके अलावा ईरान ने जो अधिक संवर्धन किया है, वह इसे रोक देगा और विश्व संस्थानों को निरीक्षण करने में सहयोग करेगा. इस समझौते का पूरे विश्व में स्वागत किया जा रहा है. भारत जैसे मित्र देश से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, जिसका ईरान के साथ तीन द्वीपों अबु मूसा, तनब कुब्रा एवं तनब सुग्रा पर वर्षों से मतभेद जारी है, ने भी इसका स्वागत किया है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं, जो इस समझौते से ख़ुश नहीं हैं. इनमें से एक इजराइल है, जो किसी न किसी बहाने ईरान पर हमले का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन इस समझौते ने इसके इरादों को नाकाम बना दिया. यही कारण है कि इजराइली प्रधानमंत्री बेनजामिन नेतनयाहू इस समझौते से न केवल नाख़ुश हैं, बल्कि उन्होंने इस समझौते को ऐतिहासिक भूल बताते हुए कहा है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक राष्ट्र दुनिया के सबसे घातक हथियार की प्राप्ति की ओर महत्वपूर्ण क़दम उठाने में सफल हो गया है. साथ ही उन्होंने यह भी साफ़ कर दिया है कि इजराइल इस समझौते पर प्रतिबद्ध नहीं है.

सउदी अरब का रुख सकारात्मक नहीं

सउदी अरब की ओर से जो बयान आ रहा है, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वह इस समझौते को सकारात्क दृष्टि से नहीं देख रहा है. सउदी अरब के विदेशी मामलों के सलाहकार का कहना है कि इस समझौते से ईरान को खाड़ी क्षेत्रों में खुला रास्ता मिल जाएगा. दरअसल, ईरान में 1979 की क्रांति के बाद इजराइल व अन्य अरब राष्ट्र (जहां बादशाहत है) ईरान को अपने लिए बड़ा ख़तरा मानते हैं. इजराइल का आरोप है कि ईरान इजराइल विरोधी संगठनों को आर्थिक सहायता और आधुनिक हथियार उपलब्ध कराता है, जिनमें सबसे ताक़तवर लेबनान का संगठन हिज़्बुल्ला है, जबकि सउदी अरब का आरोप है कि ईरान सुन्नी राष्ट्रों में अप्रभावी शिया बिरादरियों का समर्थन करता है, ताकि बहुल राष्ट्रों को नुक़सान पहुंचाया जा सके. सउदी अरब का कहना है कि ईरान के पास जितने परमाणु प्रतिष्ठान उपलब्ध हैं, उनकी मदद से भविष्य में वह परमाणु बम तैयार कर सकता है. इस समझौते के बाद ईरान को सुन्नी देशों में अपना प्रभुत्व जमाने का एक और मौक़ा मिलेगा, लेकिन क्या सउदी अरब की यह आशंका उचित है? क्या वास्तव में ईरान इस समझौते के बाद अरब देशों में अपनी गतिविधियां बढ़ा पाएगा? अगर परिस्थितियों का जायज़ा लिया जाए, तो अनुमान होता है कि सउदी अरब की आपत्ति का कारण यह समझौता नहीं, बल्कि खाड़ी क्षेत्रों में ईरान का बढ़ता प्रभाव है. ईरान के साथ वर्षों तक युद्ध की स्थिति में रहने वाले इराक की नीति 2003 के बाद बदल गई है और वह एक दुश्मन से मित्र देश बन गया है. हालांकि 2011 में मिस्र में सउदी अरब विरोधी सरकार बनी, लेकिन शीघ्र ही इसका अंत हो गया. इस प्रकार अरब क्षेत्रों में एक ओर ईरान के मित्र देशों की बढ़ती हुई संख्या और दूसरी ओर ईरान की ओर अमेरिकी झुकाव ने सउदी अरब को चिंता में डाल दिया है.

अमेरिका की सउदी अरब से दूरियां

अमेरिका सउदी अरब से दूर होता जा रहा है. अभी हाल ही में सउदी अरब ने ईरान के एक गहरे मित्र देश सीरिया पर मिसाइल से हमला करने पर दबाव डाला था. सउदी अरब ने युद्ध के सभी ख़र्चे उठाने का भी संकेत दिया था, लेकिन अमेरिका ने अचानक हमले से इन्कार करके सउदी अरब को निराश कर दिया. इधर, सउदी अरब ईरान पर परमाणु ऊर्जा को लेकर आर्थिक प्रतिबंध में अधिक सख़्ती की आशा कर रहा था, लेकिन पश्चिमी देशों ने इस पर प्रतिबंध हटाने का रास्ता साफ कर दिया है.

वैसे, सउदी अरब की यह आशंका किसी हद तक सही भी हो सकती है, क्योंकि रेज़ा शाह पहलवी के कार्यकाल में अमेरिका सउदी अरब के बजाए ईरान से अधिक नज़दीक था, लेकिन इसके बाद ईरान में कट्टर इस्लाम को मानने वालों के हावी होने से अमरीका धीरे–धीरे ईरान से दूर और सउदी अरब से क़रीब होता गया. अहमदीनेज़ाद के दौर में यह दूरी आगे बढ़ी, लेकिन इनके बाद जब हसन रूहानी राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उदारवाद का रास्ता अपनाया. उनके इसी उदारवाद की ओर इशारा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी कह चुके हैं कि उनके राष्ट्रपति बनने के कारण ही यह समझौता संभव हो सका है. ज़ाहिर है, अगर हसन रुहानी कट्टर इस्लामवाद के बजाए उदारवाद को अपनाते हैं, तो रेज़ा शाह पहलवी की तरह अमेरिका का झुकाव ईरान की ओर ही रहेगा और ऐसी स्थिति में ईरान और सीरिया खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका से गठबंधन करके सुन्नी अरब राष्ट्रों के लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं. ये ही वे कारण हैं, जिससे सउदी अरब नहीं चाहता है कि ईरान पर अमेरिका की नकेल ढीली पड़े एवं इन दोनों राष्ट्रों के संबंध मधुर हों.

अधिकांश राष्ट्र समझौते के पक्ष में

कुछ राष्ट्रों के अलावा सभी राष्ट्र इस समझौते को सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं. इस समझौते के बाद ईरान को आर्थिक संकट से बाहर निकलने का मौक़ा मिलेगा. यह प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र की ओर से 2006 में लगाया गया था. यूं तो अमेरिका व ईरान के व्यापारिक संबंध 1995 से ही बंद थे, लेकिन 2006 के बाद इस पाबंदी में सख़्ती बढ़ती गई और 2007 में परमाणु ऊर्जा पर प्रतिबंध के अलावा ईरानी बैंक के साथ लेन–देन पर भी पाबंदी लगा दी गई थी. 2008 में इसमें और तेज़ी आ गई और ईरान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को विदेश यात्रा करने पर रोक लगा दी गई. इसके बाद 2009 और 2010 में भी पाबंदियों में अधिक सख़्ती की घोषणा की गई. इधर कुछ दिनों से आर्थिक पाबंदी में अधिक सख़्ती लाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस मामले में रुचि दिखाई और ईरान को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वह अपनी परमाणु ऊर्जा के संवर्धन को सीमित रखे. बदले में ईरान के सिविल प्रयोग के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए मरम्मत और इसके निरीक्षण और तेल के विक्रय की राशि में लगभग 4.2 अरब अमेरिकी डॉलर रिलीज़ करने, ईरान के लगभग 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि दूसरे देशों में शिक्षण संस्थानों को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जाएगी.

भारत की कूटनीति

भारत शुरू से ही ईरान की पाबंदी को लेकर अमेरिका से सीधे बात करने की ओर ध्यान दिलाता रहा है. लिहाज़ा, पिछले साल गुट निरपेक्ष आन्दोलन (एनएएम) के अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तेहरान में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई से भेंट के दौरान अमेरिका से सीधे बात करने की सलाह दी थी, लेकिन तब यह ईरान की कड़ी नीतियों के कारण संभव नहीं हो सका. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान चाहता, तो बातचीत के द्वारा बहुत पहले ही इस समस्या को हल कर सकता था, लेकिन ये चीज़ें नई सरकार के आने के बाद ही संभव हो सकीं. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि इस समझौते के बाद आगे की बातचीत के रास्ते प्रशस्त होंगे. इस समझौते से भारत इसलिए भी ख़ुश है, क्योंकि दोनों देशों के स्थिर व्यापारिक संबंध हैं. लंबे समय तक भारत ईरान के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा क्रेता रहा है. हालांकि पश्चिमी राष्ट्रों की ओर से प्रतिबंध के बाद क्रय में कमी आई थी, फिर भी 2011–12 में भारत ने ईरान से 14.689 मिलियन टन तेल क्रय किया था. हालांकि पश्चिमी राष्ट्रों ने भारत को ईरान से संबंध ख़त्म करने और तेल न ख़रीदने पर बहुत दबाव डाला था, लेकिन भारत ने ईरान के साथ पुराने रिश्ते की ख़ातिर पश्चिमी दबाव को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था और अब, जबकि 6 देशों के साथ ईरानी समझौते के बाद पांबदी हटने की संभावनाएं पैदा हो गई हैं, तो उम्मीद है कि भारत एक बार फिर ईरानी तेल का बड़ा ख़रीदार बन जाएगा. इस समझौते के कारण भारत को सस्ता तेल मिलने की आशाएं बढ़ गई हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, अगर भारत ईरान से अतिरिक्त 11 मिलियन टन कच्चा तेल क्रय करता है तो 531 अरब रुपये की बचत होगी. इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा और पेट्रोल व डीज़ल के मूल्यों में बार–बार होने वाली वृद्धि पर रोक भी लग पाएगी. इस समझौते से भारत को यह फ़ायदा होगा कि तेल क्रय का भुगतान भारत डॉलर में कर रहा था, लेकिन ईरानी बैंकों पर पाबंदी के कारण भारत के लगभग 5.3 अरब रुपये की राशि रुक गई थी. नये समझौते के बाद ईरान आसानी से डॉलर में राशि वसूल कर सकता है. इसके अलावा भारत–ईरान पाइप लाइन पर भी तेज़ी से काम होने की उम्मीद है. अगर यह उम्मीद पूरी हो जाती है और पाइप लाइन का काम चल पड़ता है तो भारत में गैस आपूर्ति की लागत में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है. इसके अलावा अन्य कई प्रयोग की चीज़ें जैसे चाय पत्ती, ऑटो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, पुर्जे और कृषि पैदावार में उच्च स्तर पर व्यापार होने के अलावा क्षेत्रीय ट्रांस्पोर्ट नेटवर्क और क्षेत्रीय सिक्योरिटी पर भी दोनों देशों के बीच काम हुआ है और अब इनमें तेज़ी आने की संभावना भी प्रबल हुई है.

बहरहाल, ईरान को 6 महीने का समय दिया गया है. इस दौरान ईरान को समझौते की सभी शर्तों को अमल में लाना होगा. विशेषत: ईरान को अपनी परमाणु योजना के समझौते के अनुसार सीमित करना होगा, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ईरान अपनी ऊर्जा योजना को कम करेगा. अगर वह इसमें सफल नहीं हो सका, तो अमेरिका ने साफ़ कर दिया है कि सभी पाबंदियां पुन: लगाई जा सकती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई

अब एक क्षण साईबाबा की जीवनी का भी अवलोकन करें. साईबाबा के निवास से ही शिरडी तीर्थस्थल बन गया है. सभी जगहों के लोग वहां जाने लगे हैं तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंच रहा है. बाबा के असीम प्रेम, उनके अद्भुत ज्ञानभंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है. धन्य तो वही है, जिसे कुछ अनुभव हो चुका है. वे आनन्दमूर्ति बन भक्तों से घिरे हुए रहते थे.

एक बार...

सर्वशक्तिमान साई

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई की प्रकृति अगाध है, जिसका वर्णन करने में वेद और सहस्त्रमुखी शेषनाग भी अपने को असमर्थ पाते हैं. भक्तों की स्वरुप वर्णन में रुचि नहीं, उनकी तो दृढ़ धारणा है कि आनन्द की प्राप्ति केवल साई के चरणों में ही संभव है. साई के चरणकमलों के ध्यान के अतिरिक्त, उनके भक्तों को अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का अन्य मार्ग विदित ही नहीं. कृष्ण पक्ष के आरम्भ होने पर चन्द्र–कलाएं दिन–प्रतिदिन घटती चलती है तथा उनका प्रकाश भी क्रमशः क्षीण होता जाता है और अन्त में अमावस्या के दिन चन्द्रमा के पूर्ण विलीन रहने पर चारों ओर निशा का भयंकर अंधेरा छा जाता है. जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है, तो लोग चन्द्र–दर्शन के लिए अति उत्सुक हो जाते हैं. इसके बाद द्वितीया को जब चन्द्र अधिक स्पष्ट गोचर नहीं होता, तब लोगों को वृक्ष की दो शाखाओं के बीच से चन्द्रदर्शन के लिए कहा जाता है और जब इन शाखाओं के बीच उत्सुकता और ध्यानपूर्वक देखने का प्रयत्न किया जाता है, तो दूर क्षितिज पर छोटी–सी चन्द्ररेखा के दृष्टिगोचर होते ही मन अति प्रफुल्लित हो जाता है. इसी सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए हमें बाबा के दर्शन का भी प्रयत्न करना चाहिए. बाबा के चित्र की ओर देखो कितना सुन्दर है. वे पैर मोड़ कर बैठे हैं और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा गया है. बाएं हाथ की अंगुलियां दाहिने चरण पर फैली हुईं हैं. दाहिने पैर के अंगूठे पर तर्जनी और मध्यमा अंगुलियां फैली हुईं हैं. इस आकृति से बाबा समझा रहे है कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो, तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर उक्त दो अंगुलियों के बीच से मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो. तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो सकोगे. भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सुगम मार्ग है.

अब एक क्षण साई बाबा की जीवनी का भी अवलोकन करें. साईबाबा के निवास से ही शिरडी तीर्थस्थल बन गया है. सभी जगहों के लोग वहां जाने लगे हैं तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंच रहा है. बाबा के असीम प्रेम, उनके अद्भुत ज्ञानभंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है. धन्य तो वही है, जिसे कुछ अनुभव हो चुका है. वे आनन्द मूर्ति बन भक्तों से घिरे हुए रहते थे. कभी सरल चित्त रहते. कभी संक्षिप्त और कभी घंटो प्रवचन किया करते थे. लोगों की आवश्यकतानुसार ही भिन्न–भिन्न प्रकार के उपदेश देते थे. उनके मुखमंडल के अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छाएं सदा अतृप्त ही बनी रहीं. बाबा की लीलाओं का कोई भी अंत न पा सका. उन्हीं लीलाओं में से एक लीला के बारें में वर्णन कर रहा हूं. भक्तों के संकटों के घटित होने के पूर्व ही बाबा उपयुक्त अवसर पर किस प्रकार उनकी रक्षा किया करते थे. बालासाहेब मिरीकर, जो सरदार काकासाहेब के सुपुत्र थे, एक बार दौरे पर चितली जा रहे थे. तभी मार्ग में, वे साईबाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे. उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा की चरण–वन्दना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर चर्चा की. बाबा ने उन्हें चेतावनी देकर कहा कि क्या तुम अपनी द्वारकामाई को जानते हो. बालासाहेब इसका कुछ अर्थ न समझ सके, इसलिए वे चुप रहे. बाबा ने उनसे पुनः कहा कि जहां तुम बैठे हो, वही द्वारकामाई हैं. जो उसकी गोद में बैठता है, वह अपने बच्चों के समस्त दुःखों और कठिनाइयों को दूर कर देती हैं. यह मस्जिद माई परम दयालु हैं. सरल हृदय भक्तों की तो वह मां हैं और संकटों में उनकी रक्षा अवश्य करेंगी. जो उसकी गोद में एक बार बैठता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं. जो उसकी छत्रछाया में विश्राम करता है, उसे आनन्द और सुख की प्राप्ति होती है. उसके बाद बाबा ने उन्हें उदी देकर अपना हाथ उनके मस्तक पर रख आशीर्वाद दिया.

बालासाहेब ने पुनः विचार कर शामा को अपने साथ चलने के लिए कहा. तब शामा पुनः बाबा की आज्ञा प्राप्त कर बालासाहेब के साथ तांगे में रवाना हो गए. वे नौ बजे चितली पहुंचे और हनुमान मंदिर में जाकर ठहरे. आफिस के कर्मचारी अभी नहीं आए थे, इस कारण वे यहां–वहां की चर्चाएं करने लगे. बालासाहेब दैनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शांतिपूर्वक बैठे थे. उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर पर पड़ा हुआ था और उसी के एक भाग पर एक सर्प बैठा हुआ था. किसी का भी ध्यान उधर न था. वह सी–सी करता हुआ आगे रेंगने लगा. यह आवाज सुनकर चपरासी दौड़ा और लालटेन ले आया.

बालासाहेब जाने के लिए उठ खड़े हुए, तो बाबा बोले कि क्या तुम लम्बे बाबा (अर्थात सर्प) से परिचित हो. अपनी बाईं मुट्ठी बन्दकर उसे दाहिने हाथ की कुहनी के पास ले जाकर दाहिने हाथ को सांप के सदृश हिलाकर बोले कि वह अति भयंकर है, परन्तु द्वारकामाई के लालों का वह कुछ नहीं कर सकता है. जब स्वंय ही द्वारकामाई उनकी रक्षा करने वाली हैं तो सर्प की सामर्थ्य ही क्या है. बाबा ने शामा को बुलाया और बालासाहेब के साथ जाकर चितली यात्रा का आनन्द लेने की आज्ञा दी. तब शामा ने जाकर बाबा का आदेश बालासाहेब को सुनाया. वे बोले कि मार्ग में असुविधाएं बहुत हैं, अतः आपको व्यर्थ ही कष्ट उठाना उचित नहीं है. बालासाहेब ने जो कुछ कहा, वह शामा ने बाबा को बताया. बाबा बोले कि अच्छा ठीक है, न जाओ. सदैव उचित अर्थ ग्रहणकर श्रेष्ठ कार्य ही करना चाहिए. जो कुछ होने वाला है, सो तो होकर ही रहेगा.

बालासाहेब ने पुनः विचार कर शामा को अपने साथ चलने के लिए कहा. तब शामा पुनः बाबा की आज्ञा प्राप्त कर बालासाहेब के साथ तांगे में रवाना हो गए. वे नौ बजे चितली पहुंचे और हनुमान मंदिर में जाकर ठहरे. आफिस के कर्मचारी अभी नहीं आए थे, इस कारण वे यहां–वहां की चर्चाएं करने लगे. बालासाहेब दैनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शांतिपूर्वक बैठे थे. उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर पर पड़ा हुआ था और उसी के एक भाग पर एक सर्प बैठा हुआ था. किसी का भी ध्यान उधर न था. वह सी–सी करता हुआ आगे रेंगने लगा. यह आवाज सुनकर चपरासी दौड़ा और लालटेन ले आया. सर्प को देखकर वह सांप–सांप कहकर उच्च स्वर में चिल्लाने लगा. तब बालासाहेब अति भयभीत होकर कांपने लगे. शामा को भी आश्चर्य हुआ. तब वे तथा अन्य व्यक्ति वहां से धीरे–से हटे और अपने हाथ में लाठियां ले लीं. सर्प धीरे–धीरे कमर से नीचे उतर आया. तब लोगों ने उसका तत्काल ही प्राणांत कर दिया. जिस संकट की बाबा ने भविष्यवाणी की थी, वह टल गया और साई–चरणों में बालासाहेब का प्रेम दृढ़ हो गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

सबसे सरल परमेश्वर का नाम

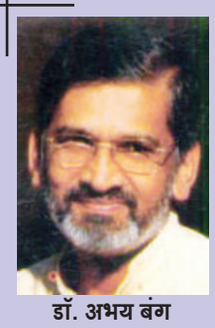

डॉ. अभय बंग

ध्यान–मार्ग से ईश्वर–दर्शन के लिए प्रयत्न करते हुए अपने ही मन की अनिवार्य अनियन्त्रित हलचल देखकर और उसे शान्त करने का प्रयत्न करते–करते आज मैं थक गया. यह सब अपने बस की बात नहीं, ऐसा लगा. योग व ध्यान से शरीर निरोगी रहता है, मन प्रसन्न व सहज होता है, तनाव रहित होता है, जीवन सुंदर लगने लगता है, बोझ हट जाता है–यह काफी बड़ी उपलब्धि है. लेकिन ईश्वर–दर्शन वगैरह तो इससे कुछ होता नहीं, कम–से–कम मुझे तो नहीं हुआ. यह रास्ता छोड़कर दूसरा अपना लिया जाए. भक्तिमार्ग से ही कुछ घटित होगा. एक दिन थक कर मैंने सोचा.

आठ–दस दिन ये विचार घुमड़ते रहे. फिर भी मैं ध्यान का अभ्यास तो करता ही रहा. एक दिन अचानक ध्यान का एक नया अर्थ समझ में आया. ध्यान की विविध पद्धतियों से अपनी विविध ज्ञानेन्द्रियां संवेदनक्षम होती हैं एवं उनसे संबंधित संवेदनाएं शुद्ध होती हैं. दृष्टि–ध्यान करने से दृष्टि साफ हो जाती है. त्वचा की संवेदना पर लक्ष्य केंद्रित करने वाला ध्यान विपश्यना करने से स्पर्श संवेदना तीव्र व स्वच्छ होती है. तीव्र होती है, यह तो ठीक है, लेकिन स्वच्छ कैसे होती है? इन संवेदनाओं को हम अंततः अपने मन द्वारा ही जान पाते हैं. मन यदि विचलित विकारग्रस्त होगा, तो संवेदनाओं द्वारा दिया गया संदेश वह भली–भांति ग्रहण नहीं कर सकेगा. अपने विकारों अथवा अपेक्षाओं से मन संवेदनाओं को कलुषित करेगा. ध्यान से मन तटस्थ तथा वस्तुनिष्ठ होता है. इसके परिणामस्वरूप मनोविकारों द्वारा संवेदनाओं का कलुषित होना रुकेगा. मेरे आसपास का विश्व सत्य है एवं इसे जानने के लिए मेरे पास ज्ञानेन्द्रियां और मन यही दो साधन हैं. अतएव विनोबा जी ने इन ज्ञानेन्द्रियों को शरीर का प्रकाशद्वार कहा है. ये साधन संवेदनाक्षम एवं स्वच्छ करने का अर्थ है, सत्य जैसा है वैसा जानने की क्षमता विकसित करना. ध्यान व योग द्वारा यह सत्यदर्शन बेहतर हो सकता है, लेकिन सत्य यानी कि ईश्वर यह तो मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं. तब तो ध्यान द्वारा विश्व–दर्शन=सत्य–दर्शन=ईश्वर–दर्शन फिर एक बार दृष्टि स्पष्ट व स्वच्छ होने का चक्र पूर्ण हुआ एवं सब कुछ साफ दिखाई देने लगा. ध्यान कैसे ईश्वर के नजदीक ले जाता है, यह समझ में आ गया. अलग से कोई ईश्वर दिखाई नहीं देगा. अभी वर्तमान क्षणों में हमारे आस–पास ही जो विश्व है, उसी में ईश्वर के दर्शन करने की शक्ति और दृष्टि हमें ध्यान से प्राप्त होगी. ईश्वर इस सृष्टि के पार कहीं और नहीं है. इस विश्व में सर्वत्र समाया हुआ है. वह कहीं बाहर से आकर हमें दर्शन नहीं देगा. मेरी दृष्टि में स्वच्छता, तीव्रता व निर्मलता आने पर वह जहां है, जैसा है, वैसा ही दिखाई पड़ने लगेगा. नजरों में ही ईश्वर को स्थापित करना होगा. यही योग है और यही भक्ति है.

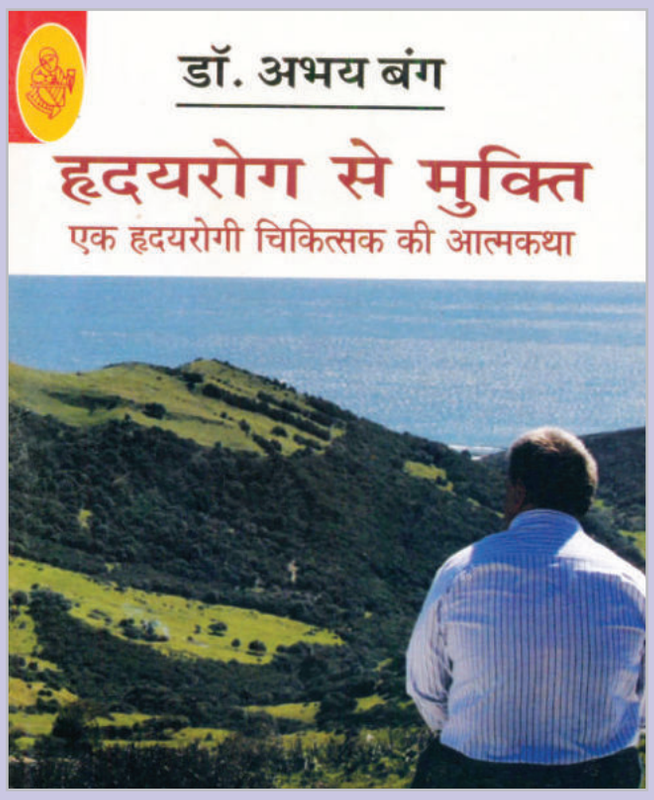

जेथे जेथे जाई मन, फिरवावा नारायण

जहां–जहां मन जाएगा, वहां–वहां नारायण को ले जाओ आज सबेरे अचानक विचार आया –अरे, ईशावास्योपनिषद में जो कहा है मूर्णमिदम् यानी वह निर्गुण अमूर्त ईश तत्व पूर्ण है यह मुझे सहज स्वीकार्य है. लेकिन पूर्णमदः यानी यह सर्वत्र दिखाई देने वाला सगुण साकार विश्व भी पूर्ण है, उतना ही ईश्वर है, यह मात्र पचता नहीं, अनुभूत नहीं होता. इस सगुण के विविध रूपों के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं. राग–द्वेष पसंद–नापसंद वगैरह. निराकर तत्व हमें ईश्वर के रूप में देखना सुविधाजनक लगता है. उसका कोई गुण व आकार न होने की वजह से उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया नहीं होती. निराकार, निर्विकार होने से उसके प्रति हम निर्विकार रह सकते हैं, लेकिन सगुण साकार के प्रति हमारे विकार प्रतिक्रिया के रूप में उभरते ही हैं.

यह कुछ ठीक नहीं, सगुण भक्ति वाले कहते हैं कि निगुण उपासना कठिन है, अतः सगुण रूप चाहिए और मुझे तो उलटा ही अनुभव होता है. इस सगुण में ईश्वर कब दिखाई देगा? कब अनुभव आएगा? ईश्वास्यं इदं सर्वम् सर्वत्र ईश्वर भरा हुआ है, यह सतत अनुभव कब होगा? अध्यात्म मार्ग का यह छलावा हमेशा बना रहता है. साथ ही यह आशा और यह हूक कि वह दर्शन कब होगा. यह लुकाछिपी करता प्रश्न सच पूछो, तो वह दर्शन इसी क्षण मेरे चारों ओर अभी है. बस मुझे दिखाई नहीं देता अनुभूत नहीं होता. मुझे वह दृष्टि कब मिलेगी? बीच का परदा कब उठेगा? मूर्तिपूजा के लिए मेरे मन में कभी आकर्षण नहीं रहा. मैंने स्वयं शायद ही कभी मूर्ति पूजा की हो. रानी अवश्य काफी मूर्तिपूजक हैं. मैं उसका विरोध भले ही नहीं करता, लेकिन थोड़ा–सा मजाक जरूर उड़ाता था. मूर्तिपूजा के नाम पर होने वाले कर्मकाण्डों से तो मुझे बेहद चिढ़ है. एक मूर्ति में परमेश्वर की कल्पना के बजाय विश्वव्यापी अदृश्य तत्व की कल्पना मुझे अधिक अच्छी लगती है. मेरी उपासना, यदि उसे उपासना कहा जाए, तो वह निर्गुण थी. यह मेरे नैसर्गिक स्वभाव का भी भाग था. सगुण साकार मुझे उतना आकर्षित नहीं करता था. उसके बजाय मनुष्य का नैसर्गिक अथवा आध्यात्मिक तत्व, मनुष्य का मनोविज्ञान मुझे अधिक अच्छा लगता था. रोगी मनुष्य के बजाय उसका रोग मुझे अधिक इंटरेस्टिंग लगता था. प्रेमभावना की बजाय तात्विक विचारों का मुझ पर अधिक प्रभाव होने की वजह से सगुण भक्ति की बजाय ईश्वर की निर्गुण कल्पना मुझे अधिक स्वीकार्य लगती थी. विनोबा जी पुस्तक गीता प्रवचन के दसवें–ग्यारहवें एवं बारहवें अध्याय में निर्गुण–सगुण भक्ति एवं मूर्तिपूजा संबंधित विस्तृत विवेचन पढ़ा और अचानक मेरे बुद्धिवादी आग्रह दूर होने लगे. विनोबा का वह विवेचन इतना अप्रतिम है कि उसे मूल रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए. विश्व में समाया हुआ ईश्वरीय तत्व अथवा सत्य, जितना विश्व में है अधिक नहीं, तो उतना ही वह उस मूर्ति में भी है. वह मूर्ति विश्व का छोटा–सा रूप ही तो है. छोटा ही हो, फिर भी वह पूर्ण रूप है. ईश्वर का अपूर्ण टुकड़ा नहीं छोटी आवृत्ति है.

मूर्तिपूजा का अर्थ तो कुछ समझ में आया. संत ज्ञानेश्वर ने तो और भी कमाल कर दिया है . उनके अनुसार ईश्वर के वैश्विक स्वरूप का लघु रूप यदि मूर्ति है तो उससे भी सरल सुलभ प्रतीक है. नाम, परमेश्वर का नाम. ■

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

दीया

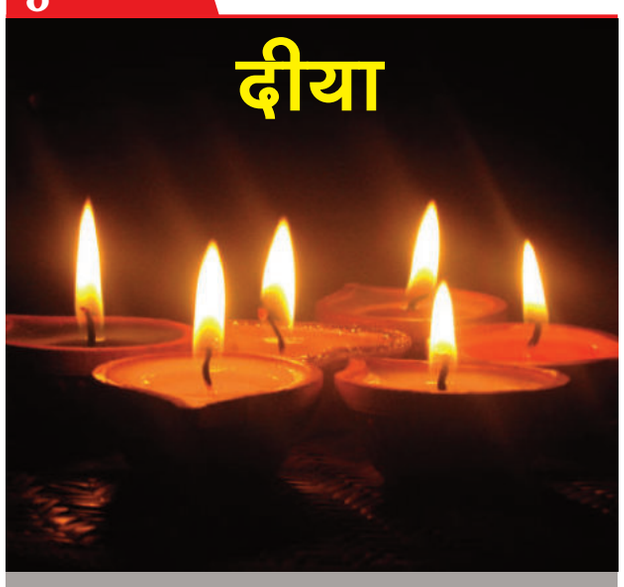

एक बार की बात है, दीपावली की शाम थी, मैं दीये सजा ही रहा था कि एक ओर से दीपों के बात करने की आवाज़ सुनाई दी. मैंने ध्यान लगाकर सुना. चार दीपक आपस में बातें कर रहे थे. कुछ अपनी सुना रहे थे, कुछ दूसरों की सुन रहे थे. पहला दीपक बोला, मैं हमेशा बड़ा बनना चाहता था, सुंदर बनना चाहता था पर क्या करूँ ज़रा–सा दिया बन गया. दूसरा दीपक बोला, मैं भी अच्छी भव्य मूर्ति बनकर किसी अमीर के घर जाना चाहता था. उनके सुंदर, घर की शोभा बढ़ाना चाहता था, पर क्या करूँ मुझे कुम्हार ने छोटा–सा दिया बना दिया. तीसरा दीपक बोला, मुझे बचपन से ही पैसों से बहुत प्यार है काश मैं गुल्लक बनता, तो हर समय पैसा मेरे पास होता.

चौथा दीपक चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था. अपनी बारी आने पर मुस्कराकर अत्यंत विनम्र स्वर में कहने लगा, एक राज़ की बात मैं आपको बताता हूं, कुछ उद्देश्य रख कर आगे पूर्ण मेहनत से उसे हासिल करने के लिए प्रयास करना सही है, लेकिन यदि हम असफल हुए, तो भाग्य को कोसने में कहीं भी समझदारी नहीं हैं. यदि हम एक जगह असफल हो भी जाते हैं तो और द्वार खुलेंगे. जीवन में अवसरों की कमी नहीं हैं, एक गया तो आगे अनेक मिलेंगे. अब यही सोचो, दीपों का पर्व–दीपावाली आ रहा है, हमें सब लोग खरीद लेंगे. हमें पूजा घर में जगह मिलेगी. कितने घरों की हम शोभा बढ़ाएंगे. इसलिए दोस्तों, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, हर हाल में खुश रहो. द्वेष मिटाओ. खुद जलकर भी दूसरों में प्रकाश फैलाओ.

शिक्षा: जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

एक ओर जहां देशभर में लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य के मीना बाज़ार में तब्दील होते जा रहे हैं. जहां साहित्य और साहित्यकार को उपभोक्ता वस्तु में तब्दील करने का खेल खेला जा रहा है. साहित्य और संस्कृति की आड़ में मुनाफ़ा कमाने का उद्यम हो रहा है, ऐसे में पटना पुस्तक मेला देश की साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के अभियान में जुटा है. हिंदी के तमाम साहित्यकारों और संस्कृतिकर्मियों को भी इस मेले में सहभागिता से चीज़ों को देखने की एक नई दृष्टि मिलती है.

मेला नहीं आंदोलन

अनंत विजय

चंद दिनों पहले ख़त्म हुए पटना पुस्तक मेला में तक़रीबन बीस वर्षों बाद जाने का अवसर मिला. आयोजक सेंटर ऑफ रीडरशिप डेवलपमेंट की एक गोष्ठी 'विकास की राजनीति' पर व्याख्यान और सवाल जवाब का सत्र था. पटना पुस्तक मेले में पहुंचते ही नॉस्टेलजिक हो गया. वही गांधी मैदान, वही घेरा, तमाम स्मृतियां दिमाग़ में कौंधने लगीं. तमाम शिक्षाविद यह कहते हैं कि लड़के स्कूल और कॉलेज छोड़कर या भागकर फिल्में देखने चले जाते हैं, लेकिन कोई भी स्कूल कॉलेज से भागकर पुस्तकालय या फिर पुस्तकों के पास नहीं पहुंचता है. यह बात सत्य हो सकती है पर हमारा अनुभव बिल्कुल अलहदा है. हम तो कॉलेज छोड़कर अपने दोस्तों के साथ 1992 का पुस्तक मेला देखने तक़रीबन सवा दो सौ किलोमीटर की यात्रा करके पटना पहुंचे थे. दो तीन दिनों तक पुस्तक मेले में ख़रीदारी की थी. वहीं कई हिंदी के प्रकाशकों के स्टॉल पर जाकर पुस्तक क्लब आदि की सदस्यता भी ली थी. मेरे जैसे जाने कितने नौजवान बिहार के दूर–दूर के गांवों–कस्बों से पटना पुस्तक मेले में पहुंचते होंगे. बिहार की बारे में मान्यता है कि वहां सबसे ज्यादा पत्र–पत्रिकाएं बिकती हैं. लोग सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक रूप से जागरूक हैं. यह हक़ीक़त भी है. यहां के लोग सिर्फ़ पढ़ते ही नहीं हैं, उसपर बेहिचक अपनी राय भी देते हैं. बिहार में इस जागरूकता को और फैलाने और नई पीढ़ी की पढ़ने की रुचि को संस्कारित करने में पटना पुस्तक मेले ने बेहद सकारात्मक और अहम भूमिका निभाई है. बिहार ने इस स्थापना को भी नैगेट किया है कि युवा साहित्य नहीं पढ़ते या युवाओं की साहित्य में रुचि नहीं है. पटना पुस्तक मेले के दौरान युवाओं की भागीदारी और उनके उत्साह को देखकर संतोष होता है कि पाठक बचे हैं, ज़रूरत सिर्फ़ उनतक पहुंचने के उपक्रम की है. पटना पुस्तक मेले के दौरान इस बार लेखक रत्नेश्वर की क़िताब जीत का जादू को लेकर ग़ज़ब का उत्साह देखने को मिला. मैं, विनोद अनुपम, रत्नेश्वर जी, प्रभात प्रकाशन के कर्ताधर्ता पियुष जी उनके स्टॉल के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे. अचानक एक छात्र पहुंचा और उसने रत्नेश्वर जी के पांव छुए. अचकचाते हुए रत्नेश्वर जी ने झुके हुए छात्र को उठाया और प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखा. उस छात्र ने छूटते ही कहा– सर मैंने आपकी किताब 'जीत का जादू' पढ़ी है. इस किताब ने मुझे गहरे तक प्रेरित किया और मेरी सोच और राह दोनों बदल दी. अब रत्नेश्वर जी का चेहरा दमकने लगा था. एक लेखक के चेहरे पर उस तरह की संतोष मिश्रित ख़ुशी जरा कम ही देखने को मिलती है. ख़ैर, दोनों के बीच बातचीत ख़त्म हुई और उस लड़के ने जाते वक़्त कहा कि आप और भी इस तरह की किताबें लिखिए.

आज से तकरीबन साठ साल पहले बिहार में पुस्तक मेले को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी. साठ के दशक में ही पटना में एक पुस्तक प्रदर्शनी लगी थी, उसके बाद रुक–रुक कर लंबे–लंबे अंतराल के बाद पटना में पुस्तक मेले का आयोजन होता रहा. कभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तो कभी नेशनल बुक ट्रस्ट ने तो कभी पुस्तक व्यवसायी संघ ने पटना में पुस्तक मेले का आयोजन किया. हर बार बिहार की जनता ने अपने उत्साह से आयोजकों को फिर से पुस्तक मेला आयोजित करने के लिए बाध्य किया. फिर भी निरंतरता नहीं बन पाई थी. अस्सी के दशक के अंतिम वर्षों में इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि कोई एक संगठन नियमित तौर पर पटना में पुस्तक मेले का आयोजन करे. बिहार शैक्षिक संघ बना और उन्नीस सौ नब्बे में 14 दिनों तक चलने वाले पुस्तक मेले का आयोजन किया गया. यह पुस्तक मेला इतना सफल रहा कि 1991 और 1992 में आयोजित किया गया. फिर तो पुस्तक मेला बिहार के सांस्कृतिक कैलेंडर में स्थायी हो गया. कालांतर में यह एक वर्ष रांची और एक वर्ष पटना में आयोजित होने लगा. हर साल यह आयोजन दोनों जगहों पर सफल होता रहा. मुझे याद है कि पटना पुस्तक मेले की चर्चा पटना से दूर गांवों और कस्बों तक पहुंचने लगी थी. इस काम में बिहार के दैनिक अखबारों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है. ऐसा नहीं है कि पटना पुस्तक मेले के आयोजन में बाधा नहीं आई. दो हज़ार में पटना जिला प्रशासन ने आयोजन स्थल गांधी मैदान के आबंटन के लिए व्यावसायिक दर से शुल्क मांगा जो कि इतना ज्यादा था कि आयोजकों को स्थान बदलने पर मजबूर होना पड़ा. पुस्तक मेला पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से हटकर शहर के एक दूसरे छोर पर स्थित पाटिलपुत्र कॉलोनी के मैदान जा पहुंचा. गांधी मैदान न देने का फ़ैसला सरकारी अफसरों की संवेदनहीनता का नमूना था. लेखकों, संस्कृतिकर्मियों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों के ज़बरदस्त विरोध में सरकार ने नियमों में बदलाव कर पुस्तक मेले के लिए विशेष इंतज़ाम किया. ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी मैदान से पुस्तक मेले को हटाने की प्रतिक्रिया में ही वहां हर साल यह आयोजन होने लगा. भागीदारी भी बढ़ी और पुस्तक मेले का दायरा भी. पुस्तकों से आगे जाकर उसने सांस्कृतिक आंदोलन की शक्ल अख़्तियार कर ली. पटना पुस्तक मेले में लेखकों, पत्रकारों और विशेषज्ञों के साथ नियमित विमर्श होता है. इस बार भी हर दिन एक ख़ास विषय पर हर रोज़ शाम चर्चा हुई. दिल्ली से हर दिन कई लेखकों और पत्रकारों की भागीदारी रही. पाखी के संपादक प्रेम भारद्वाज, बिंदिया की संपादक गीताश्री, इंडिया टुडे के मैनेजिंग एडिटर दिलीप मंडल, कथाकार उदय प्रकाश के अलावा कई लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया. गंभीर चर्चा के अलावा मेले के दौरान फिल्मों पर एक कार्यक्रम बाइस्कोप भी होता है. इसमें किसी एक थीम पर हर दिन एक फिल्म का प्रदर्शन होता है. पटना पुस्तक मेले ने सूबे में समाप्तप्राय नुक्कड़ नाटक को एक विधा के तौर फिर से संजीवनी प्रदान की. इस काम के लिए सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट की तारीफ़ की जानी चाहिए.

एक ओर जहां देशभर में लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य के मीना बाज़ार में तब्दील होते जा रहे हैं. जहां साहित्य और साहित्यकार को उपभोक्ता वस्तु में तब्दील करने का खेल खेला जा रहा है. साहित्य और संस्कृति की आड़ में मुनाफ़ा कमाने का उद्यम हो रहा है, ऐसे माहौल में पटना पुस्तक मेला देश की साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के अभियान में जुटा है. पटना पुस्तक मेले में देशभर के बुद्धिजीवियों की भागीदारी उसको एक व्यापक फलक भी प्रदान करती है. हिंदी के तमाम साहित्यकारों और संस्कृतिकर्मियों को भी इस मेले में सहभागिता से चीज़ों को देखने की एक नई दृष्टि मिलती है. अब ज़रूरत इस बात की है कि पटना पुस्तक मेले को भारत सरकार अपने सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल करे और विश्व के साहित्यिक पर्यटकों को यहां बुलाने का उद्यम करे. अगर ऐसा हो पाता है तो हिंदी के लेखकों और संस्कृतिकर्मियों को विश्व स्तर पर पहचान भी मिलेगी और शोहरत भी. ज़रूरत तो इस बात की भी है कि बिहार सरकार इस पुस्तक मेले को बिहार के गौरव के साथ जोड़कर प्रचारित करे, ताकि बिहार की गंभीर छवि से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों का परिचय हो सके.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)

anant.ibn@gmail.com

कविता

ज़िम्मेदारियां

विमलचंद्र पांडेय

वक़्त बीतने के साथ जैसे घटता है बालों का घनत्व
गुस्से का परिमाण
और हड्डियों का कैल्शियम
इसी तरह या किसी दूसरे पैटर्न पर बदलता है
जिम्मेदारियों का रूप और इनका धर्म

कल आवारा कहा जाने वाला लड़का
आज झुला रहा है अपनी बेटी को अपनी बांहों के झूले में
निकालता हुआ तोतली आवाज़
मेली गुलिया, मेली बिटिया

कल की संकोची लड़की आज मॉडलिंग की शूट में अधनंगी बैठी
ज़रा भी असहज महसूस नहीं कर रही
जस्ट टेक दिस शॉट इमिडिएटली

पहली चोरी के बाद स्कूल से निकाला गया बालक
बीसवें कत्ल के लिए झाड़ियों के पीछे घात लगाए बैठा है
इस बार निशाना नहीं चूकेगा भाऊ, एनिहाऊ

पिछले चुनाव में हारने के बाद इस बार
पूरे तामझाम के साथ दौरे पर निकला है पूर्व मंत्री
और तेज़ चलो रामसुभग, तीन गांव करने हैं

जैसे बदल जाती है बाहर आने जाने की आवृत्ति
खाने का चार्ट
पुराने टीवी कार्यक्रम
दोस्तों के पते और फोन नंबर
वैसे ही शर्ट, जूते या चश्मे का नंबर जैसी
फालतू चीज़ें बदलते ही
हम पाते हैं कि जिम्मेदारियां भी बदल गई हैं

हम कभी बड़े नहीं होते
लेकिन ये हमें रंग लेती हैं अपने रंग में
और हमें चीज़ों को वाजिब अभिनय के साथ बरतना सिखाती हैं

जिम्मेदारियां मौत की तरह आती हैं
अचानक, चुपचाप, दबे पांव

पुस्तक समीक्षा

मुश्किल समय में असुविधाजनक कविताएं

रेणु व्यास

पाश ने कहा था– *'सबसे ख़तरनाक होता है/मुर्दा शांति से भर जाना/न होना तड़प का सब सहन कर जाना/घर से निकलना काम पर/और काम से लौटकर घर जाना/सबसे ख़तरनाक होता है/हमारे सपनों का मर जाना.'* जिसे पाश समाज के लिए ख़तरनाक कहते हैं, वह आज के सफल व्यक्ति के लिए सुरक्षित रूप से जीने का सबसे सुविधाजनक रास्ता है. सुविधाजनक है–सड़क के किनारे फेंकी गई मरनासन्न लड़की और घायल लड़के का अनदेखा कर आगे बढ़ जाना. सुविधाजनक है– कचरे के ढेर से पॉलिथीन बीनते बच्चे की ओर से आंखें फेर लेना. सुविधाजनक है–चाय की गिलास लाते–ले जाते छोटू को पढ़ने का उपदेश देना. भीख मांगते किशोर को काम करके पसीने की कमाई खाने का उपदेश देना. और इन सबके साथ ही देश की राजनीति के गिरते स्तर पर चिंता जताना. और इन सबसे भी ज़्यादा सुविधाजनक है– सुविधाशुल्क के ज़रिये अटका–लटका काम निकलवाना. रक्तालोक–स्नात पुरुष क्यों किसी–किसी मुक्तिबोध के ही सीने में जगता है? जब साहित्यिक बिरादरी सुविधाजनक तरीक़े से मृत्यु दल के प्रोसेशन की शोभा बढ़ा रही हो. आज के युग में एक नये किस्म का नियतिवाद छाता जा रहा है– भूमंडलीकरण. यह तो होना ही है. खुला बाज़ार, उपभोक्तावाद यह तो भूमंडलीकरण के साथ आना ही है. हमारे जल, जंगल और ज़मीन, जो बेहतर क़ीमत लगाए, उनके हाथों बिकने ही हैं. एक लाख रुपये की कार के लिए खेत का मोह छोड़ना होगा. धान तो राशन की दुकान पर दो–तीन रुपये किलो भी मिल सकता है. 27 मंज़िल के घरवालों के लिए, ईंट–गारे–कवेलू की झोपड़ी वाले को अपना घर छोड़ना ही होगा. नहीं तो तोड़ने के लिए विकास के बुलडोज़र की मदद लेनी होगी. बांध बनेंगे, तभी बिजली आएगी. कितने बेशर्म लोग हैं, घर टूटने का मुआवज़ा लेकर भी घर नहीं छोड़ते. विकास रोका नहीं जा सकता. इसकी इतनी क़ीमत तो चुकानी ही है.

कुल मिलाकर एक आरोपित विकल्पहीनता की स्थिति में हम जी रहे हैं. कम से कम हमारे कथित उच्च मध्यम वर्ग के लिए तो यह नियतिवाद न केवल इच्छित अपरिहार्य है, बल्कि नए अवसरों को भी लेकर आया है–लाख दो लाख प्रति माह वेतन पाने का अवसर, वीक एंड में हिल स्टेशन और सालाना छुट्टियां सिंगापुर, दुबई और स्विटजरलैंड में मनाने का अवसर. नौकरियां और निष्ठाएं पैरहन की तरह बदलना आज मजबूरी नहीं, अपारच्युनिटी है. फिर भी वे अपारच्यूनिस्ट नहीं, आप्टिमिस्टिक हैं. धारा में बहते ऐसे सुविधापरक ज़माने में धारा का रुख मोड़ने की बात करना बेमानी ही नहीं, बेवकूफ़ी समझी जाती है, सभ्य शब्दों में कहें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा कवि का भोलापन कहा जा सकता है. अशोक कुमार पांडेय की एक कविता की कुछ पंक्तियां इसी सुविधाजनक चुप्पी का रहस्य खोलती हैं–

'वे चुप हैं/कि उन्हें मालूम हैं आवाज़ के ख़तरे/वे चुप हैं कि उन्हें मालूम हैं चुप्पी के हासिल/...../चुप्पी ख़तरा हो तो हो/ज़िंदा आदमी के लिए/तरक्कीराम के लिए तो मेहर है अल्लाह की.' ऐसे समय में कविता करना, वह भी यथास्थिति से प्रतिरोध की, उसके परिवर्तन के लिए, अपने आप में एक असुविधाजनक स्थिति है. अशोक अपने कविता संग्रह 'लगभग अनामंत्रित' में यही असुविधा अपने लिए चुनते हैं–'एक असुविधा
थी कविता हमारे हिस्से.'

पाश की बात को आगे बढ़ाते हुए अशोक कहते हैं– 'बहुत बुरे होंगे वे दिन/जब रात की शक्ल होगी बिलकुल देह जैसी/और उम्मीद की चेकबुक जैसी/विश्वास होगा किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का विज्ञापन/खुशी घर का कोई नया सामान/और समझौते मजबूरी नहीं, बन जाएंगे आदत/लेकिन सबसे बुरे होंगे वे दिन/जब आने लगेंगे इन दिनों के सपने.' (सबसे बुरे दिन) ये बुरे दिन तो आ चुके. कम से कम देश–दुनिया के एक सुविधाभोगी हिस्से के लिए. क्योंकि 'बनिया की भाषा तो सहमति की भाषा है' (धूमिल), मगर दुनिया सिर्फ़ इतनी ही तो नहीं. इस 99 प्रतिशत बाकी दुनिया के रोटी, कपड़ा, मकान, काम के सिर्फ़ सपने नहीं, अधिकार के संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध होना सिर्फ़ कविता का नहीं, लेखन का ही नहीं, इंसानियत का फर्ज़ है. जो बचेगा/कैसे रचेगा? (श्रीकांत वर्मा). राहत की बात है कि अशोक कुमार पांडेय की कविताएं इन सवालों से पूरी ताक़त से जूझती हैं और यही प्रतिबद्धता उनकी ताक़त है. आधिपत्य, दमन और शोषण सत्ता का स्वभाव है और हर प्रकार के दमन, शोषण का विरोध सच्ची कविता का. कविता का स्वाभाविक क्षेत्र सत्ता का प्रतिपक्ष है. सत्ता चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक–सामाजिक वर्चस्व कायम करने वाली हो या फिर पितृ–सत्ता. धूमिल के शब्दों में–'कविता/शब्दों की अदालत में/मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का/हलफनामा है.' अशोक कुमार पांडेय की कविता भी यही भूमिका निभाती है– 'हर उस जगह थे हमारे स्वप्न/जहां वर्जित हमारा प्रवेश.'

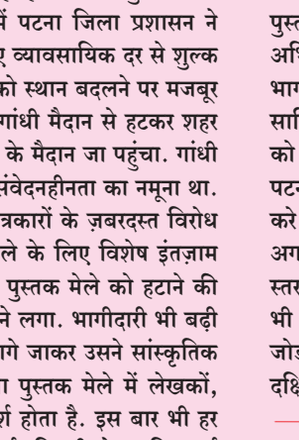

उनकी कविताओं में आज की शोषक यथास्थिति के ख़िलाफ़ आक्रोश है, मगर काग़ज़ी नहीं. इस उबलते आक्रोश में उनके हृदय की ऐंठन है, दिमाग की चटकती हुई नसें हैं और साथ ही एक गहरा दर्द है, सहानुभूति है और कुछ अपराधबोध भी; नहीं है तो– निराशा, ऊब और भावहीन तटस्थता. यह 'लगभग अनामंत्रित' परिवर्तन के लिए अनिच्छुक ही नहीं, उसे असंभव मानने वाले, यथास्थिति को स्वीकार करने वाले आज के स्वप्नहीन सुविध–ाजनक व्यावहारिक समय में राहत की बात है. बेहतर दुनिया के सपने को साकार करने के लिए प्राथमिक शर्त है– उस सपने में और उसकी अवश्यंभाविता में विश्वास रखना. यह विश्वास अशोक की कविताओं में नज़र आता है. *'समझौतों और समर्पण के इस अंधेरे समय में/जितना भी बचा है संघर्षों का उजाला/समेट कर भर लेना चाहता हूं अपनी कविता में/और दे जाना चाहता हूं तुम्हें उम्मीद की तरह जिसकी शक्ल/मुझे बिलकुल तुम्हारी आंखों–सी लगती है.'*

'लगभग अनामंत्रित' में कई कविताएं इसी संवेदनशीलता की बानगी पेश करती हैं और बेशक वे इस संग्रह की सबसे अच्छी रचनाओं में से हैं. 'एक सैनिक की मौत' कविता में कवि युद्धोन्मादी देशभक्ति के विपरीत, एक मां का थका हुआ रुदन, पिता की अनदेखी उदासी, पत्नी की सूनी मांग और बच्चों की निरीह भूख को देखता है, जिसे कोई नहीं देखता. देखना ही नहीं चाहता. यह कविता यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्यों यह गौरवपूर्ण शहादत एक बेरोज़गार युवा की ज़िंदगी की मजबूरी है? *'देशभक्ति नौकरी की मजबूरी थी/और नौकरी ज़िंदगी की/बचपन में कुत्तों के डर से/रास्ते बदल लेने वाला मेरा दोस्त/आठ को मार कर मरा था/बारह दुश्मनों के बीच फंसे आदमी के पास/बहादुरी के अलावा और चारा भी क्या है?'* उस पर विडम्बना यह कि यह शहादत किसी युद्ध में नहीं, शांति की जय–जयकार करती युद्ध जैसी स्थिति में हुई थी. *'अजीब खेल है/कि वज़ीरों की दोस्ती/प्यादों की लाशों पर पनपती है/और जंग तो जंग /शांति भी लहू पीती है.'*

'जगन की अम्मा' कविता एक बहुत ही आत्मीय याद के सहारे, उपभोक्तावादी भयावह संभावनाएं' (या आशंकाएं) हमारे सामने रखती है. *मैं चाहता हूं/इस तेज़ी से भागती समय की गाड़ी के लिए/कुछ मासूम से कस्बाई स्टेशन.' 'पता नहीं कितनी बची हो तुम मेरे भीतर'* कविता में कवि आधी दुनिया की संवेदना को वही होकर महसूस करना चाहता है.

कवि की कुछ प्यारी कविताएं अपनी बेटी (या सिर्फ़ बेटी) के नाम हैं. बेटी के जन्म पर दादी मां की उदासी का बगैर किसी नारेबाजी के निवारण करती यह कविता देखिए– *'मां दुखी है/कि मुझ पर रुक जाएगा खनदानी शजरा/...../उदास हैं दादी, चाची, बुआ, मौसी...../कहीं नहीं जिनका नाम उस शजरे में/जैसे फस्लों का होता है नाम/पेड़ों का, मकानों का...../और धरती का कोई नाम नहीं होता.....'*

'काम पर कांता' घड़ी की सुइयों के साथ भागती कामकाजी गृहिणी की दिनचर्या को दर्ज करती है. 'चाय, अब्दुल और मोबाइल' भी मध्यमवर्गीय विसंगतियों को दर्शाती एक और कविता है. 'अकीका' कविता मात्र एक रस्म का अर्थ जानने के लिए डिक्शनरी देखना नहीं है. यह एक ही देश के दो समुदायों के बीच आ गए अपरिचय को रेखांकित करती है, जिसके बिना सांप्रदायिकता को गलतफहमियां फैला कर पैर टिकाने की जगह नहीं मिल पाती. इस संग्रह में कुछ दूसरी तरह की कविताएं भी हैं, जिन में कवि की वैचारिकता प्रबल है. एक लंबी कविता है, जो दर–असल आदिवासी कहे जाने वाले लोगों की उनके निवास–स्थान से ही नहीं, उनके जल, जंगल और ज़मीन से ही नहीं, जीने के अपने अधिकार से बेदख़ल किए जाने और विकास के नाटक का नेपथ्य उद्घाटित करती सत्यकथा है– *'जब वे कहते विकास/हमारी धरती के सीने पर कुछ और फफोले उग आते.'*

अशोक न सिर्फ सोचते हैं, बल्कि सोचे हुए को करना भी अपना कर्तव्य मानते हैं. *अच्छे आदमी/हमेशा सोचते हैं अच्छी बातें/यहां तक कि/दुनिया को बदल देने के बारे में/सिर्फ़ सोचते हैं.'* 'जो नहीं किया हमने' सत्तर के दशक के कामरेड के जीवन की विडम्बना को दर्शाती है, 'जहां दुनिया बदलने से पहले ही बदल गया सब कुछ' और 'अब तो बस कविता ही रह गई है अंतिम अवलंब'. अशोक जो ख़ुद एक कवि हैं, कविता को कर्म का विकल्प नहीं मानते– *'जानते तो आप भी हैं कि कुछ करना/विकल्प नहीं होता सब कुछ करने का/और न ही हमेशा कुछ न करने से बेहतर.'* लेकिन फिर भी कविता उनके लिए लड़ाई का एक आवश्यक अस्त्र है लड़ रहे हैं कि नहीं बैठ सकते खामोश.' उनकी नज़र बहुत साफ़ है क्योंकि उन्हें यह पता है कि उन्हें किसके विरुद्ध लड़ना है और किसके लिए. हिरोशिमा की परमाणविक त्रासदी पर रची कविता 'आग', 'तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह' भी महत्व–पूर्ण कविताएं हैं.

असल में अवतार सिंह पाश, धूमिल, कुमार विकल को समर्पित यह कविता–संग्रह साहित्य–जगत में 'अनामंत्रित' नहीं है, यह गुंजाइश कवि ने ख़ुद 'लगभग' विशेषण लगा कर छोड़ दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

लैपकेयर लैपटॉप एक्सेसरीज की जानी-मानी कंपनी है, जो लगभग सभी लैपटॉप ब्रांड के लिए एक्सेसरीज बनाने का काम करती है. कंपनी ने लैपकेयर इन्वर्टर के नाम से इसी एक्सेसरीज को पेश किया है, जो कार में लैपटॉप को चार्ज करेगी.

आठ हजार का फैबलेट 13 हजार का गिफ्ट

यह फैबलेट सबसे पहले होमशॉप 18 के जरिये लॉन्च किया गया. इस फैबलेट के साथ 1000 रुपये का फ्री सर्टिफिकेट और 12000 रुपये मूल्य का एयरसेल पैकेज ऑफर किया जा रहा है.

भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स ने अपना नया फैबलेट-कैनवास जूस 77 ऑनलाइन लॉन्च किया है. इस फैबलेट के बारे में जानकारी पहले ही माइक्रोमैक्स ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर दी थी. होमशॉप 18 पर यह फैबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है. इस सस्ते फैबलेट की कीमत 7999 रुपये है. इसके अलावा कंपनी इस फैबलेट के साथ एयरसेल का खास ऑफर और कई सारी फ्री एक्सेसरीज भी दे रही है. यह फैबलेट सबसे पहले होमशॉप 18 के जरिये लॉन्च किया गया. इस फैबलेट के साथ 1000 रुपये का फ्री सर्टिफिकेट और 12000 रुपये मूल्य का एयरसेल पैकेज ऑफर दिया जा रहा है. यह बात पक्की है कि भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ जमाने के लिए माइक्रोमैक्स कंपनी खूब मेहनत कर रही है. इस फैबलेट का नाम कैनवास जूस इसकी बैटरी को ध्यान में रखकर दिया गया है. इस फैबलेट में 3000 एमएएच की बैटरी है, जो लगभग 10 घंटों का टॉकटाइम देती है. कंपनी के हिसाब से इस हैंडसेट के बैटरी यूजर को यह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी. कैनवास जूस फैबलेट की स्क्रीन 5 इंच की है. इसके साथ ही इस फैबलेट में 854-480 पिक्सल का कैमरा है. यह फैबलेट एंड्रॉयड जेलीबीन 4.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. 1.3 जीएचजेड के डुअल कोर प्रोसेसर के साथ इस हैंडसेट में 1 जीबी रैम भी है. अगर इंटरनल मेमोरी की बात करें तो इस फैबलेट में 4 जीबी की मेमोरी है. इस फोन की एक्सटर्नल मेमोरी को 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. एक तरह से देखा जाए तो बजट फैबलेट के हिसाब से इस हैंडसेट में अच्छे स्पेसिफिकेशन हैं. माइक्रोमैक्स कैनवास जूस में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है. इसी के साथ वीजीए फ्रंट कैमरा भी है. साथ ही लगभग सभी तरह के कनेक्टिविटी ऑप्शन भी हैं.

ख़ास है यह ऑडियो सिस्टम

अधिकतर कार यूजर्स अब सीडी प्लेयर की जगह डिजिटल ऑडियो का इस्तेमाल करने लगे हैं. सभी कारों में आज पोर्टेबल डिजिटल ऑडियो सिस्टम देखे जा सकते हैं, लेकिन यदि बात करें शानदार फीचर्स और साउंड क्वालिटी की, तो कुछ ही ऐसे ऑडियो सिस्टम होते हैं, जो हमारी उम्मीद के अनुसार होते हैं. यूएसबी, ब्लूटुथ आईपैड सपोर्ट के साथ काम करने वाला ऐसा सिस्टम, जो म्यूजिक क्वालिटी में भी शानदार हो, तो आप ऐसे ऑडियो सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं.

1 पायनियर एविक जेड 130बीटी

कार टेक फीचर्स की नजर से इस ऑडियो सिस्टम में आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं. इसमें हैंड्सफ्री कॉलिंग, वाइस कंट्रोल डिजिटल ऑडियो प्लेबैक और डिरेक्शन जैसे फीचर्स मौजूद हैं.

2 एल्पिन सीडीई-141

कम बजट के लिए एल्पिन सीडीई-141 एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें ऑडियो के सभी बेसिक फीचर्स मौजूद हैं.

3 सोनी मैक्स जीएस600बीटी

इस ऑडियो सिस्टम में कई फीचर्स मौजूद हैं. हालांकि इस ऑडियो सिस्टम को ऐप के जरिये कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. बाकी इसमें जरूरत के सभी फीचर्स मौजूद हैं.

4जी का है जमाना 3जी हुआ पुराना

भारत में 4जी से चलने वाला हैंडसेट कम से कम 18,000 रुपये का है, लेकिन अधिकतर हैंडसेट 40,000 रुपये से ज्यादा की हैं. इसके विपरीत 3जी से लैस फोन सस्ते हो गए हैं और उनकी कीमतें 4,000 रुपये से कम हो गई हैं.

जल्द ही मोबाइल के शौकीनों के लिए स्मार्टफोन सस्ते दामों में बाजार में उपलब्ध होंगे. इनकी विशेषता यह होगी कि ये 4जी टेक्नोलॉजी के होंगे. इनकी कीमत मात्र 6200 रुपये होगी. अगले डेढ़ सालों में सस्ते 4जी फोन मिलने लगेंगे. ब्रॉडकॉम ने इस बारे में जानकारी दी है. यह कंपनी मोबाइल के चिप्स बनाती है. कंपनी के सीनियर डायरेक्टर माइकल सिवीलो ने बताया कि अमेरिका में आपॅरेटर 6200 में 4जी मोबाइल फोन खरीदने के लिए तैयार है.

अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन डेढ़ वर्ष में संभव हो जाएगा.

4जी टेक्नोलॉजी अपनी पूर्ववर्ती 3जी से पांच गुना तेज है, लेकिन अभी इस पर चलने वाले हैंडसेट महंगे हैं. भारत में 4जी से चलने वाला हैंडसेट कम से कम 18,000 रुपये का है, लेकिन अधिकतर हैंडसेट की कीमत 40,000 रुपये से ज्यादा है. इसके विपरीत 3जी से लैस फोन सस्ते हो गए हैं और उनकी कीमतें 4,000 रुपये से कम हो गई हैं.

सिवीलो ने कहा कि भारत में इसकी कीमतें इसकी बिक्री के वॉल्यूम पर और रिलायंस जियो इंफोकॉम पर निर्भर करेगी, जिसके पास देश भर में 4जी स्पेक्ट्रम का ठेका है. कीमतें इन परिस्थितियों पर ही निर्भर करेंगी. ■

कार में लैपटॉप करें चार्ज

कार में अब सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं. हम कार में मोबाइल के साथ-साथ लैपटॉप भी रखते हैं. कभी घर या ऑफिस में लैपटॉप चार्ज करना भूल गए तो कोई बात नहीं, आप उसे कार में चार्ज कर सकते हैं. बड़ी बात यह है कि कार के अंदर इसको चार्ज करने की जरूरत भी पड़ती है. इसके लिए लैपकेयर इंडिया ने एक ऐसा लैपटॉप चार्जर लॉन्च किया है, जिसका इस्तेमाल कार में किया जा सकता है. लैपकेयर लैपटॉप एक्सेसरीज की जानी-मानी कंपनी है, जो लगभग सभी लैपटॉप ब्रांड के लिए एक्सेसरीज बनाने का काम करती है. कंपनी ने लैपकेयर इन्वर्टर के नाम से इसी एक्सेसरीज को पेश किया है, जो कार में लैपटॉप को चार्ज करेगी.

इस इन्वर्टर में कूलिंग फैन और यूनिवर्सल सॉकेट की सुविधा दी गई है, जिससे आप आसानी से लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं. कंपनी

दमदार है यह बाइक

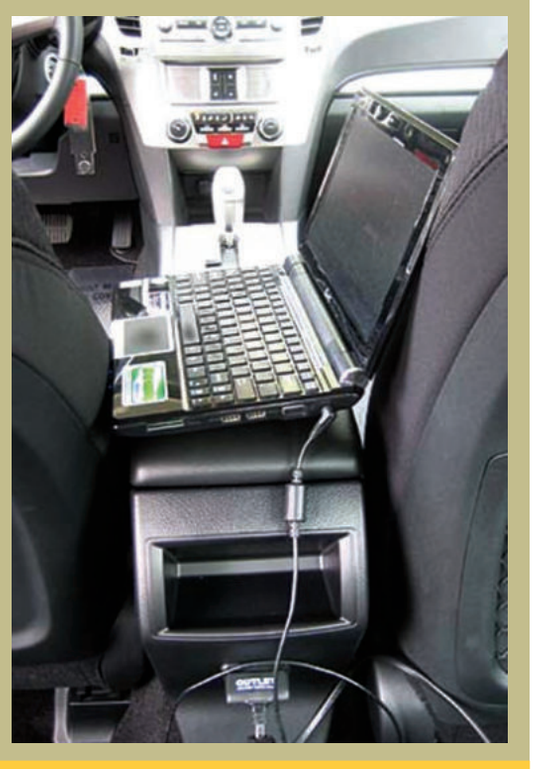

लंबे इंतजार के बाद मशहूर ब्रिटिश बाइक कंपनी रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे एडवांस और हल्की बाइक लॉन्च की है. कंपनी कॉन्टीनेंटल जीटी को भारत में लॉन्च करने जा रही है. इस मोटरसाइकिल को साल की शुरुआत में यूके में लॉन्च किया गया था. हाल ही में कंपनी ने इसके लिए गोवा में एक बड़ा इवेंट किया था. द कॉन्टीनेंटल जीटी में 535 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन है, जो कि 29पीएस और 44एनएम पीक टॉर्क की मैक्सिमम पावर है. इसमें 5-स्पीड गियर बॉक्स भी है. इसमें 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है और इस मोटरसाइकिल का कुल वजन 184 किलोग्राम है.

इस मोटरसाइकिल में 18 इंच के स्पोक्ड व्हील्स हैं. इसमें 300एमएम फ्लोटिंग ब्रेम्बो डिस्क ब्रेक आगे के लिए और 240 एमएम डिस्क रियर के लिए दिए गए हैं. कंपनी ने इस बाइक की कीमत 2.05 लाख रुपये (दिल्ली एक्स शोरूम) तय की है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

होंडा की बेहतरीन कार

होंडा सिटी का यह मॉडल पेट्रोल तथा डीजल दोनों में लॉन्च किया गया है. भारतीय बाजार में एंट्री लेवल सेडान कार अमेज के बाद सिटी सेडान होंडा की यह दूसरी कार है, जो डीजल इंजन के साथ आ रही है.

जापान की मशहूर कार कंपनी होंडा ने सेडान नाम से नया मॉडल पेश किया है. कंपनी का यह नया मॉडल दिल्ली में पेश किया गया है. पहली बार होंडा ने सिटी को थाईलैंड की बजाय भारत में पेश किया है.

कंपनी ने नई सिटी के लिए एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी. सिटी के डीजल मॉडल की एडवांस बुकिंग राशि 50,000 हजार रुपये रखी गई है. होंडा सिटी का पहला अवतार भारत में 1998 में पेश किया गया था, तब से ये कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है. होंडा सिटी का यह मॉडल पेट्रोल तथा डीजल दोनों में लॉन्च किया गया है. भारतीय बाजार में एंट्री लेवल सेडान कार अमेज के बाद सिटी सेडान होंडा की यह दूसरी कार है, जो डीजल इंजन के साथ आ रही है. कंपनी ने इसमें बॉडी डिजाइन और डीजल इंजन सहित कई सारे नये फीचर्स शामिल किए हैं, जो पहले के मॉडल से ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक हैं.

होंडा सिटी के डीजल मॉडल में 1.5 लीटर आईडीटीईसी टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो शानदार पावर और बेहतर माइलेज के लिए जाना जाता है, जबकि पेट्रोल मॉडल में इंजन संबंधी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं. नई होंडा सिटी अगले साल जनवरी माह से बाजार में मिलने लगेगी. कंपनी चार अन्य प्रोडक्ट्स भी आने वाले दो साल में पेश करने वाली है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

“यूएई ने 1996 में एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था. इसके बाद यह उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का दूसरा मौका है. नेपाल और हांगकांग के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का पहला अनुभव होगा.”

फीफा विश्व कप -2014

कौन मनाएगा सांबा के संग जश्न

फुटबॉल के महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है. समूचा विश्व एक बार फिर इसके ख़ुमार में डूब जाएगा. भारत में भले ही फुटबॉल की उतनी लोकप्रियता नहीं, जितनी कि क्रिकेट की, लेकिन फुटबॉल के खेल में जो ऊर्जा होती है, वह सबको अपनी जद में ले लेती है. फुटबॉल प्रेमियों के ख़ुमारी की ऐसी ही तस्वीरें अब पूरे विश्व में दिखाई देंगी.

मेसी ने भले ही इटली की टीम का नाम संभावित विजेता के रूप में नहीं लिया हो, लेकिन चार बार खिताब जीत चुकी इटली को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. 2006 की विजेता इटली की टीम बेहद आक्रामक तरीके से विश्व कप में उतरने की तैयारी कर रही है. इटली की टीम अपने आक्रामक खेल के लिए जानी जाती है. इटली की टीम के पास योग्यता, ज्ञान और परिपक्वता का अद्भुत मिश्रण मौजूद है. इसलिए उसे नज़रअंदाज कर पाना आसान नहीं है. इटली को हराकर ही स्पेन ने यूरो कप-2012 का खिताब जीता था.

नवीन चौहान

फुटबॉल विश्व कप के आयोजन में अभी छह महीने बाकी हैं. विश्व कप इस बार 12 जून से 13 जुलाई तक ब्राजील में खेला जाएगा. उरुग्वे के क्वालीफाई करते ही विश्व कप में खेलने वाली 32 टीमों की लाइनअप तय हो गई. इसके बाद विश्व कप विजेता के नाम को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं. अभी ऑक्टोपस पॉल की तरह किसी ने किसी एक टीम के विजेता बनने की भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन लोगों की अटकलें घूम-फिर कर कुछ टीमों के इर्द-गिर्द आकर खड़ी हो रही हैं. हाल ही में अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लायोनेल मेसी ने विजेताओं को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने हाल ही में तीसरी बार यूरोपियन लीग का गोल्डन शू पुरस्कार जीता. इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना, गत विजेता स्पेन, मेजबान ब्राजील, फ्रांस को 2014 विश्व कप के पांच सबसे बड़े दावेदार बताया. हालांकि मेसी ने अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाली टीम को अपनी टॉप फाइव की सूची में जगह नहीं दी.

मेसी अपनी क्लब की उपलब्धियों को विश्व कप में दोहराना चाहते हैं और अर्जेंटीना को विश्व कप विजेता बनाना चाहते हैं. इन्होंने कहा कि उनकी किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक विश्व कप जीतने की चाह है. उन्होंने अर्जेंटीना के अलावा चार अन्य टीमों को विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार बताया, जिसमें मेजबान ब्राजील, जर्मनी, गत विजेता स्पेन और फ्रांस की टीमें शामिल हैं. अर्जेंटीना को दावेदार बताते हुए सदी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी डियागो मेराडोना ने कहा है कि 2014 में मेसी अर्जेंटीना को विश्व कप विजेता बना सकते हैं. अर्जेंटीना की टीम में कुल मिलाकर मेसी पर निर्भर नज़र आती है. वही उनकी नैया को पार लगा सकते हैं. एक टीम की जीत में हर किसी का योगदान होता है. जब तक मेसी को साथी खिलाड़ियों से सहयोग नहीं मिलेगा, वे कोई करिश्मा नहीं कर पाएंगे.

इस बार विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों में अफ्रीकी महाद्वीप से अलजीरिया, कैमरून, आइवरी कोस्ट, घाना और नाइजीरिया एशिया के चार देश ऑस्ट्रेलिया, इरान, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप के 13 देश बेल्जियम, बोस्निया-हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, रूस, स्पेन, स्विटरजरलैंड. उत्तरी और मध्य अमेरिका से कोस्टारिका, होंडूरस, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से 6 देश अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, उरुग्वे. अंतिम 32 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं. 2010 में मेजबान रही दक्षिण अफ्रीका की टीम अंतिम 32 में जगह नहीं बना पाई.

अब तक हुए विश्व कप के 19 संस्करणों में ब्राजील सर्वाधिक 5 बार, इटली 4 बार, जर्मनी 3 बार, अर्जेंटीना और उरुग्वे दो-दो बार और इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस एक-एक बार विश्व कप पर कब्जा कर चुके हैं. स्पेन पिछले चार साल में फुटबॉल जगत में अपनी पकड़ बना चुका है. उनके टिकी-टिका स्टाइल ने उन्हें विश्व की हर बड़ी प्रतियोगिता का विजेता बना दिया है. स्पेनिश खिलाड़ियों का बेहतर तालमेल अगर इस बार भी चलता दिखा तो उन्हें खिताब बचाने से कोई टीम नहीं रोक सकती है. पिछले चार साल में स्पेनिश टीम ने विश्व कप के अलावा 2012 में लगातार दूसरी बार यूरो कप पर कब्जा किया. हालांकि 2013 में हुए कॉन्फिडरेशन कप में स्पेन को फाइनल में ब्राजील ने 3-0 से मात दी थी. बावजूद इसके, वे विश्व कप जीतने के प्रबल दावेदार हैं. स्पेन लगातार फीफा रैंकिग में नंबर एक पर बनी हुई है. अन्य टीमों के मुकाबले वह रैंकिंग अकों के मामले में दूसरी टीमों से बहुत आगे है. 2008 से लेकर अब तक स्पेन फीफा की टीम ऑफ द इयर का खिताब जीत रही है.

इस बार विश्व कप की मेजबानी ब्राजील कर रहा है, जिसे फुटबॉल का होमग्राउंड भी कहा जाता है. मेजबान ब्राजील को घर में विश्व कप के आयोजन को लेकर बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ब्राजील की टीम में नेमियार जैसे स्टार खिलाड़ी की मौजूदगी में बेहतरीन प्रदर्शन करने का माद्दा रखती है. घरेलू दर्शकों की मौजूदगी में किसी भी टीम का चरित्र कैसे बदलता है, यह हमने 2002 में कोरिया-जापान में हुए विश्व कप में दक्षिण कोरिया और जापान के प्रदर्शन में हुए अद्भुत परिवर्तन के रूप में देखा था. कोरियाई टीम चौथे स्थान पर रही थी. इसी तरह मेजबान के रूप में पहली बार विश्व कप में खेल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रही थी. उसने फ्रांस टीम को पटखनी देकर ग्रुप में बड़ा उलटफेर कर दिया. वह एक गोल के अंतर की वजह से दूसरे राउंड में नहीं पहुंच सका था. ब्राजील दूसरी बार विश्व कप की मेजबानी कर रहा है. 1950 में मेजबान ब्राजील को फाइनल में उरुग्वे ने हराकर पहली बार विश्व कप पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार ब्राजील मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता है. वह विश्व फुटबॉल का हमेशा से सिरमौर रहा है. उनके पांच खिताब इसके गवाह हैं, लेकिन मेजबान के रूप में वह विश्व कप जीतने में नाकामयाब रहा है. इसलिए 12 साल के विश्व कप खिताब के सूखे को ब्राजील अपनी धरती पर ही खत्म करना चाहता है. उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं. वे एक टीम के रूप में बेहतर खेलते हैं. इसके साथ ही अपने घरेलू मैदान पर खेलना खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, जो उन्हें विश्व कप जीतने के लिए प्रेरित करेगी.

मेसी ने भले ही इटली की टीम का नाम संभावित विजेता के रूप में नहीं लिया हो, लेकिन चार बार खिताब जीत चुकी इटली को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. 2006 की विजेता इटली की टीम बेहद आक्रामक तरीके से विश्व कप में उतरने की तैयारी कर रही है. इटली की टीम अपने आक्रामक खेल के लिए जानी जाती है. इटली की टीम के पास योग्यता, ज्ञान और परिपक्वता का अद्भुत मिश्रण मौजूद है. इसलिए उसे नज़रअंदाज कर पाना आसान नहीं है. इटली को हराकर ही स्पेन ने यूरो कप-2012 का खिताब जीता था. भले ही जर्मनी के हाथ कोई बड़ा खिताब नहीं लगा हो, लेकिन इसे इस कारण उन्हें कतई कमजोर नहीं आंका जा सकता है.

जब कभी फुटबॉल की सबसे लोकप्रिय टीम की बात आती है, तो जर्मनी का नाम सबसे ऊपर आता है. जर्मनी की टीम में मुलर और क्लिनसमेन जैसे कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो कि जर्मन टीम को खिताब जिता सकते हैं. पिछले विश्व कप में जर्मनी की टीम सबसे युवा टीम थी. टीम के खिलाड़ियों की औसत उम्र सबसे कम थी. यह टीम चार साल बाद ज्यादा अनुभवी और परिपक्व हो गई है. यदि कोई जर्मन टीम से विश्व कप जीतने की अपेक्षा रखता है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है.

फ्रांस की टीम को मेसी ने अपनी सूची में जगह दी है. फ्रांस की टीम का प्रदर्शन पिछले कुछ विश्व कप में उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 1998 में वे विश्व विजेता बने तो 2002 में ग्रुप स्टेज में बाहर का रास्ता देखने वाली पहली खिताब बचाने वाली टीम बनी. इसके बाद फिर से 2006 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उपविजेता बनी थी. इसके बाद 2010 के विश्व कप में वह पहली बार विश्व कप में खेल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम से हारकर पहले ही दौर में विश्व कप से बाहर हो गई थी. यदि वह इसी ट्रेंड पर चल रही है तो फ्रांस की बारी एक बार फिर से फर्श से अर्श पर पहुंचने की है.

साबां नृत्य के साथ हो रहे फुटबॉल कार्निवाल में विजेता ढूंढ पाना आसान नहीं दिख रहा है. यही इसकी लोकप्रियता में चार चांद लगाएगी. अभी विश्व कप के आगाज में काफी वक्त है. यह समय सभी टीमों के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने और रणनीति बनाने के लिए पर्याप्त है. टिकटों की बिक्री जोर-शोर से चल रही है. यह सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है. यह फुटबॉल के बुखार के बढ़ने का संकेत है. इस बुखार से कोई भी खेल प्रेमी नहीं बचना चाहेगा. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

सचिन ने शुरू की दूसरी पारी

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनीसेफ ने अपना ब्रांड एंबेसडर चुना है. वह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे. सचिन ने इस मौके पर कहा कि मेरी ज़िदगी को इस शानदार दूसरी पारी शुरू करने का मौका देने के लिए शुक्रिया. मैं यूनीसेफ से जुड़कर बहुत उत्साहित हूं और अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता के हिसाब से सेवा करूंगा. यह पारी मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है.■

टी-20 विश्व कप में आठ एशियाई टीम

एशिया में क्रिकेट अपना पैर बड़ी तेजी और मजबूती के साथ पसार रहा है. इसका उदाहरण 2014 में बांग्लादेश में खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप में खेलने वाली टीमों की संख्या से मालूम होता है कि एशिया में क्रिकेट की लोकप्रियता कितनी तेजी बढ़ रही है. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे टेस्ट प्लेइंग नेशंस के अलावा अफगानिस्तान, नेपाल, हांगकांग और यूएई की टीमें खेलती दिखाई देंगी. अफगानिस्तान ने तीसरी बार टी-20 विश्व कप में क्वालीफाई किया है, जबकि नेपाल, हांगकांग और यूएई की टीमें पहली बार विश्व कप में अपने जलवे बिखेरती दिखेंगी. यूएई ने 1996 में एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था. इसके बाद यह उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का दूसरा मौका है. नेपाल और हांगकांग के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का पहला अनुभव होगा. इन चारों के अलावा अबुधाबी में हुए क्वालीफायर टूर्नामेंट में नीदरलैंड और आयरलैंड की टीमों ने विश्व कप में खेलने की पात्रता हासिल की. गौरतलब है कि टी-20 विश्व कप 16 मार्च से बांग्लादेश में खेला जाएगा, जिसमें कुल 16 टीमें खेलती दिखेंगी.■

नये वनडे नियमों से गेंदबाजों को नुकसान

श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट कप्तान अर्जुन रणतुंगा को डर है कि वनडे क्रिकेट के नियमों में बार-बार होने वाले बदलाव के कारण बल्लेबाजों को काफी फायदा मिल रहा है. रणतुंगा का कहना है कि बल्लेबाजों को मिलने वाले फायदे के कारण कोई भी गेंदबाजी नहीं करना चाहेगा और अगर ऐसा होता है, तो वह दिन दूर नहीं, जब गेंदबाजों का अकाल पड़ जाएगा.

रणतुंगा ने कहा कि कई लोगों को लगता है कि क्रिकेट बैट्समेन का खेल है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अनुपात 50-50 नहीं तो 60-40 होना चाहिए. रणतुंगा ने कहा कि अब मुझे लगता है कि खेल बल्लेबाजी के पक्ष में 95-5 हो गया है. उनका मानना है कि दुनिया भर में गेंदबाजी का स्तर तेजी से गिरा है. उन्होंने कहा कि जूनियर क्रिकेटरों का झुकाव भी बल्लेबाजी की तरफ होगा. और अगर यही हाल रहा तो एशिया को भविष्य में काफी परेशानी होगी. उन्होंने कहा कि कई बार उपमहाद्वीप में खेलते समय गेंद जल्दी खराब हो जाती है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जब आप सीमिंग ट्रैक पर खेलते हैं, तो तेज गेंदबाज को फायदा होता है. श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या ने कहा कि वह अभी भी एक गेंद अपनाने के पुराने नियम को तरजीह देंगे. पूर्व तेज गेंदबाज चामिंडा वास ने कहा कि गेंदबाजों को खुद को नये नियमों के अनुरूप ढाल लेना चाहिए.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

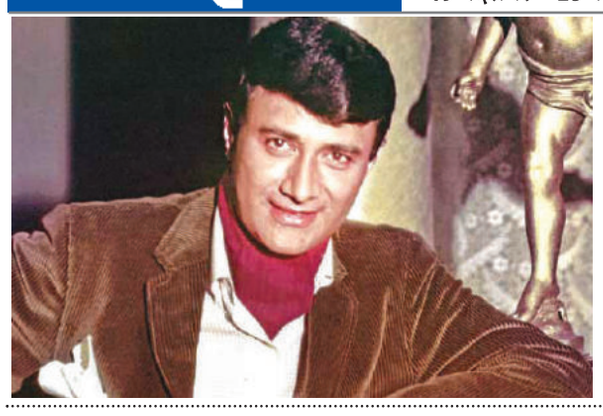

एक फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद के जीवन में सुरय्या आईं. दोनों ने 6 फिल्में साथ कीं. एक शूटिंग के दौरान देव ने सुरय्या को डूबने से बचाया था. सुरय्या उनकी दीवानी हो गईं और प्यार करने लगीं. आहिस्ता–आहिस्ता दोनों के बीच दोस्ती से आशिकी का सफ़र शुरू हो गया.

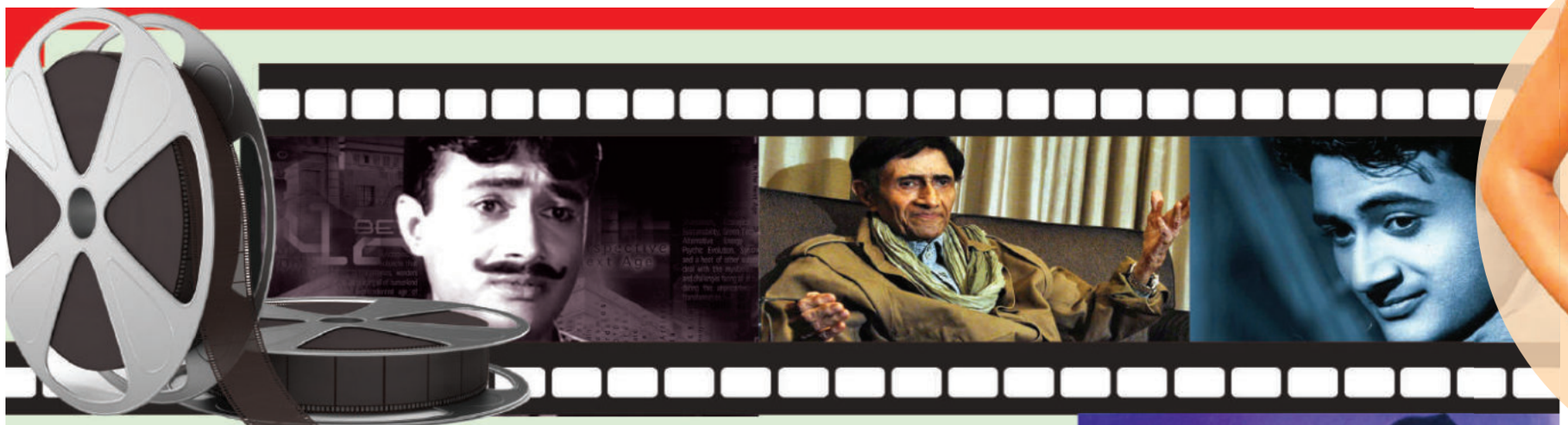

मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया...

भारतीय सिनेमा देव आनंद के बिना पूरी नहीं होती. वह एक संपूर्ण अभिनेता, निर्माता-निर्देशक और लेखक थे. देव आनंद का असल नाम धर्म देव था.

एम एच पाशा

अदाकारी को एक नया आयाम देने वाले देव आनंद ने लोगों के दिलों में अपनी ऐसी जगह बनाई कि उनका जादू 50 साल से भी ज़्यादा समय तक बरक़रार रहा. उन्हें सदाबहार नायक का खिताब मिला.

देव का जन्म पंजाब की तहसील शंकरगढ़ के ज़िला गुरदासपुर में 26 सितंबर, 1923 को हुआ, जो अब पाकिस्तान में है. उनके पिता पिशोरीमाल आनंद वकील थे. वे कुल 5 भाई–बहन थे. विजय आनंद, चेतन आनंद, मनमोहन और बहन शीला. शीला के बेटे हैं फिल्ममेकर शेखर कपूर.

देव की स्कूलिंग स्कारेड़ हार्ट स्कूल, डलहौज़ी, हिमाचल प्रदेश में हुई. उन्होंने स्नातक अंग्रेजी साहित्य में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से किया. 1940 में देव मुंबई आ गए और चर्चगेट पर मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 160 रुपया महीना की नौकरी करने लगे. वे 60 रुपये अपने पास रखते थे और बाक़ी घर भेज दिया करते थे. एक दिन उनकी जेब में मात्र 30 रुपये थे. पैसों की उन्हें सख्त ज़रूरत थी. तब उन्होंने अपने जमा किए डाक टिकट का एलबम बेच दिया. नौकरी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उन्हें प्रभात टाकीज़ की फिल्म हम एक हैं, में काम करने का मौक़ा मिला. मज़ाकिया अंदाज़ और बातों के गुनी देव साहब की दोस्ती पूना में शूटिंग के दौरान गुरुदत्त से हुई. एक दिन देव चर्चगेट पर लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे कि उनके पास शाहीद लतीफ़ और इस्मत चुग़ताई आकर बैठ गए और पूछा कि इन दिनों क्या कर रहे हो? देव ने जवाब दिया कि कुछ ख़ास नहीं. अगले ही दिन शाहिद लतीफ़ ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज़ बुलाया, जहां अशोक कुमार ने उन्हें फिल्म ज़िद्दी का नायक बना दिया. इस फिल्म में उनकी नायिका थीं कामिनी कौशल. इस फिल्म को बहुत सफलता मिली. समय के साथ चलने और प्रतिभा के साथ सही मौक़े को समझने कि सलाहियत उनमें बहुत थी. उन्होंने वर्ष 1949 में अपनी फिल्म कंपनी बनाने का फ़ैसला किया और नवकेतन के नाम से एक फिल्म कंपनी की नींव रखी. फिल्मों की गहरी समझ रखने वाले देव ने बतौर निर्माता अपनी पहली ही फिल्म में अपने दोस्त गुरुदत्त को डायरेक्टर लिया और बाज़ी नाम कि फिल्म का निर्माण किया. यह फिल्म 1951 में रिलीज हुई, मगर कुछ खास नहीं कर पाई. कई प्रतिभाएं मिलकर एक कलाकार का निर्माण करती हैं. देव की शख्सियत को निखार कर नायक बनाने में किशोर कुमार का बड़ा योगदान था. किशोर की आवाज़ को देव आनंद ने अपनी अदाकारी का अंदाज़ दिया और यही आवाज़ देव की पहचान बन गई. बतौर अभिनेता और निर्माता पहचान बना चुके देव की जल्द ही राही और आंधियां, दो फिल्में आईं. टैक्सी ड्राइवर उनकी बेहतरीन फिल्म थी, जो सुपरहिट हुई. फिल्म काला पानी के लिए उन्हें बेस्ट ऐक्टर अवॉर्ड से नवाज़ा गया. वह जीवन में एक भी पल गंवाना नहीं चाहते थे. उनके लिए मंदिर फिल्म स्टूडियो ही था. उस जमाने में नौजवान उनके स्टाइल के दीवाने थे. लड़कियां उनकी अदा पर जान झिड़कती थीं और उनकी एक झलक पाने के लिए बेक़रार रहती थीं.

तभी उनकी ज़िंदगी में सुरय्या आईं. दोनों ने 6 फिल्में साथ में कीं. एक शूटिंग के दौरान देव ने सुरय्या को डूबने से बचाया था. सुरय्या उनकी दीवानी हो गईं और प्यार करने लगीं. आहिस्ता–आहिस्ता दोनों के बीच दोस्ती से आशिकी का सफ़र शुरू हो गया. जीत के सेट पर देव ने सुरैय्या से अपने प्यार का इज़हार किया. देव ने सुरैय्या को तीन हज़ार रुपये की हीरे की अंगूठी दी, लेकिन सुरैय्या की नानी को यह रिश्ता नामंजूर था. वो हिंदू–मुस्लिम शादी के पक्ष में नहीं थीं और यहां तक कि फिल्म में सुरैय्या के देव के साथ दिए जाने वाले रोमांटिक सीन से भी उन्हें आपत्ति थी. इस तरह इस प्रेम कहानी का भी अंत हो गया, पर सुरैय्या ने किसी और से भी शादी नहीं की. देव जिंदगी अपने हिसाब से जीते थे. एक दिन तो उन्होंने शूटिंग के दौरान ही लंच ब्रेक में अपनी सहयोगी कलाकार कल्पना कार्तिक से शादी करके सबको चौंका दिया.

उन्होंने 1965 में अपनी पहली रंगीन फिल्म गाइड की. यह आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित थी. फिल्म में उनकी नायिका वहीदा रहमान थीं. इस फिल्म को देव की बेहतरीन फिल्म माना जाता है. देव को फिल्मों की गहरी समझ थी. उन्होंने बतौर अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक फिल्मों में काम किया. बतौर अभिनेता उन्होंने लगभग 100 और बतौर निर्माता 33 फिल्में कीं. उन्होंने 19 फिल्में निर्देशित कीं और 13 फिल्मों की पटकथा लिखी. बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म थी प्रेम पुजारी.

समाज को बेहतर ढंग से समझने वाले देव साहब को दुनिया की भी अच्छी समझ थी. वे भारतीय राजनीति को भी एक बेहतर विकल्प देना चाहते थे. इसलिए उन्होंने वर्ष 1977 में अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसका नाम नेशनल पार्टी ऑफ़ इंडिया रखा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ थी, लेकिन यह राजनीतिक पार्टी बहुत दिनों तक नहीं चल पाई. रोमैंटिक फिल्मों के इस जादूगर ने अपनी फिल्मों में संगीत को बहुत महत्व दिया. अपने साथ बेहतरीन गायक, गीतकार और संगीतकारों की एक जमात रखी, जिसमें शंकर–जयकिशन, ओपी नैय्यर, कल्याणजी–आनंदजी, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन थे. लेखकों में हसरत जयपुरी, मज़रूह सुल्तानपुरी, नीरज, शैलेंद्र, आनंद बख्शी, मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, और मुकेश आदि थे. उन्होंने 2007 में अपनी जीवनी रोमांसिंग विद लाइफ भी लिखी, जिसका विमोचन उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर किया. भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने 2001 में उन्हें पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया.■

feedback@chauthiduniya.com

शादी नहीं की पर

मातृत्व को एंज्वॉय कर रही हैं सुष्मिता

अपनी शर्तों पर जीने वाली सुष्मिता समाज की किसी बंदिश को नहीं मानतीं. सुष्मिता ने हाल ही में अपना 38वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में.

उम्र के 38 वसंत पार कर चुकीं ब्रह्मांड सुंदरी सुष्मिता सेन को अब तक कोई हमसफर नहीं मिला है. सुष्मिता ने शादी तो नहीं की है, पर मातृत्व को वह पूरा-पूरा एंज्वॉय कर रही हैं. उन्होंने दो बच्चियों को गोद लिया है और उनके साथ वे बेहद खुश हैं. सुष्मिता ने हर तरह की फिल्में की हैं, पर फिल्में हिट हो या फ्लॉप, उन्हें फर्क नहीं पड़ता. हालांकि सुष्मिता की तमन्ना है कि वह इंग्लिश-विंग्लिश में श्रीदेवी जैसा किरदार करें. हालांकि फिल्मों से ज़्यादा वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं हैं. इन दिनों उनका नाम जोड़ा जा रहा है रितिक भसीन से. रितिक मुंबई के एक नाइट क्लब के मालिक और ओरियन ऐंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं. सुष्मिता के फैंस भी चाहते हैं कि अब उनका घर बस जाए, लेकिन देखना यह है कि यह रोमांस किसी अंजाम तक पहुंचता है या यह भी सुष्मिता के पुराने अफेयर्स की तरह ही अधूरा रह जाता है. सबसे पहले सुष्मिता का नाम जुड़ा फ़िल्म निर्देशक विक्रम भट्ट से. विक्रम सुष्मिता की पहली फ़िल्म दस्तक के स्क्रिप्ट राइटर थे. शूटिंग के दौरान ही दोनों में प्यार हुआ. एक बच्ची के पिता विक्रम सुष्मिता के साथ लिव-इन में रहने लगे. विक्रम की पत्नी विक्रम की बचपन की दोस्त भी थीं. कुछ वक्त बाद ही विक्रम और सुष्मिता का रिश्ता टूट गया और वो वापस अपनी पत्नी के पास चले गए. विक्रम के बाद हॉटमेल डॉट कॉम के हेड सबीर भाटिया से सुष्मिता का नाम जुड़ा. सबीर ने 10.5 कैरेट की एक डायमंड रिंग भी सुष्मिता को गिफ्ट की. यह अफेयर भी टूट गया. इसके बाद सुष्मिता का नाम जुड़ा स्ट्रगलर रणदीप हुडडा से, पर जब रणदीप को फिल्में मिलने लगीं, तो उन्होंने सुष्मिता से किनारा कर लिया. फिर उनके जीवन में आए मानव मेनन. वह मानव से इतना इंप्रेस्ड हुईं कि उन्होंने अपनी होम प्रोडक्शन फ़िल्म रानी लक्ष्मीबाई के निर्देशन का जिम्मा मानव को सौंप दिया, पर कुछ समय बाद दोनों के बीच तनाव हो गया और फ़िल्म ठंडे बस्ते में चली गई. मानव के बाद सुष्मिता के दिल में दस्तक दी फ़िल्म निर्देशक मुदस्सर अजीज़ ने. उम्र में छोटे मुदस्सर के साथ उनके लिव-इन में रहने की खबरें भी आईं. सुष्मिता का नाम इवेंट मैनेजर बंटी सचदेवा के साथ भी जुड़ा. बंटी सुष्मिता से पहले दो बॉलीवुड हसीनाओं नेहा धूपिया और दीया मिर्जा को भी डेट कर चुके थे. सुष्मिता की पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम से भी गहरी दोस्ती रही. ■

लेखक की समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी बनती है :जलीस शेरवानी

जलीस शेरवानी अब तक 72 फिल्मों की पटकथा लिख चुके हैं. उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सलमान को दबंग की पहचान जलीस शेरवानी की कलम ने ही दी है.

फिल्म लेखक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेट्री और अध्यक्ष रहे लेखक जलीस शेरवानी कहते हैं कि यह सफ़र आसान नहीं था. मां से उन्हें प्रेरणा मिली और सफलता ने उनके क़दम चूमे.

आपने अपना सफ़र कहां से शुरू किया?

फिल्म प्रतिघात से. मैंने गुरुदत्त जी के भाई देवीदत्त जी के लिए सीरियल अपने पराए लिखा. वह दूरदर्शन पर आता था. इसके जरिये मेरी पहचान राजश्री प्रोडक्शन में हुई. यहीं मुझे प्रतिघात मिली.

आप मुंबई कब आए?

1979 में मैं मुंबई आया. तब से लिखने की शुरुआत हो गई. महेश भट्ट का सीरियल ज़मीन आसमान, हिमेश रेशमिया का अंदाज़, कसक, ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी, ज़्यादातर वीकली शो ही लिखे. फिल्मों में नटवर लाल, गेम, संग्राम, माफिया, लोफ़र, हफ्ता वसूली, मृत्युदाता, प्यासा, बाग़ी इन सब फिल्मों के मैंने डायलॉग लिखे हैं. इसके अलावा बतौर गीतकार मैंने पहली फिल्म लिखी हैलो ब्रदर. उसके बाद क्या यही प्यार है, तुमको ना भूल पाएंगे, मुझसे शादी करोगी, वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड, चश्मेबद्दूर, गर्व आदि फिल्मों की पटकथा लिखी.

फिल्मों में आने की प्रेरणा कहां से मिली?

मुंबई आया कि अखबारों में लिखकर रोज़ी–रोटी चलती रहेगी. तभी मेरी मुलाक़ात कल्याणपुरी से हो गई. उन्होंने मेरे अफसाने और डायलॉग अखबारों मे पढ़े थे. मुझे देखते ही पहचान गए. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को आपकी ज़रूरत है. उन्होंने देवीदत्त जी से मीटिंग कराई. पहली ही मीटिंग में काम तय हो गया और शगुन मिल गया.

एक लेखक की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं?

लेखक समाज को दिशा देता है, पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है. कुछ भी लिखा जा रहा है. लेखक का काम समाजिक बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान दिलाना है. वह कलम से ऐसा कुछ न लिखे, जो समाज को गुमराह करे.

आप मानते हैं कि लेखकों को सम्मान नहीं मिलता?

गुलज़ार साहब, जावेद अख्तर, प्रसून जोशी, इरशाद कामिल और समीर जैसे लोगों की इंडस्ट्री में काफ़ी इज़्ज़त है. जिन्हें जगह नहीं मिली, वो जगह बना नहीं पाए. काफ़ी लोग जो अच्छा लिख सकते हैं, वो जगह नहीं बना पाए.

बतौर लेखक पढ़ना कितना ज़रूरी है?

लिखने से ज़्यादा ज़रूरी पढ़ना है. आप चार लेखकों को पढ़कर पांचवां नज़रिया अपना दे सकते हैं.

आज के दौर में फिल्में भी ग्लोबल हुई हैं?

नये–नये विषयों पर फिल्में बन रही हैं. ऐसे में इंटरनेशनल लेबल पर पहचान मिलना तो तय है. पहले हमारे पास लैला मजनू के अलावा क्या था? आज क्रिश, चेन्नई एक्सप्रेस और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्में बन रही हैं, जो पूरी दुनिया में पसंद की जा रही हैं. शाहरुख, सलमान, आमिर की फिल्में ओवरसीज़ में करोड़ों में बिकती हैं. ये देश और जनता दोनों की बड़ी तरक़्क़ी है.

आप किस तरह का सिनेमा पसंद करते हैं?

वे फिल्में, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा हो और व्यावसायिक तौर पर भी हिट हों.

फिल्म लेखक एसोसिएशन का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?

लेखक एसोसिएशन में काम करना अपने फ़ायदे के लिए नहीं होता. मेंबर्स आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजते हैं. इसमें उनका कोई फायदा नहीं होता. जब कोई एसोसिएशन का मेंबर बनता है तो एसोसिएशन उससे वादा करती है कि उस मेंबर के हितों की रक्षा हमारी ज़िम्मेदारी है. अभी भी एसोसिएशन मॉडल कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है. जिस दिन ये प्रोड्यूसर के साथ टाई हो जाएगा, उस दिन हमारे मेंबर्स को बहुत फायदा होगा.

मॉडल कॉन्ट्रैक्ट क्या है?

मॉडल कॉन्ट्रैक्ट लेखक और निर्माता के बीच का वो एग्रीमेंट है, जिसके आधार पर दोनों फिल्म में काम करते हैं. लेखक को कितना पैसा दिया जाएगा, कब–कैसे दिया जाएगा. इसके अलावा फिल्म में लेखक के नाम की वैल्यू होगी. कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के साथ काम करने की शर्तें होंगी. अभी निर्माता लेखक के साथ अपना एग्रीमेंट करता है, जिसमें सिर्फ़ प्रोड्यूसर के हिसाब की शर्तें होती हैं. अपने मेंबर्स की हिफाज़त करना राइटर एसोसिएशन का जिम्मा है, वो करती रही है और हमेशा करती रहेगी.

कॉपीराइट बिल से लेखक कैसे लाभान्वित होंगे?

2004 में हमने लड़ाई शुरू की थी. एक लंबी लड़ाई के बाद 2012 में जाकर पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, जिसमें वक़्त, मेहनत, पैसा और ताक़त लगी. राइटर एसोसिएशन जावेद अख्तर का शुक्रिया अदा करती है. चूंकि जावेद साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिस वजह से बात सरकार तक पहुंच सकी और जावेद अख्तर साहब की स्पीच, जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी, उसके जरिये हम अपनी बात रख सके. अब लेखक को रॉयल्टी मिल सकेगी. उनको उनका हक़ मिल सकेगा. बहुत सालों से उनके हक़ का पैसा उनको नहीं मिल पा रहा था. ये बहुत बड़ी कामयाबी है. खुशनसीब हूं कि मैं इस लड़ाई का हिस्सा बना.

आप अपने प्रशंसकों को कोई संदेश देना चाहते हैं?

हां, मेरी गुजारिश है कि पाइरेटेड फिल्में न देखें और कोई भी पाइरेटेड चीज़ न खरीदें. कपड़ा, दवाई और पार्ट्स कुछ भी नहीं.■

साक्षात्कार : एमएच पाशा, *डीएमएल, मुंबई*

चौथी दुनिया

09 दिसंबर–15 दिसंबर 2013

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार–झारखंड

चारा घोटाले में सीबीआई का शपथपत्र

फंसे या बचे नीतीश

अश्विनी चौबे इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं. सीबीआई पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए वह कहते हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई नीतीश कुमार को बचा रही है. दरअसल, कांग्रेस बिहार में राजनीतिक जमीन की तलाश में है और उसे यह गलतफहमी हो गई है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर वह लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है. इसी लालच में सीबीआई की मदद से नीतीश कुमार को बचाया जा रहा है.

सरोज सिंह

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी से जुड़े चारा घोटाले के मामले में अपना शपथ पत्र पेश कर दिया. नीतीश कुमार से लेकर उनके राजनीतिक विरोधियों तक को इस शपथपत्र का इंतजार था, इसलिए हर एक निगाह 22 नवंबर को हाईकोर्ट में सीबीआई के कदम निहार रही थी. शपथपत्र के माध्यम से सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि चारा घोटाले के तीन मामलों में सीबीआई ने बयानों के बीच तालमेल नहीं रहने और साक्ष्य के अभाव में नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी को आरोपी नहीं बनाया और उनके खिलाफ जांच नहीं की. हालांकि शपथपत्र में सीबीआई ने इस बात को स्वीकार किया है कि चारा घोटाले की जांच के दौरान नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी के पैसे लेने की बात सामने आई थी. एस बी सिन्हा, आर के दास और विजय मलिक ने अपने बयान में पैसा देने की बात स्वीकार की थी, पर ट्रायल के दौरान कोर्ट में वे अपने पहले के दिए गए बयान से पलट गए. सीबीआई ने कोर्ट से आग्रह किया कि मामले में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाए. जाहिर है सीबीआई ने जो दलील पेश की उससे ऊपरी तौर पर तो यह लगता है कि नीतीश कुमार और शिवानंद पर लगाए गए आरोप सबूतों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन क्या सचमुच चारा घोटाले की कहानी कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश करती है जैसी सीबीआई दिखा रही है.

वरिष्ठ वकील दीनू कुमार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रमेश सिंह के मामले में साफ कर दिया है कि किसी अपराध के लिए किसी की संलिप्तता की शंका भी हो तो उससे पूछताछ होनी चाहिए. इसके अलावा पृथ्वीपाल सिंह के केस में यह भी निर्णय आ चुका है कि किसी मामले में एक गवाह होने पर भी फैसला लिया जा सकता है. चारा घोटाले में तो गवाहों की भरमार है, तो फिर सीबीआई ने नीतीश कुमार और शिवानंद से पूछताछ क्यों नहीं की? दीनू कुमार कहते हैं कि सीबीआई खुद कह रही है कि जांच के दौरान नीतीश कुमार और शिवानंद के द्वारा पैसे लेने की बात सामने आई है. शपथ पत्र में यह बात भी कही गई है कि आर के दास ने 164 के बयान में कहा है कि नीतीश कुमार को एक लाख रुपये नकद और एयर टिकट भी दिया गया था. उस समय नीतीश कुमार सांसद थे. दीनू कुमार कहते हैं कि सबसे अहम बात तो यह है कि सीबीआई के शपथ पत्र में एसपी जावेद के हलफनामे का जिक्र ही नहीं है. पटना हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में जावेद ने चारा घोटाले के लाभान्वितों का जिक्र किया था. इससे साफ होता है कि सीबीआई के हलफनामे में कई कमियां है. जिस तरह से सीबीआई ने जांच में भेदभाव किया है उसी तरह शपथ पत्र देने में भी भेदभाव बरता गया है. दीनू कुमार ने कहा कि सीबीआई का यह पहला दायित्व था कि जांच के क्रम में जिन लोगों का नाम आया था, उनके खिलाफ जांच कर आरोपत्र दायर करती या फिर उनके लिए आरोप मुक्ति पत्र जारी करती ताकि कोर्ट अपना निर्णय ले सके. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो शक पैदा करता है. एसपी जावेद ने अपने हलफनामे में उमेश सिंह पर उंगली उठाई थी लेकिन उस मामले की भी लीपापोती कर दी गई. जानकार बताते हैं कि कहीं यह हलफनामा सीबीआई को भारी न पड़ जाए. जब जांच में पैसे के लेनदेन की बात आई और 164 में आर के दास के बयान में भी यह बात कही गई तो कम से कम नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी से सीबीआई को पूछताछ तो करनी ही चाहिए थी. इस मामले में रांची हाईकोर्ट में बहस कर रहे वरिष्ठ वकील विभूति पांडेय का कहना है कि 13 दिसंबर को अदालत में केस की मेरिट पर बहस होगी. वह कहते हैं कि इस पूरे मामले में मेरी आपत्ति केस की जांच को लेकर है. सारी गवाही को कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया गया. कहा जाए तो सीबीआई ने बहुत ही सेलेक्टेड जांच की. हमलोग चाहते हैं कि जांच अपने तय नियमों के आधार पर हो और अगर कोई बेकसूर है तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए. 13 दिसंबर को हम अदालत को सारे तथ्यों से अवगत कराएंगे. इस मामले के याचिकाकर्ता मिथिलेश सिंह सीबीआई के हलफनामे के बाद अपनी जीत को लेकर ज्यादा ही आशान्वित हैं. सिंह कहते हैं कि मेरा सीधा आरोप है कि समता पार्टी का गठन ही चारा घोटाले के पैसे से हुआ है. हलफनामे में भी पैसे के लेनदेन की बात सामने आई है. यही बात हमलोग बार–बार कह रहे थे. अब सवाल है कि अगर लेनदेन हुआ तो फिर पूछताछ क्यों नहीं? क्या सीबीआई मुंह देखकर पूछताछ करती है? पूर्व विधान पार्षद पी के सिन्हा कहते हैं कि 13 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. नीतीश कुमार के खिलाफ इतने तथ्य हैं कि इस मामले में नया मोड़ आना तय है.

– शेष पृष्ठ 18 पर

निर्दलीय विधायक मोदी और
लालू के संपर्क में उपेंद्र कुशवाहा

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में नेताओं ने विकल्प के सारे रास्ते खोल कर रखे हैं. चुनावी सुविधा के हिसाब से समय आने पर तय कर लिया जाएगा कि कौन किसका हमसफर होगा. लेकिन अंदरखानों में हमसफर बनने का होमवर्क जारी है. कुछ परदे के बाहर हैं तो कुछ परदे के पीछे. नीतीश सरकार को समर्थन दे रहे कुछ निर्दलीय विधायकों का धर्य अब टूटता नजर आ रहा है. मंत्रिपरिषद का विस्तार न होने से उनकी हताशा बढ़ती जा रही है. इसके अलावे सरकार ने इन विधायकों से कुछ और वादे भी किए थे जो पूरे नहीं हुए. ऐसा ही एक मामला बिहार गृह रक्षा वाहिनी का है. निर्दलीय विधायक सोमप्रकाश ने उनकी मांगों को लेकर एक समझौता सरकार से कराया था. लेकिन आज की तारीख तक यह समझौता बस कागजों तक ही है. गौरतलब है कि बिहार में गृहरक्षकों की संख्या एक लाख 20 हजार के आसपास है. उनके वेतन व इ्यूटी को लेकर सोमप्रकाश आवाज उठाते भी रहे हैं. पिछली बार सरकार के साथ जो इनका समझौता हुआ था इसमें सोमप्रकाश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. अब जब समझौता लागू नहीं हुआ तो सोमप्रकाश अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं. अपनी ताकत का अहसास कराने के लिए 9 दिसंबर को गृहरक्षकों ने विधानसभा के घेराव का फैसला किया है. वे आर ब्लाक पर धरना व प्रदर्शन भी करेंगे. सोमप्रकाश कहते हैं कि गृहरक्षकों को बार–बार ठगने का काम सरकार कर रही है. उनका आरोप है कि इ्यूटी लेने के लिए भी गृहरक्षकों को एक हजार घूस देनी पड़ती है. उनका कहना है कि सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था पर अब वह सब भूल गई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ राजनीतिक दल उनके आंदोलन को समर्थन दे सकते हैं. बताया जा रहा है कि सोमप्रकाश ने इस पूरे मामले में सुशील मोदी से बात कर इनका सहयोग मांगा है. इस मसले पर सुशील मोदी कहते हैं कि जनसमस्याओं पर जनप्रतिनिधियों से बात होती रहती है. इन्होंने यह भी कहा कि नीतीश सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं. क्या ये सभी आप के संपर्क में हैं इस पर मोदी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के लिए हिट सॉन्ग किसने गाया था . आप खुद अंदाज लगा लीजिए की किसकी निष्ठा किसकी तरफ है? समय आने दीजिए सब साफ हो जाएगा. इसी तरह नए राजनीतिक गठजोड़ का एक किस्सा रांची में भी हुआ. रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने जेल में जाकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मुलाकात की. जब यह माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा से हाथ मिलाना तय है ऐसे में इस नए घटनाक्रम ने राजनीतिक विश्लेषकों को कुछ पल के लिए चौंका दिया. इस मुलाकात के दौरान लगभग दस मिनट तक उपेंद्र कुशवाहा और लालू प्रसाद के बीच अकेले में बातचीत हुई. बताया जा रहा है कि दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए अब जगह न छोड़ी जाए. इस मुलाकात को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इधर लोजपा को दी जाने वाली सीटों को लेकर राजद में अलग–अलग राय है. भाजपा भी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बहुत उदार नहीं दिख रही है. ऐसे में यह नई मुलाकात कोई नया गुल भी खिला सकती है.■

उपेंद्र कुशवाहा

सुशील मोदी

सोम प्रकाश

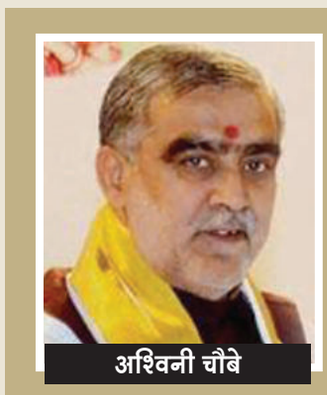
अश्विनी चौबे

शिवानंद तिवारी

पीके सिन्हा

दीनू बाबू

मिथिलेश सिंह

सम्राट चौधरी

भगवान भरोसे जमुई कांग्रेस

राजेश/मनोज feedback@chauthiduniya.com

जमुई में कांग्रेस के चेहरे से गायब हुई मुस्कान की चमक को वापस लाने की कवायद में पिछले दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी यहां आए थे. उनके भाषण के दौरान यह महसूस नहीं हुआ कि वे यहां संगठन को सशक्त करने आए थे. दो दशक से जिले में कांग्रेस की स्थिति काफी खराब है. संगठन की कमान बयोवृद्ध शिवकिशोर सिंह को सौंपकर आलाकमान ने यहां सबों से चल रही आंतरिक गुटबंदी को समाप्त करने का प्रयास किया था. उद्देश्य की कसौटी पर उक्त समझौतावादी निर्णय खरा नहीं उतर पाया. इधर हाल के कुछ वर्षों में पार्टी के जिला समन्वयक अनिल सिंह संगठन को सशक्त करने की कोशिश में जुटे हैं लेकिन मृतप्राय संगठन को पुनर्जीवित करने में उन्हें आंशिक कामयाबी मिली. जमुई स्थित कांग्रेस कार्यालय अपने शुरुआती दिनों में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री चन्द्रशेखर सिंह सहित श्यामा प्रसाद सिंह, कुमार कालिका प्रसाद सिंह, यमुना बाबू जैसे दिग्गजों की राजनीति का केन्द्र हुआ करता था. लेकिन 1995 के बाद पार्टी संगठन से कई नामी सख्शियतों के पलायन कर जाने से यहां पार्टी की नींव ही हिल गई. फिलहाल कांग्रेस संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के बिना नेपथ्य में चल रहा है.

अनिल सिंह

शिवकिशोर सिंह

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
1 YEAR GUARANTY
WINNER OF NATIONAL AWARD
Contact : 9386595926, 9334115955

राजद ने मगध की धरती से किया चुनावी शंखनाद

परिवर्तन रैली के बहाने वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास

प्रमण्डल स्तरीय परिवर्तन रैली में जुटी भीड़ से उत्साहित राजद नेताओं ने लालू प्रसाद को जेल भेजे जाने को भाजपा और जदयू के नेताओं, विशेषकर नीतीश कुमार की, साजिश बताया. राजद के नेताओं ने इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम दावों को झूठ बताया और बिहार की जनता को ठगने वाले नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने वोटरों से आह्वान किया कि लालू जी को जेल भेजने में साम्प्रदायिक ताकतें एकजुट हो गईं. उसी तरह आपको भी एकजुट होने की अपील करने आई हूं और आगामी चुनाव में बिहार की नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करती हूं.

सुनील सौरभ

राष्ट्रीय जनता दल ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में कूदने की तैयारी कर ली है. राजद ने मगध की धरती से इसका शंखनाद कर दिया है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बहुचर्चित चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद जेल जाने पर लगने लगा था कि राजद का कुनबा बिखर जाएगा. लेकिन ऐतिहासिक मगध की धरती गया जिले के नक्सल प्रभावित शेरघाटी अनुमण्डल मुख्यालय में राजद की परिवर्तन रैली में जुटी भीड़ ने साबित कर दिया कि राजद का वोट बैंक आज भी एकजुट है. लेकिन रैली में राजद के वोट बैंक में सत्ता से बेदखल होने का दर्द भी नजर आया. लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद राजद को एकजुट रखने के लिए राबड़ी देवी तथा उनके दोनों पुत्रों, तेजस्वी और तेज प्रताप, ने आगामी लोकसभा चुनाव के महासमर में उतरने के लिए मगध की धरती का ही चुनाव किया. प्रमण्डल स्तरीय परिवर्तन रैली में जुटी भीड़ से उत्साहित राजद नेताओं ने लालू प्रसाद को जेल भेजे जाने को भाजपा और जदयू के नेताओं, विशेषकर नीतीश कुमार की, साजिश बताया. राजद के नेताओं ने इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम दावों को झूठ बताया और बिहार की जनता को ठगने वाले नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने वोटरों से आह्वान किया कि लालू जी को जेल भेजने में साम्प्रदायिक ताकतें एकजुट हो गईं. उसी तरह आपको भी एकजुट होने की अपील करने आई हूं और आगामी चुनाव में बिहार की ढपोरशंखी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करती हूं.

शेरघाटी में आयोजित राजद की परिवर्तन रैली के लिए गया-बोधगया होते हुए, डोभी-शेरघाटी जाने वाली सड़क पर दर्जनों तोरण द्वार तथा हजारों झण्डे-बैनर लगाए गए थे. कभी राजद का गढ़ माने जाने वाले मगध में अपनी बिखर चुकी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए राबड़ी देवी ने राजद कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए आंचल फैलाने की बात करते हुए कहा कि राजद का हर कार्यकर्ता लालू है. लालू प्रसाद के जेल जाने में साजिश की बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश सरकार के कारण बाथे नरसंहार के आरोपी जेल से छूट गए और गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद को बिना कसूर के जेल में डाल दिया गया. परिवर्तन रैली में राबड़ी देवी ने कहा कि विधि-व्यवस्था से लेकर तमाम मोर्चों पर नीतीश सरकार फेल हो गई है. विकास के सारे आंकड़े फर्जी हैं. जमीन पर कहीं कोई विकास नहीं है. गांव में गरीबों के घर और जमीनें छीनी जा रही हैं. पुलिस थानों में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है. इस रैली को लालू-राबड़ी के दोनों पुत्रों, तेजस्वी और तेज प्रताप, ने भी सम्बोधित किया. रैली को पूर्व मंत्री और विधायक डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव, पूर्व विधायक बाजी वर्मा, विनोद कुमार यादवेन्दु, सुरेश पासवान, आदि ने भी सम्बोधित किया. राजद के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रभुनाथ सिंह, रामकृपाल यादव के निशाने पर मुख्य रूप से नीतीश कुमार ही रहे. नीतीश कुमार से भाजपा के अलग होने के बाद राजद के लिए मगध के सभी संसदीय क्षेत्र (गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और कराकट का आधा क्षेत्र) राजद के लिए चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण हो गया है. एनडीए के शुरुआती दौर में भी मगध राजद का गढ़ रहा था. बाद के दिनों में मगध में एनडीए मजबूत हो गया और राजद को मगध में पिछले दो चुनावों में करारी शिकस्त मिली. लेकिन इस बार बिहार में जदयू-भाजपा गठबंधन टूटने के बाद से भाजपा समेत जदयू के हिन्दुत्ववादी सोच के मतदाता नीतीश कुमार से खफा हो गए हैं. हिन्दुत्ववादी सोच वाले मतदाताओं के बंटने की संभावना से राजद में उत्साह है. लेकिन दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल जाने के मामले को भी राजद 'गरीबों के मसीहा को साजिश के तहत जेल भेजे जाने' की बात कह कर चुनावी लाभ लेने की चाहत में हैं. इसलिए राजद के रणनीतिकारों ने इसके लिए मगध की धरती का चयन कर परिवर्तन रैली का आगाज गया जिले के घोर नक्सल प्रभावित शेरघाटी अनुमण्डल मुख्यालय से किया. ज्ञात हो कि कभी मगध के 26 विधानसभा क्षेत्रों में से करीब दो दर्जन पर राजद का ही कब्जा था. लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में स्थिति उलट गई और दो दर्जन क्षेत्रों पर भाजपा-जदयू गठबंधन का कब्जा हो गया. शेरघाटी की परिवर्तन रैली में भीड़ से उत्साहित राजद नेताओं को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में मगध में पार्टी की स्थिति मजबूत होगी. बिहार में कोई भी चुनाव जाति आधारित होता है. इस लिहाज से मगध में राजद के वोट बैंक का प्रतिशत आज सबसे अधिक है. यदि जातीय समीकरण और वोट बैंक एकजुट रहा तो मगध में राजद से मुकाबला करना जदयू तथा भाजपा प्रत्याशियों के लिए बहुत मुश्किल होगा. ऐसे चुनाव में जो समीकरण बनता है वह अंत आते-आते किस रूप में बदल जाएगा कहना बहुत मुश्किल होता है. फिर भी आज मगध में राजद का समीकरण मजबूत नजर आता है.■

feedback@chauthiduniya.com

शेरघाटी की परिवर्तन रैली में भीड़ से उत्साहित राजद नेताओं को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में मगध में पार्टी की स्थिति मजबूत होगी. बिहार में कोई भी चुनाव जाति आधारित होता है. इस लिहाज से मगध में राजद के वोट बैंक का प्रतिशत आज सबसे अधिक है.

चंपारण

सांसद के खिलाफ जदयू की युवा शक्ति

इन्तेजारुल हक

सत्ताधारी दल जदयू की हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है. पार्टी अपने सिद्धान्तों व सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के पहले ही अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझने लगी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोक सभा चुनाव में मजबुत उपस्थिति दर्ज कराने व भाजपा के पीएम उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की हवा को रोकने के लिए एक तरफ संकल्प सभाएं आयोजित कर रहे हैं और जनता का समर्थन मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के कुछ नेता पार्टी सिद्धान्तों व वसूलों को दरकिनार कर पार्टी को नुकसान पहुंचाने में जुटे हुए हैं. कुछ ऐसी ही स्थिति पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण जिले में देखने को मिल रही है. पूर्वी चम्पारण में जदयू के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिन्हा व जदयू सांसद बैद्यनाथ महतो पर तनाशाही व हिटलरशाही करने तथा अपमानित करने का आरोप लगाते हुए जदयू की मुख्य सहयोगी इकाई छात्र समागम के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों पुतला दहन किया. कार्यकताओं ने जिस तरह अपनी ही पार्टी के उक्त दोनों नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की, वह जदयू की वास्तविक स्थिति अवगत कराने के लिए काफी है. वैसे जदयू में गुटबाजी कोई नई बात नही है. पहले भी पार्टी के पुराने नेताओं की उपेक्षा करने व युवा कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का आरोप जिलाध्यक्ष सिन्हा पर लगता रहा है और इसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होती रही हैं. किन्तु इस बार की घटना जदयू के लिए काफी महंगी साबित हो सकती है. किसी भी दल के लिए युवा ही रीढ़ होते हैं और उनकी शक्ति की बदौलत ही पार्टियां कामयाबी की शिखर पर पहुंचती रही हैं. ऐसी स्थिति में युवा शक्ति ही बिखर जाए और गुटबाजी की शिकार हो जाए तो पार्टी की क्या हालत होगी, सहज अनुमान लगाया जा सकता है. जानकारी के अनुसार, खुलकर विरोध करने का यह मामला जदयू किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विनय सिंह के आवास पर प्रस्तावित संकल्प रैली की तैयारी को लेकर हुई बैठक से तूल पकड़ा. बैठक में मौजूद राज्य सभा सांसद आरसीपी सिन्हा ने अगर छात्र समागम के नेताओं की शिकायतें सुन ली होतीं तो शायद इस कदर हंगामा नहीं होता और जदयू जिलाध्यक्ष को इतनी फजीहत नही झेलनी पड़ती. यहां बता दें कि छात्र समागम के नेता अपने प्रदेश उपाध्यक्ष मनौवर आलम पर दर्ज हरिजन एक्ट मुकदमा से आरसीपी सिंह को अवगत कराने गए थे. उनका आरोप था कि सांसद बैद्यनाथ महतो ने ही छात्र समागम के प्रदेश उपाध्यक्ष पर हरिजन एक्ट का मुकमदा कराया है. सांसद सिंह ने उनकी बातें सुनने से इन्कार क्यों कर दिया, यह अलग विषय है किन्तु जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है उसके अनुसार, छात्र समागम के नेताओं का वहां पहुंचना जिलाध्यक्ष सिन्हा व सांसद बैद्यनाथ महतो को नागवार गुजरा और उनकी भावना को दरकिनार कर दिया.

दूसरी तरफ छात्र समागम के जिलाध्यक्ष अक्षय कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष तेजस्वी कुमार, नगर महासचिव नीरज सिंह, एमएस कालेज के महासचिव रोहित राज सोनू, जिला स्कूल के उपाध्यक्ष उमंग दुबे, विक्की सिंह, सौरभ तिवारी, अध्यक्ष कैसर खां, मुकेश कुमार, संतोष कुमार, राजवीर सिंह, यशवंत सिंह, मृणाल कुमार,किशन कुमार, प्रिंस राज, विंकी कुमार, गोलू राज, प्रशान्त कुमार, नितेश्वर कुमार व मुकेश आदि जदयू जिलाध्यक्ष सिन्हा पर अपमानित करने का आरोप लगाते हैं और बताते हैं कि छात्र समागम के नेताओं को सम्मान नहीं दिया जाता है. वे सिन्हा पर तनाशाही करने का आरोप भी लगाते हैं और कहते हैं कि केवल उनका इस्तेमाल करना जानते हैं. उधर युवा जदयू के नगर अध्यक्ष निर्भय श्रीवास्तव भी जिलाध्यक्ष सिन्हा पर पार्टी से युवाओं को दूर करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि छात्र समागम के नेताओं के साथ जो व्यवहार किया गया उसकी जितनी भी निन्दा की जाए वह कम है. अगर यही स्थिति रही तो पार्टी से युवाओं का पलायन कोई नहीं रोक सकेगा. पार्टी के एक और युवा नेता व युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष बबन कुशवाहा का आरोप तो काफी निराला है. उनका आरोप है कि किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के आवास पर हुई बैठक में उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया. जबकि उन्हें बैठक में आमंत्रित किया गया था. बुलाकर फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. कुल मिलाकर पूर्वी चम्पारण में जदयू की युवा शक्ति काफी बिखर गई है और इसका असर मुख्यमंत्री की प्रस्तावित सकंल्प रैली में पड़ सकता है. यहां यह भी बता दें कि अभी तक विपक्षी नेता ही पुतला जलाते थे और विरोध में सड़क पर उतरते थे. किन्तु इस बार उल्टा हो गया और सत्ताधारी दल के नेता के खिलाफ सत्ताधारी दल के नेता सड़क पर उतर गए. ■

रंगदारों की गिरफ्त में पश्चिमी चम्पारण

अवधेश कुमार शर्मा

पश्चिमी चम्पारण जिला इन दिनों रंगदारों, अपराधियों व नक्सलियों की गिरफ्त में है. यहां कब किस से रंगदारी मांगी जाएगी और किसकी हत्या हो जाएगी यह कहना काफी मुश्किल है. हाल ही में जिला परिषद के उपाध्यक्ष व राजद नेता मो. गाजी की हुई दिन दहाड़े हत्या का जख्म अभी भरा भी नही था कि नरकटियागंज में नगर परिषद के मुख्य पार्षद सुनील कुमार से एक बार फिर पांच लाख रूपये की रंगदारी मांग कर अपराधियों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है. पुलिस अभी तक इस मामले में कोई खास सफलता हासिल नही कर सकी है. इस वजह से लोगों में दहशत का माहौल है. यहां बता दें कि पश्चिमी चम्पारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पांच वर्षों के अन्दर 470 लोगों की हत्याएं हुई हैं और कई दर्जन लोगों से रंगदारी मांगी जा चुकी है. केवल 2013 में यहां 52 हत्याएं हुई हैं. बीते 22 नवम्बर को नरकटियागंज में रात में नगर परिषद के मुख्य पार्षद सुनील कुमार के मोबाइल पर देवराज नामक व्यक्ति ने जिस तरह से स्वयं को पीपुल्स वार ग्रुप का सदस्य बताकर पांच लाख रूपये रंगदारी मांगी और नहीं देने पर उनके घर को बम से उड़ा देने की धमकी दी, उससे साफ हो गया कि यहां रंगदारों का नेटवर्क काफी मजबुत है. रंगदारी मांगे जाने की घटना के तुरन्त बाद अगर सुनील कुमार ने अपने भाई को फोन पर इस घटना की जानकारी नहीं देते और घर की तलाशी नही होती तो स्थिति और खराब हो जाती. तलाशी के दौरान सीढ़ी के नीचे लकड़ी पर एक प्लास्टिक में घड़ी लगा एक बम रखा हुआ मिला जिसे जेनरेटर की पानी टंकी में डाल दिया.

घटना की सूचना शिकारपुर थाना की पुलिस को भी दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी तो कर दी किन्तु अभी तक रंगदारों की गिरफ्तारी नही हो सकी. मौके पर एसपी अभियान राजेश कुमार, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार भी पहुंचे थे. इससे पूर्व भी सुनील कुमार से 20 लाख रुपये रंगदारी मांगी जाचुकी है.इसके अलावा बेतिया स्थित अवर निबंधन कार्यालय के पास पूअर पीपुल्स वार नामक संगठन द्वारस बम रखने व वर्ष 2000 में विधायक सतीशचन्द्र दुबे को धमकी देने की घटना घट चुकी है. दूसरी तरफ राजद नेता मो. गाजी की हत्या जिस तरह से दिन दहाड़े कर दी गई और पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति करती रही. कुल मिलाकर पश्चिमी चम्पारण जिला पूर्ण रूप से रंगदारों व अपराधियों की चपेट में है. ■

feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

नीतीश पर बरसे अशोक

राष्ट्रीय जनता दल ने निर्मली विधानसभा सम्मेलन बड़े ताम-झाम के साथ शुरू किया. उक्त सम्मेलन का उद्घाटन राजद के कमिश्नरी प्रभारी पूर्व मंत्री अशोक सिंह ने किया. उन्होंने कहा कि लालूजी को साजिश के तहत फंसाया गया. नीतीश कुमार राजनीति के नटवर लाल हैं. बिहार की जनता ने बिहार की बेहतरी के लिए जनादेश दिया था, लेकिन अपने आठ वर्ष के अधिक शासन में सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. इतना ही नहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि इस निकम्मी और जनविरोधी सरकार के शासन काल में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है. भ्रष्टाचार इस सरकार का संस्कार बन गया है. सात वर्षों में भ्रष्टाचार में बहुत इजाफा हो गया. दिशाविहीन, संवेदनहीन सरकार में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, इस सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं.

– जुबैर अंसारी

प्रेरण सत्र का उद्घाटन

इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा द्वारा सीतामढ़ी कृषि विज्ञान केंद्र को डिप्लोमा एवं पीजी डिप्लोमा हेतु कार्यक्रम अध्ययन केंद्र बनाया गया है. वर्तमान समय में केंद्र को मुख्य रूप से कार्बनिक खेती एवं कुक्कुट पालन का सर्टिफिकेट कोर्स, डेयरी तकनीक में डिप्लोमा, प्लांट प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएट की स्वीकृति मिली है. उक्त विषयों में अब तक 88 छात्रों ने नामांकन लिया है. उक्त विषय से संबंधित प्रेरण सत्र का उद्घाटन केंद्र के अध्यक्ष नवल किशोर राय ने दीप प्रज्वलित कर किया. मौके पर इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. एसएस, उप क्षेत्रीय निदेशक डॉ. एसके पांडेय, सचिव सुदिष्ट कुमार, वैज्ञानिक राम ईश्वर प्रसाद, डॉ. सच्चिदानंद प्रसाद, मनोहर पंजिकार, डॉ. किंकर कुमार, डॉ. दीपक सिंह समेत अन्य थे.

– गोविंद कुमार

आवागमन मुश्किल

सीतामढ़ी-शिवहर राष्ट्रीय पथ संख्या - 104 पर स्थित धनकौल पुल आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. वर्ष 1906 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा निर्मित लोहे का पुल अब अंतिम मुकाम पर पहुंच गया है. सीतामढ़ी जिले को शिवहर-मोतिहारी तक जोड़ने वाले मुख्य पथ में मौजूद इस पुल की आवश्यक मरम्मत भी असंभव बनी है. मरम्मत के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों की लूट तो की जाती है, परंतु पुल को नया जीवन देने की बजाए मामूली मरहम पट्टी कर छोड़ दिया जाता है. स्थानीय नंद किशोर झा, वेद प्रकाश चौधरी, जय प्रकाश शर्मा व देव नारायण साह समेत अन्य ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन से उक्त पुल का काया कल्प कराने की मांग की है.

– राम नारायण

कांग्रेस पदाधिकारी हुए सम्मानित

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय ललित आश्रम में जिला पार्टी कमेटी की एक बैठक हुई. जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पूर्व के प्रस्ताव पर चर्चा की गई. साथ ही पार्टी की प्रदेश कमेटी में नव नियुक्त पदाधिकारी मधुरेंद्र कुमार सिंह, मो. परवेज आलम, मो. असद, विजेंद्र यादव, राज कुमार साह व सुरेश रजक को उपाध्यक्ष सीताराम झा, रामबली महतो, सत्येंद्र कुमार तिवारी, हिफुजुर रहमान, मो. शहनशाह व बच्चा मिश्र ने माला पहना कर स्वागत किया. बैठक में वीरेंद्र कुशवाहा, शत्रुघ्न मिश्र, ओमप्रकाश झा, ताराकांत झा, नागेंद्र पासवान, महेश माझी, मणिभूषण कुमार, जयकृष्ण पूर्वे, संजय कुमार, हरदेव पाठक, विजय कुमार सिंह, डॉ. अनवर हुसैन व महेश्वर गिरी समेत अन्य थे. ■

– ब्रजेश

दमा, कष्टदायक रोग
Ariskon Pharma Pvt.Ltd.
ACOBA CAP/SYP/INJ
Carbo-XT
AREX
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of Ariskon Pharma

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : मेरे ससुर जी के आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है और वे ऑपरेशन से बचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में CINERARIA ...

... भी समर्थ नहीं हो पाता हूं। स्थायी उपचार बतायें। सुधीर सिंह, जयपुर

Breastriim Oil का सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से सीना का विकास ...

REPL

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें 9304291051

किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें।

REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

फंसे या बचे नीतीश

पृष्ठ 17 का शेष

श्याम बिहारी सिन्हा और आर के दास के बयान पर किसी को सजा होगी और कोई बाहर घूमेगा ऐसा कैसे हो सकता है? सीबीआई कहती है कि नीतीश कुमार और शिवानंद के खिलाफ जांच नहीं हुई. हमलोगों का भी तो यही प्वाइंट है कि अगर पैसे के लेनदेन की बात अनुसंधान के दौरान आई तो ऐसी क्या परिस्थिति थी कि इन दोनों से कम से कम पूछताछ भी नहीं हुई. श्री सिन्हा कहते हैं कि न्यायपालिका पर हमलोगों को पूरा भरोसा है कि इस मामले में न्याय जरूर होगा. पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं.सीबीआई पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए वह कहते हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई नीतीश कुमार को बचा रही है. दरअसल कांग्रेस बिहार में राजनीतिक जमीन की तलाश में है और उसे यह गलतफहमी हो गई है कि नीतीश कुमार का साथ लेकर वह लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है. इसी लालच में सीबीआई की मदद से नीतीश कुमार को बचाया जा रहा है. रांची हाईकोर्ट में सीबीआई द्वारा दायर हलफनामा इसका जीता जागता प्रमाण है. श्री चौबे कहते हैं कि यह अजीब बात है कि सीबीआई कहती है कि पैसे का लेन देन हुआ और फिर खुद कहती है कि उसने जांच नहीं की. अगर जांच करने वाली एजेंसी ही जांच कर सबूत नहीं जुटाएगी तो फिर यह काम आखिर कौन करेगा. चौबे का कहना है कि इस मामले को वह जनता के बीच लेकर जाएंगे ताकि बिहार की भोली भाली जनता भी नीतीश कुमार की सच्चाई से वाकिफ हो सके. इसी तरह की बात राजद विधायक सम्राट चौधरी भी कहते हैं. श्री चौधरी का कहना है कि सीबीआई ऐसे ही अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है और ताजा हलफनामे से साफ है कि इस जांच एजेंसी ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है. चौधरी कहते हैं कि लालू प्रसाद को किस साजिश के तहत जेल भेजा गया है, इसे बिहार की जनता समझ रही है. एक को जेल और दूसरे से पूछताछ भी नहीं. सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और शिवानंद इस मामले में दोषी है पर जांच की जो सामान्य प्रक्रिया है उसका तो पालन हो. ऐसा न करके सीबीआई अपनी ही साख पर बट्टा लगा रही है. इन बातों के परिपेक्ष्य में देखा जाए तो लगता है कि सीबीआई ने अपने हलफनामे से इस मामले को साफ करने के बजाय उलझा दिया है. अब तो यह 13 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि अदालत इस मामले की गुत्थी को सुलझा पाने में सफल कितना रही?■

feedback@chauthiduniya.com

बागमती में अवैध नाव परिचालन बना जानलेवा

नेपाली भू-भाग से निकल कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली बागमती नदी के तांडव का इतिहास कोई नया नहीं है. सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र के अख्ता, जमुआ, फुलवरिया एवं ढेंग घाट पर अब तक कई नाव दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. परंतु ढेंग घाट को छोड़कर अन्य घाटों पर अब तक पुल निर्माण नही कराया जा सका है. नतीजतन सैकड़ों लोग अलग-अलग हुई नाव दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं. इतने के बाद भी प्रशासन की तंद्रा भंग होने का नाम नही ले रही है....

विनोद कुमार

सूबे बिहार की सरकार ने बागमती नदी से प्रतिवर्ष होने वाली भारी तबाही से निजात को लेकर पिछले तकरीबन चार दशक से अधूरे पड़े बागमती तटबंध के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया. दूसरी ओर घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ढेंग घाट पर पुल निर्माण करा कर जनता की प्रशंसा बटोरी. परंतु हजारों की आबादी के आवागमन के मुख्य मार्ग को अब भी भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है. नतीजा है कि सैकड़ों लोग जान की बाजी लगा कर नाव से यात्रा करने को विवश हैं. वहीं दूसरी ओर बिना प्रशासनिक सहमति के दादा सरीखे लोगों द्वारा अवैध रूप से नाव का परिचालन कर प्रतिदिन हजारों रुपये की अवैध वसूली कर लोगों को परेशान किया जाता है. प्रशासनिक सक्रियता का आलम है कि उक्त नाव परिचालन की सूचना के बावजूद प्रखंड अथवा जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाने से परहेज किया जा रहा है. पूर्व में हुईं नाव दुर्घटना के प्रति प्रशासनिक संवेदना का आलम है कि 5 साल बाद भी घटना की जांच भी स्थानीय पुलिस पूरी नहीं कर सकी है. बीते 11 नवंबर को जब बैरगनिया थाना क्षेत्र के अख्ता घाट पर नाव दुर्घटना की सूचना मिली तो एक बार फिर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. यह तो महज संयोग ही था कि घटना में एक ही व्यक्ति असमय काल कवलित हुआ. बताते चलें कि वर्ष 2009 में लालबकेया नदी के फुलवरिया घाट पर नाव दुर्घटना हुई थी, जिसमें तकरीबन 70 लोग पानी के तेज बहाव में डूब गए थे. बड़ी मशक्कत के बाद भी सभी की तलाश नहीं निकाली जा सकी थीं. मामले में एक प्राथमिकी (143/09) दर्ज की गई थी. घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने घटना स्थल पहुंच कर घड़ियाली आंसू बहाने से परहेज नही किया था. परंतु समय गुजरने के साथ ही तमाम कसमें वादे पानी की तरह बह गए. अभी इस घटना को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि जुलाई 2010 में अख्ता घाट पर नाव डूब गई जिसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी. परंतु इस बार प्रशासन ने घटना के संबंध में प्राथमिकी तक दर्ज कराना मुनासिब नहीं समझा. बताया जाता है कि क्षेत्र में नाव माफियाओं की पकड़ के सामने प्रशासनिक तंत्र बौना है. चाहे घटना कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मामले में प्रशासनिक सक्रियता संभव नही हो पाती है.

सरकारी अथवा प्रशासनिक स्तर पर कठोर कार्रवाई नहीं हो पाने के कारण नाव माफियाओं की दादागिरी थमती नहीं है. इसका खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता है. बताया जाता है कि जब कभी प्रशासनिक स्तर पर चहल कदमी की जाती है तो नाव माफियाओं द्वारा नया कदम उठा लिया जाता है. आनन-फानन में नदी घाट पर चचरी पुल का निर्माण कर अवैध वसूली की प्रक्रिया को लागू रखा जाता है. कारण कि प्रतिदिन कम से कम 5-7 हजार रुपये तक की वसूली उक्त घाटों से की जाती है. किसी की मजाल नहीं कि बिना मनमाना भाड़ा चुकाए चचरी से पार हो ले. अख्ता नाव दुर्घटना मामले में चौकीदार शेख फखरुदीन के बयान पर प्राथमिकी (148/13) दर्ज तो कर ली गई है परंतु इस मामले में किसी पर कार्रवाई भी होगी यह लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है. वैसे वर्तमान डीएम डॉ. प्रतिमा एवं एसपी पंकज सिन्हा की सजगता पर भरोसा करने वाले लोग कहते हैं कि अबकी बार दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा. घटना के तत्काल बाद ही थानाध्यक्ष रीता कुमारी ने मामले में दोषी की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी. घटना पर स्थानीय भाजपा विधायक मोतीलाल प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता जटाशंकर आत्रेय, रामबाबू प्रसाद, मालती देवी, भाई ओम प्रकाश, ओम प्रकाश सुमन, देवेंद्र सिन्हा, दीपक कुमार दीप समेत अन्य ने गहरा दुख व्यक्त किया है. मामले में आगे क्या होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. परंतु अब क्षेत्र के लोगों में इस समस्या को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है. लोगों का कहना है कि अब तक वोट की खातिर लंबी-चौड़ी बातें करने वाले प्रतिनिधियों ने केवल ठगने का काम किया है. आगामी लोकसभा चुनाव में वोट के सौदागरों से एक-एक लाश का हिसाब लिया जाएगा, जो सरकारी, प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता के कारण बागमती की धारा में बहती रही है. अगर चर्चाओं में दम है तो निश्चित तौर पर इस बार चुनावी समर में आने वाले प्रत्याशियों के लिए बैरगनिया प्रखंड का नदी घाट परेशानी का सबब बन सकता है. ■

चचरी से पार होते लोग

feedback@chauthiduniya.com

आरा (भोजपुर) सुधार गृह में पिछले दिनों चार बच्चे सुरक्षाकर्मी को चाकू दिखाकर भाग गए. हालांकि बाद में वे पकड़े भी गए. सुधार गृहों के बाहर बच्चों के अपराधी बनने का खतरा बना रहता है तो अंदर यौन शोषण का घिनौना काम भी चलता है. कुछ माह पहले की घटना है जब पटना के बाल सुधार गृह के कुछ दबंग बाल कैदियों ने राजेश कुमार नाम के एक कैदी की हत्या कर दी थी.

यातना गृह में बदल रहे बाल सुधार गृह

राजीव कुमार

सवाल है कि बिहार में बाल सुधार गृह यातनागृह में क्यों बदलते जा रहे हैं? सरकार इन बच्चों को लेकर क्यों नहीं ठोस कदम उठा पाती है? लालफीते में किशोर न्याय कानून क्यों जकड़ गया है? इनमें ज्यादातर सुधार गृहों में न तो बचपन सुधर रहा है और न ही भविष्य संवर रहा है. सुधार गृहों की कहानी अक्सर अखबारों की सुर्खियां बनती है, लेकिन इस पर सुशासन की सरकार मानों लाचार नजर आती है. कानूनी प्रावधानों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अनगिनत जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं.

बाल सुधार गृह भोजपुर के बड़े बाल कैदियों द्वारा जबरन पैसा वसूले जाने पर बमुश्किल राजा पासवान ने दो सौ रुपये अपने एक परिजन से मांगकर दिए और कहा कि अब इससे अधिक नहीं हो पाएगा. बस इतनी सी बात पर अधिक उम्र के कैदियों ने राजा पासवान को पीट–पीटकर कर अधमरा कर दिया. उसी रात को राजा की जमकर पिटाई की गई. जिससे राजा को असहनीय पीड़ा हुई. उसने किशोर न्याय परिषद (भोजपुर) को एक पत्र लिखा. पत्र में सुधार गृह के अधीक्षक के इशारे पर तोता खान, गुड्डू, राजा बाबू एवं मोहन महतो को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया. जिन्होंने उसका जीना दूभर कर रखा है. कुछ इसी तरह की अहसनीय पीड़ा से हरिशंकर को भी गुजरना पड़ा था. जब वह रात भर दर्द से कराहता रहा था, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया. कुछ ऐसी ही घटना किशोर मुन्ना पाण्डेय नाम के एक बाल कैदी के साथ घटी. किशोर को राजाबाबू, कमलेश, शंकर, कृष्णानन्द आदि ने पीटा था. किशोर के एक मित्र को अजय ने पीटकर लहुलुहान कर दिया. सिर में काफी चोटें आई थीं. भयभीत किशोर एवं अजय के एक और मित्र सोनू को भी धमकाया गया था. सोनू ने इस बाबत किशोर न्याय परिषद से गुहार लगाते हुए पत्र लिखा है कि मेरी जान को खतरा है इसलिए मुझे जेल भेज दिया जाए ताकि मेरी जान की रक्षा हो सके. यह कहानी सिर्फ राजा, किशोर या सोनू की ही नहीं है, बल्कि दीपक कहार, हरिशंकर राय जैसे बाल सुधार गृह (भोजपुर) में बंद 40 बच्चों के साथ यह हर रोज की घटना है.

कभी बाल कैदी डोमा की निर्मम हत्या कर दी गई थी तब भोजपुर सुधार गृह अखबारों की सुर्खियों में आया था. घटना की जानकारी विभाग में बैठे ऊपर के लोगों को भी होती रही है, लेकिन आज तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई होते नहीं देखा गया. आरा (भोजपुर) सुधार गृह में पिछले दिनों चार बच्चे सुरक्षाकर्मी को चाकू दिखाकर भाग गए. हालांकि बाद में वे पकड़े भी गए. सुधार गृहों के बाहर बच्चों के अपराधी बनने का खतरा बना रहता है तो अंदर यौन शोषण का घिनौना काम भी चलता है. कुछ माह पहले की घटना है जब पटना के बाल सुधार गृह के कुछ दबंग बाल कैदियों ने राजेश कुमार नाम के एक कैदी की हत्या कर दी थी. पिछले दिनों जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकतर बच्चे सुधार गृह को जेल ही मानते हैं. बाल सुधार गृह में बच्चों के प्रति न तो अधिकारियों में संवेदनशीलता देखी जाती है और न ही सरकार में इसके प्रति चिन्ता. बाल सुधार गृह से बच्चे भागते हैं. गुट बनाकर एक दूसरे पर हमले करते हैं. मारपीट में घायल होते हैं. कई बार वे सुरक्षाकर्मियों पर भी हमले करते हैं. दिन में सुधार गृह में समय काटते हैं और रात में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं. नियमत: 18 वर्ष के बाल कैदियों को सुधार गृह में रहने की व्यवस्था है, लेकिन जानकारी के अनुसार इससे अधिक उम्र के कैदी भी फर्जी प्रमाणपत्र के साथ सुधार गृह में रहते हैं और उत्पात मचाते हैं. फर्जी प्रमाणपत्र द्वारा सुधार गृह में रह रहे तय उम्र से बड़े बाल कैदियों से इन्कार नहीं किया जा सकता. बड़े लड़के बात–बात पर मासूमों के साथ गाली एवं लात घूंसों की बौछार करते रहते हैं. इस बाबत समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पटना एवं आरा में वास्तविक उम्र से काफी कम उम्र के प्रमाणपत्र देने वाले बच्चों की संख्या भी है. फर्जी प्रमाणपत्र देने वाले स्कूल के प्रभारी शिक्षकों को जांच में दोषी पाए जाने के बाद हटाया गया है. साथ ही ऐसे शिक्षकों को जेल की हवा खानी पड़ी है. पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, मुंगेर, पूर्णिया, बेतिया, छपरा, दरभंगा भागलपुर एवं गया में बाल सुधार गृह संचालित है, प्रत्येक सुधार गृह में 50 बच्चों को रखने की व्यवस्था है. बाल सुधार गृह के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्थानीय स्कूल के दो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है. मैट्रीक व इंटरमीडिएट या प्रतियोगी परी–क्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को ट्यूशन भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है. साथ ही वोकेशनल प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है. प्रत्येक बाल कैदी को वर्ष में एक बार दो हजार रुपये मूल्य के दो जोड़े कपड़े, स्वेटर आदि दिए जाते हैं. भोजन मद में प्रतिमाह 1200 और चिकित्सा मद में दो सौ रुपये देने का प्रावधान है. मनोरंजन के लिए टीवी, कंप्यूटर, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन एवं जूडो कराटे के प्रशिक्षण की सुविधा तथा भोजन में पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था है, लेकिन सुधार गृह में मेनू के हिसाब से भोजन नहीं मिल पाता है, बाकि सभी सुविधाओं की भी स्थिति जर्जर ही होती है. भोजपुर सुधार गृह के कई बच्चे टीबी के मरीज बन चुके हैं, लेकिन उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है. इलाज हेतु बच्चों से पैसे वसूले जाते हैं. सड़ी–गली सब्जी एवं गंदे परिवेश से बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती है. बिजली की स्थिति भी ठीक नहीं रहती है जिससे गर्मी के दिनों में बच्चों को परेशानियों से दो–चार होना पड़ता है. किशोर न्याय परिषद समय से फैसले नहीं सुनाती है जिसकी वजह से बच्चों को वर्षों यातनाएं सहनी पड़ती हैं. पानी, खेलकूद, सफाई, कपड़े, साबुन, सर्फ आदि की स्थिति भी करीब–करीब बुरी ही होती है , जिससे बच्चों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है.

आजादी के 53 वर्षों के बाद इन बदनसीब बच्चों के लिए सरकार ने सन 2000 में किशोर न्याय अधिनियम लाया. किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में तीन सदस्यीय बोर्ड बाल कैदियों के मामलों की सुनवाई करता है. बाल सुधार गृह में ही शिविर लगाकर बच्चों को न्याय दिया जाता है. चार माह में केस का निपटारा कर देना होता है. अधिकतम कैद की सजा तीन वर्ष तक हो सकती है. बाल कैदियों के साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की जा सकती है. राज्य में 38 न्याय परिषद और 28 बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है. किशोर न्याय परिषद सुधार गृह में जाकर बाल कैदियों के मामले में फैसला सुनाता है. बताया जाता है अधिकतर मामलों में पुलिस आरोपपत्र समय पर दाखिल नहीं करती है जिससे समय पर रिहाई नहीं हो पाती है. पिछले दिनों संसद ने बाल संरक्षण बिल 2012 भी पारित कर दिया है इसके दायरे में 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चे एवं बच्चियों को शामिल किया गया है. इसमें 6 तरह के यौन बर्ताव के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है. इसके तहत कम से कम दस साल की सजा और जुर्माने के अलावा अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. जहां तक संभव होगा ऐसे मामलों की जांच का काम महिला पुलिस अधिकारी ही करेगी और वह इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे की अधिकारी नहीं होगी. बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार को भी विधेयक के दायरे में लाया गया है. कानून में घर के भीतर या बाहर या होटल में कहीं भी कोई घटना होती है तो कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन यह मानों किताबी बातें है. किसी भी राज्यस्तरीय समाज कल्याण विभाग की बैठक में जिला स्तर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहा करता है. जिससे आपसी संवाद भी नहीं होता है. हाल में मुफ्फरपुर के सुधार गृह में बंद एक किशोरी ने वहां के दो महिला कर्मचारियों पर यौन व्यापार कराने का सनसनीखेज आरोप लगाया है. वह अपने ऊपर हो रहे अन्याय को लेकर गुहार लगा रही है, लेकिन ऐसी अनगिनत लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटनाएं घटती रहती हैं और दबी रह जाती हैं. इसके साथ ही इससे जुड़े अनगिनत सवाल मुंह बाए खड़े हो जाते हैं.

बाल सुधार गृह में बच्चों के प्रति न तो अधिकारियों में संवेदनशीलता देखी जाती है और न ही सरकार में इसके प्रति चिन्ता. बाल सुधार गृह से बच्चे भागते हैं. गुट बनाकर एक–दूसरे पर हमले करते हैं. मारपीट में घायल होते हैं. दिन में सुधार गृह में समय काटते हैं और रात में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं. नियमत: 18 वर्ष के बाल कैदियों को सुधार गृह में रहने की व्यवस्था है, लेकिन इससे अधिक उम्र के कैदी भी फर्जी प्रमाणपत्र के साथ सुधार गृह में रहते हैं और उत्पात मचाते हैं.

सवाल है कि बिहार में बाल सुधार गृह यातनागृह में क्यों बदलते जा रहे हैं? सरकार इन बच्चों को लेकर क्यों नहीं ठोस कदम उठा पाती है? लालफीते में किशोर न्याय कानून क्यों जकड़ गया है? इनमें ज्यादातर सुधार गृहों में न तो बचपन सुधर रहा है और न ही भविष्य संवर रहा है. सुधार गृहों की कहानी अक्सर अखबारों की सुर्खियां बनती है, लेकिन इस पर सुशासन की सरकार मानों लाचार नजर आती है. कानूनी प्रावधानों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अनगिनत जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं. समाज को भी सोचना होगा कि उसकी अगली पीढ़ी के अपराध की अंधी गलियों में भटक जाने पर समाज का कितना अहित हो रहा है और फिर उन्हें दोबारा अपराध के रास्ते पर ही चलने को क्यों मजबूर किया जा रहा है?

feedback@chauthiduniya.com

अररिया से अर्थव्यवस्था बिगाड़ने की साजिश

अजातशत्रु अग्रवाल

भारत–नेपाल अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित अररिया जिले में भारतीय अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की चौतरफा साजिश हो रही है. इसके लिए सक्रिय नेटवर्क का सहारा लिया जा रहा है. इस नेटवर्क में शामिल असमाजिक तत्वों के द्वारा विदेशी घुसपैठ, जाली नोटों का प्रवाह, पशुधन तस्करी एवं नशाखुरानों का खेल खेला जा रहा है. सनद रहे कि अररिया जिले का उत्तरी छोर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल को छूता है, वहीं पूर्वी क्षेत्र से किशनगंज जिले की सीमा लगती है. किशनगंज जिले का पूर्वी हिस्सा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से जुड़ता है. सूत्रों के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल होते हुए किशनगंज और वहां से अररिया जिले में भी होती है. इस बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं अन्य राजनीतिक संगठनों के द्वारा समय–समय पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस पर अंकुश लगाने की मांग जोरदार ढंग से की जाती रही है. सूत्रों की मानें तो बांग्लादेशी घुसपैठ इस सीमावर्ती क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है जिसके कारण असमाजिक एवं

राष्ट्रविरोधी गतिविधियां पर्दे के पीछे से खेली जाती है जिसका खामियाजा भारतीय नागरिकों को विभिन्न आपराधिक वारदातों जैसे चोरी, डकैती, राहजनी, लूटमार एवं हत्या जैसे जघन्य अपराधों के रूप में भुगतना पड़ता है. इस विदेशी घुसपैठ के कारण भारतीय मतदान भी प्रभावित होने की बात राजनीतिक जानकार बताते हैं. इस विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस सीमावर्ती क्षेत्र में सशस्त्र सीमाबल एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती भी की गई है. उनके द्वारा सक्रिय रूप से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास भी किया जाता है लेकिन विदेशी घुसपैठ कराने से जुड़े लोग मौके की ताक में रहते हैं और जिस वक्त भी उन्हें अवसर प्राप्त होता है वे सक्रिय हो उठते हैं.

भारतीय अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में जाली नोट का खेल भी खेला जाता है. इस खेल में बांग्लादेश के साथ–साथ नेपाल की जमीन का उपयोग भी मौकापरस्त लोग बखूबी शामिल होते हैं. जानकारों की मानें तो इस जाली नोट के प्रवाह में भारतीय क्षेत्र के सफेदपोश लोगों की भूमिका भी काफी मायने रखती है. जाली नोट का प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों के जरिए कराया जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाली एवं सही नोट की पहचान करने में असमर्थ होते हैं जिसका लाभ इस धंधे से जुड़े लोग उठाते हैं. कम वक्त में ज्यादा लाभ अर्जित करने की मंशा रखने वाले लोगों को इस धंधे से जुड़े लोग इस्तेमाल करते हैं. उन्हें भौतिक सुख सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने का लालच देकर उन्हें इस कुत्सित कार्य में शामिल कर लेते हैं. जानकारों के अनुसार एक लाख के जाली नोट के एवज में पच्चीस हजार के सही नोट का भुगतान लिया जाता है. इतने बड़े अन्तर का लालच उन्हें गुमराह कर देता है. जाली नोट के प्रवाह को रोकने के लिए भारतीय पुलिस के साथ–साथ सेना के जवान भी समय–समय पर सक्रिय रूप से कार्य करते हुए कई बार छोटे गुर्गों को पकड़ने में सफल होते हैं. इस जाली नोट के खेल में शामिल लोगों की पहुंच उनके सरगन–ाओं तक दूर–दूर तक नहीं होती है जिस कारण भारतीय एजेंसियां इस धंधे में शामिल बड़े लोगों के गिरेबां तक नहीं पहुंच पाती हैं और यह धंधा फलता–फूलता जाता है. भारतीय बैंकों के द्वारा जाली एवं असली नोट की पहचान के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के हाट–बाजार में अभियान चलाकर लोगों को सक्रिय तो किया जाता है लेकिन इसका पूर्णत: लाभ अभी तक लोगों को नहीं मिल पाता है. मिली जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं. अर्थ व्यवस्था से जुड़े लोगों की मानें तो प्लास्टिक के नोट के जाली नोट बनाने में काफी कठिनाई है अगर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्लास्टिक के नोटों का चलन आम आवाम के लिए प्रारंभ हो जाय तो लोगों को बहुत हद तक इस जाली नोट की समस्या से छुटकारा मिल सकता है. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में काफी पहले से प्लास्टिक के नोटों का चलन हो रहा है. वर्तमान में लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक आ चुका है और इस वक्त जाली नोटों के प्रवाह की संभावना काफी बढ़ जाती है. समय रहते अगर इस जाली नोटों के खेल पर पूर्णत: अंकुश न लगाया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता. असामाजिक तत्वों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए पशुधन तस्करी के कार्य को अंजाम दिया जाता है. इसके जरिए भारतीय पशुओं को पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश तक पहुंचाने के लिए बड़ा नेटवर्क काम करता है. इस नेटवर्क से जुड़े लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और फिर इस पशु को अपने सशक्त नेटवर्क के जरिए विदेश पहुंचाते हैं. पशुधन तस्करी के कारण इस सीमावर्ती क्षेत्र में पशुओं की कमी होने का रोना कृषक वर्ग रोते रहते हैं. इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पशुओं की कमी होगी तो कृषि कार्य प्रभावित होगा ही और इसका बहुत ही खराब प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है . ऐसे समय में इस बात आवश्यकता है कि इसे रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएं और सख्त कदम उठाए जाएं. भारतीय अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का अन्य प्रयास नशोखारी के जरिए चल रहा है. युवा पीढ़ी को नशे के आगोश में लाने का खेल भी खेला जा रहा है. नशे की गिरफ्त में आने के उपरांत लोग अपना विवेक खो बैठते हैं इस कारण वे सही और गलत कार्य में फर्क भी नहीं कर पाते हैं जिसका खामियाजा लोगों को बड़े स्तर पर भुगतना पड़ता है. समय रहते इस दिशा में भी सक्रिय प्रयास की जरूरत समाज एवं राष्ट्रहित में जरूरी ही नहीं अतिआवश्यक भी है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

09 दिसंबर– 15 दिसंबर 2013

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश– उत्तराखंड

पश्चिमी यूपी: दंगों के बाद गन्ना हुआ सियासी

संजय सक्सेना

मुजफ्फरनगर दंगों की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वोट बैंक का गन्ना काटने की जुगाड़ में लग गए. मेरठ में एक चीनी मिल के उद्घाटन के दौरान सीएम ने गन्ना किसानों को खूब पुचकारा. हालांकि, सपा के पहले के वादों और लोकसभा चुनाव को देखकर सीएम के गन्ना किसानों के प्रति तथाकथित प्रेम के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये सब सिर्फ सियासी चाल है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचे. वहां उन्होंने कई घोषणाएं कीं, तो वोट बैंक साधने के लिए बयानबाजी का भी सहारा लिया. यह दौरा उनके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा. पिछले दौरे की कड़वाहट भी इस दौरे से काफी हद तक कम हो गई होगी. पूर्व में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर दंगों के बाद दंगा पीड़ितों का हाल लेने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पधारे थे, तब उनका स्वागत काले झंडों से हुआ था. उनकी सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे. आम राय यही थी कि सरकार की कमजोरी की वजह से दंगा भड़का था. जाट और मुसलमानों के बीच हुए झगड़े में दोनों ही पक्षों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे. कांग्रेस–बसपा ने भी अखिलेश सरकार को घेरते हुए दंगे की आग में घी डालने का काम किया था. सपा विरोधियों ने ही नहीं, बुद्धिजीवियों ने भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया था. यहां तक कहा गया कि समय रहते अगर सरकार सही कदम उठा लेती तो मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, वह नहीं होता. सपा को अपना खेल बिगड़ता दिखा तो उसने मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए अनाप–शनाप फैसले लिए, जिससे हालात और खराब हो गए. यहां तक कि अखिलेश सरकार की भेदभाव पूर्ण कार्यशैली से खफा देश के उच्चतम न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ गया. कोर्ट दंगों की जांच अपनी निगरानी में करा रहा है तो अखिलेश सरकार के ऐसे फैसलों को पलटने में भी देर नहीं कर रही है, जो किसी एक वोट बैंक को खुश करने के लिए लिए जा रहे हैं.

मुजफ्फनगर दंगों से अखिलेश सरकार की फजीहत देश में ही नहीं हुई, यह मसला अंतरराष्ट्रीय चर्चा में भी रहा, लेकिन समाजवादी नेताओं ने हार नहीं मानी है. पहले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बरेली में हुंकार भरी. इसके बाद अखिलेश यादव ताल ठोंकने लगे. मौका मिलते ही बीते दिनों एक बार फिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेरठ पहुंच गए. उन्होंने एक दिन के दौरे में अनेक गोटें बैठाईं तो एक दिन पूर्व मेरठ निवासी और वाराणसी में पोस्टिंग के दौरान दबंगों की गोली में मारे गए डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की वजह से मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था को लेकर मीडिया और विरोधियों के सवालों का जबाव देना मुश्किल हो गया. यादव ने वाराणसी में डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की हत्या पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हुए हत्यारों को शीघ्र पकड़ने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए. इसके साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा मृतक की पत्नी को योग्यतानुसार सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की.

सीएम ने डिप्टी जेलर के परिवार के साथ सहानुभूति दिखाई तो उनके निशाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोटर विशेष रूप से रहा. दंगा पीड़ितों को लुभाने और गन्ना किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वह काफी आगे तक जाते दिखाई दिए. दंगों की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सीएम वोट बैंक का गन्ना काटने की जुगाड़ में लग गए. मेरठ में एक चीनी मिल का उद्घाटन करके युवा सीएम ने यह जताने की कोशिश की कि उनकी सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है. एक तरफ तो उन्होंने अपनी सरकार की मंशा बताते हुए कहा कि गन्ना किसानों को किसी प्रकार का संकट न हो, चीनी मिलें भी चलें और चीनी के दाम भी कम रहें. वहीं, केन्द्र सरकार पर आरोप मढ़ने से भी वह नहीं चूके और कहा कि केन्द्र द्वारा चीनी के आयात पर रोक न लगाकर चीनी उद्योग पर चोट पहुंचाने का काम किया है. पिछली सरकार ने मामूली दामों पर चीनी मिलों को बेचने का काम किया था. इस प्रकरण की जांच सरकार तथा माननीय हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है. मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल के पेराई सत्र के शुभारम्भ के बाद किसानों को सम्बोधित करते हुए यह बात कही.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र देश की 60 प्रतिशत चीनी पैदा करते है. किसानों के करोड़ों परिवार गन्ने की खेती से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग तथा मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर चलने वाले लोग किसी भी स्तर पर किसानों को संकट में नहीं डालेंगे. सरकार द्वारा किसानों की हर स्तर पर मदद की जा रही है. वह गन्ना किसानों को चौधरी चरण सिंह के नाम पर लुभा रहे थे तो इस हकीकत से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि सपा नेतृत्व राष्ट्रीय लोकदल के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहता है. इधर, कुछ दिनों से रालोद गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर काफी तेजी दिखा रहा था. पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ तक में रालोद नेता धरना–प्रदर्शन कर रहे थे.

सीएम ने मेरठ पहुंचकर कई घोषणाएं की, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की मांग कर रहे वकीलों से उन्होंने मुलाकात करना उचित नहीं समझा. रालोद किसानों के गन्ने का हक मांगने आगे आया तो उन्हें पकड़ कर पुलिस लाइन भेज दिया गया. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उन्होंने सीएम के दौरे की हवा निकालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का यह दौरा अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए था. गन्ना मूल्य 350 रुपये नहीं घोषित किया गया. 2400 करोड़ का बकाया भुगतान बाकी है. रालोद के सांसद जयंत सिंह का कहना था कि राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है. रालोद गन्ना किसानों के हितों के लिए बड़ा आंदोलन करेगी. बसपा सांसद का कहना था कि यदि सरकार सख्ती भी करे तो भी 25 दिसंबर से पूर्व मिलों में पेराई शुरू नहीं हो सकती है. किसानों के मामले में यह सरकार फेल रही है. दंगे की आग शांत भी नहीं हुई थी और गन्ने की राजनीतिक फसल लहलहाने लगी है. विभिन्न दलों के सुरमा गन्ने की राजनीति को गरमाने का कोई भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं हैं.

सीएम के दौरे के दौरान 'गैर' ही नहीं, इनके अपने भी 'जख्म' देने में पीछे नहीं रहे. अखिलेश के सामने सपाई आपस में लड़ते रहे. टांग खिंचाई से शुरू हुई लड़ाई गाली–गलौच तक पहुंचने में देर नहीं लगी. मुख्यमंत्री के बगल में बैठने को लेकर सपा युवजन सभा के नेताओं में होड़ मची रही. अतुल प्रधान और मंत्री शाहिद मंजूर के समर्थक एक–दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करते रहे. हालात इतने बदतर हो गए कि अखिलेश को स्वयं मंच का संचालन करना पड़ गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

लखनऊ

खाद्य सुरक्षा बिल : सपा–कांग्रेस में टकराव

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के धरना–प्रदर्शनों, राजनीतिक दबाव और राहुल गांधी के हमलावर रुख के बाद भी अखिलेश सरकार खाद्य सुरक्षा बिल को लटकाए रखने के मूड में है. आम चुनाव के बाद ही राज्य की जनता को इसका फायदा मिल पाएगा. राज्य सरकार यह नहीं कह रही है कि वह इसे लागू नहीं करेगी. इसके लिए शासन स्तर पर फाइल चल रही है, लेकिन सब कुछ कच्छप गति से हो रहा है, ताकि कांग्रेस खाद्य सुरक्षा बिल के सहारे यूपी में अपनी जड़ें मजबूत न कर सके. सपा नेता कहते घूम रहे हैं कि अगर इतनी ही जल्दी है तो यह बिल साढ़े चार वर्षों तक क्यों लटकाए रखा गया. कांग्रेसी भी सब जान–समझ रहे हैं. उन्हें पता है कि वे चाहे जितनी ताकत लगा लें, आगामी लोकसभा चुनावों तक इस बिल को राज्य सरकार जान–बूझकर लटकाए रखेगी. केंद्र की इस योजना का लाभ चुनावों से पहले अगर आम जनता को मिलना शुरू हो गया तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा. कांग्रेस की मंशा को भांप कर प्रदेश भाजपा इकाई और बसपा नेताओं ने भी इस मामले पर चुप्पी साध लेना बेहतर समझा है. सरकार कहती है कि कागजों पर तैयार हो चुकी इस योजना को लागू कराने के लिए राज्य सरकार को काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी. जल्दी में बात बिगड़ सकती है.

अखिलेश सरकार अपनी मजबूरी गिनाते हुए कहती है कि जिस खाद्य एवं रसद विभाग पर इस योजना का सबसे बड़ा दारोमदार है, वह महकमा पहले से दुश्वारियों से जूझ रहा है. विभाग में अधिकारियों के पांच हजार पद रिक्त पड़े हैं. राशन कार्डों के नवीनीकरण का काम भी चल रहा है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा होना है. ऐसे में खाद्य सुरक्षा लागू करने के साथ खाद्य आयोग के गठन की नई जिम्मेदारी आ गई है.

वैसे भी राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बुरा

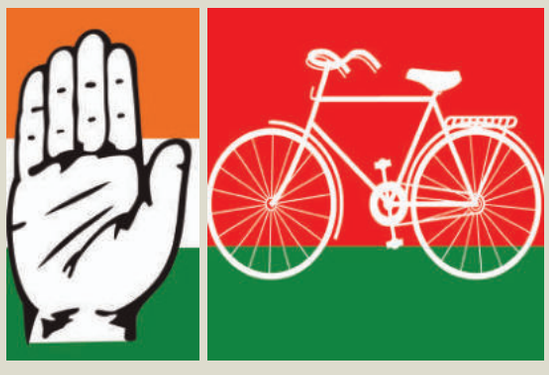

हाल है. एक करोड़ से ज्यादा राशन कार्डधारकों को समय से गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी तेल उपलब्ध कराना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं. वे चक्कर लगाने को मजबूर हैं. सरकार को नई योजना शुरू करने से पहले विभाग की दशा सुधारनी होगी. नई भर्ती करनी पड़ेगी. आर्थिक रूप से सरकार वैसे ही तंगी में चल रही है. वर्तमान समय में विपणन कार्य से जुड़े कर्मचारियों के करीबी 3900 और आपूर्ति से जुड़े 1500 अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने के साथ ही खाद्य एवं रसद विभाग में 10–12 हजार नये पद सृजित करना पड़ेगा. तब खाद्य सुरक्षा बिल को अमलीजामा पहनाया जा सकेगा.

राज्य सरकार पाल का घड़ा अपने सिर नहीं फोड़ना चाहती है. इसलिए उसने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन कर दिया है. खाद्य आयुक्त को इसका संयोजक बनाया गया है. योजना की मॉनीटरिंग के लिए एक आईएएस अधीकारी की भी तैनाती की गई है. राज्य खाद्य आयोग के गठन की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है. जिलाधिकारियों को सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना–2013 का काम तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. चार नोडल अधिकारी भी नियुक्त होंगे. राशन कार्डों से संबंधित सूचना का कार्य एनआईसी को दिया गया है, जिसके इसी माह के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह प्रभावित हुआ है.

बिल को लागू नहीं कर पाने की वजह वित्तीय समस्याओं से भी जुड़ी है. नियमानुसार, अनाज को कोटेदारों तक पहुंचाने का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, जबकि राज्य सरकार को उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए आयोग की स्थापना, उचित मूल्य के दुकानदारों को दिए जाने वाले लाभ के अंतर के साथ–साथ विभाग में नई भर्तियों और साथ ही उनके वेतन आदि की व्यवस्था करनी होगी.

गौरतलब हो कि खाद्य सुरक्षा केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को 35 किलो अनाज हर महीने कम मूल्य पर देने का प्रावधान रखा है. इन परिवारों को तीन रुपये प्रति किलो चावल, दो रुपये प्रति किलो गेहूं और एक रुपये प्रति किलो मोटा अनाज दिया जाएगा. हर तीन साल में योजना के अधीन आने वाले परिवारों की समीक्षा की जाएगी. देश में इस कानून का सबसे ज्यादा लाभ यूपी में 12 करोड़ लोगों को मिलेगा. अभी तक यूपी को 66 लाख टन अनाज मिलता था. अब 96 लाख टन मिलेगा. इससे 80 फीसद ग्रामीण और 65 फीसद शहरी जनता को लाभ मिलेगा.

वहीं अखिलेश सरकार कहती है कि केन्द्र ने सारी योजना हवा में बना दी है. न तो यह देखा गया कि इसके दायरे में कितनी आबादी आएगी, न ही य कि इसकी संख्या क्या होगी, न ही यह ध्यान दिया गया कि इसमें कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे. बताते चलें कि पिछले दिनों कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सरकार ने इसे सख्ती से कुचल दिया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

नुमाइशी शादियों पर रोक जरूरी है

कोई भी मज़हब दहेज प्रथा की इजाज़त नहीं देता. इस्लाम में भी दहेज लेने या देने की मनाही है और दहेज को इस धर्म में जुर्म माना गया है. बावजूद इसके, समाज में ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय में दहेज का बढ़ता हुआ चलन कल के तसव्वुर को, इन ग़रीब मां-बाप को ग़र्क में डालने की कोशिश है, ताकि ग़रीबों की बेटियां ग़रीबों के घरों तक ही महदूद रहें.

सैय्यद फ़िरोज़ुद्दीन

ताहिरा हसन

गुलाम जीलानी

सालिम अंसारी

सैय्यद शावेज़ फ़िरोज़

इस्लाम को नज़रअंदाज़ करते हुए डंके की चोट पर सौदेबाज़ी और ख़रीद-फ़रोख़्त का सिलसिला चल रहा है. बिना मोटरकार के बेटी ब्याहना अब सिर्फ़ ख़्वाबों और फ़िल्मों तक ही सीमित होकर रह गया है. ऐसे में ग़रीब मुसलमानों की बेटियां अपने बाबुल का घर छोड़ कर पिया की दहलीज़ तक कैसे पहुंच पाएंगी. यह एक सवाल है? इस दौर में मुस्लिम घरानों में जो शादियां हो रही हैं, वो बेलगाम, बेशुमार दान-दहेज, पैसे-रुपये के बलबूते पर नुमायशी अंदाज़ में की जा रही हैं, जिसका ख़ामियाज़ा ग़रीबों की बेटियां भुगत रही हैं. आख़िर इसमें इनका क्या कुसूर है? रोज़ कुआं खोदकर पानी पीने वाले कहां से दहेज में मोटरकार देंगे? बहरहाल, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है?

इसके लिए हम किसे ज़िम्मेदार ठहराएं? कोई भी मज़हब दहेज की इजाज़त कतई नहीं देता. इस्लाम में दहेज प्रथा को पाप बताया गया है, लेकिन जिस तरह से इस्लाम में दहेज प्रथा बढ़ता जा रहा है, वह चिंता का विषय है.

अब तो निकाह पढ़ाने वाले मौलाना भी हदिया के तौर पर 1100 रुपये से अपना निकाहनामा शुरू करते हैं. कहते हैं 300 रुपये तो रसीद का होता है, जबकि एक वक़्त था कि मौलाना निकाह पढ़ाते थे और चले जाते थे, जो कोई ख़ुशी से जो कुछ दे देता था, उसे वह तस्लीम करते थे. यह रिवाज आज मुस्लिम घरानों के ख़ासकर अगड़ों में मसलन मिल्क़ी, शेख, पठान, सैय्यद और सिद्दीक़ी तबक़ात में कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं. दूल्हा बेंचा और ख़रीदा जाने लगा है. दस लाख, 20 लाख या उससे भी ज़्यादा, चार पहिया लक्ज़री गाड़ी. यही नहीं, दहेज के सामान भी हमारे शहर से ख़रीदो और यहीं दे दो, जिसे न समाज देखे, न बिरादरी और नाम हो जाए कि सिर्फ़ कपड़े और गहने पर दुल्हन विदा हो गई. इस मुद्दे को संजीदगी से उठाते हुए चौथी दुनिया ने इस्लाम के नुमाइन्दों, समाजसेवियों, समाज शस्त्रियों सहित इन मुस्लिम दानिश्वरों की नब्ज़ टटोली. सबने एक लहजे में यही कहा कि नुमायशी लोगों के ख़िलाफ़ आवाम और मीडिया को मिलकर अवाज़ उठाने की ज़रूरत है और अपने पास-पड़ोस में बढ़ रहे दहेज के चलन पर पर्दा डालने और ख़ुद इसी नक़्शेकदम पर चलने के बजाए सख़्त क़दम उठाते हुए ऐसे लोगों को बिरादरी और समाज से बेदख़ल करने की मुहिम छेड़नी चाहिए, ताकि नुमायशी लोगों के ज़रिये बुना गया दौलत का ताना-बाना किसी ग़रीब की बेटी का हक़ न मार बैठे.

मदरसा इरफ़ानुल उलूम, इस्लामपुर, मुग़लसराय के नाजिम़ मौलाना गुलाम रसूल क़ासमी कहते हैं कि गरीबों में बारात और दहेज का तसव्वुर है ही नहीं. जो हो रहा है, सरासर ग़लत है. यह ग़ैर समाजी है, ग़ैर इस्लामी है, ग़ैर इस्लाही है. इस पर पाबंदी लगनी चाहिए. जहां तक निकाह पढ़ाने के हदिया की बात है तो पेशेवर लोगों ने अपना हक़ तैयार कर रखा है, जिनका काम है मिलाद पढ़वा लो, फ़ातेहा करवा लो, निकाह पढ़वा लो. बहरहाल, यह एक अच्छी बात है कि मुसलमानों के इस नुस्ख़े को कोई अख़बार उठा रहा है. ऑल इंडिया अख़बार नवीस एसोसिएशन के सदर सैयद फ़िरोज़ुद्दीन ने कहा कि क़ानून हो या मज़हब दहेज लेना और देना दोनों ही एक अभिशाप ही नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है. यह सिर्फ़ मुसलमानों पर ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में अहले क़बूल क़रार नहीं दिया गया है. जहां तक दीन-ए-इस्लाम की बात है, यहां अमीर और ग़रीब का कोई तक़वा नहीं है. यहां सर्फ़ और जमायत की बात की जाती है कि सब बराबर हैं. फिर अगर पैसों की नुमाइन्दगी, ताक़त की नुमाइन्दगी की जाती है और बड़े-बड़े ओलमा व समाजी कारकुनीन शामिल होते हैं, जिनके ज़रिये बढ़ती चली जा रही दहेज प्रथा पर कोई आवाज़ नहीं उठायी जाती, जबकि दुनिया भर के उलूल-जुलूल मुद्दों पर बहस की जाती है. अभी भी वक़्त है अहले इल्म मुसलमान इस पर कविश पा सकता है. सिर्फ़ ज़रूरत है दीन के आइने में इस्लाह की.

लखनऊ से जर्नलिस्ट व सोशल वर्कर ताहिरा हसन ने कहा कि मेरा यह मानना है कि ओलमा-ए-दीन ऐसे इशूज़ पर नहीं बोलते हैं. इनकी आवाज़ बेजा चीज़ों पर उठती है. मसलन, यह लिबास हराम है, वह पहनावा ख़राब है, फ़ोटो खिंचवाना हराम है, लड़कियों का बाहर निकलना व ऊंची तालीम हासिल करना अच्छा नहीं है, डबल बेड पर सोना हराम है, वग़ैरह-वग़ैरह. ग़रीब बच्चियों की शादी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, जिसे सभी जानते हैं. मेहनतकश बुनकर दम तोड़ रहा है. कर्ज़ में डूब रहा है. कौन है सुध लेने वाला. निकाह पढ़ाने का ऊंचा हदिया लिया जा रहा है. अनाप-शनाप तरह से पैसे की बर्बादी शादियों में की जा रही है. कौन बोलेगा? नहीं तो क्यों? कहीं से कोई किताबी प्रैक्टिकल अमल में नहीं है, जबकि इस्लाम सबसे ख़ूबसूरत मज़हब है. मर्दों के बराबर औरतों को बराबरी का दर्जा हासिल है, लेकिन इस आईन में कोई बेहतरी सोशल रीफ़ॉर्म के लिए नहीं की जा रही है. महंगी शादियों पर रोक लगनी चाहिए, मसला देना चाहिए, फ़तवा देना चाहिए. तब होगा अमल. उत्तर प्रदेश जामियतुर्रराइन के प्रदेश सचिव व प्रमुख समाजसेवी गुलाम जीलानी कहते हैं कि हमारी सब्ज़ीफ़रोश बिरादरी में तो दहेज न लेने और न देने के लिए एक आंदोलन, एक तहरीक़ बरसों से चलाई जा रही है. इस पर अमल भी हो रहा है. अगर कोई रिश्ता ज़रूरतमंद है और बेटी के लिहाज़ से क़ाबिल-ए-आएद है और इसे कुछ देना है ताकि परिवार ठीक-ठाक चले तो वह भी नुमाइश के हद के बाहर है. क्या दिया, क्या लिया, ख़ुद ने जाना. इसका असर और किसी पर नहीं पड़ा. मऊ के मेम्बर ऑफ़ पार्लियामेन्ट और शोहरत याफ़्ता मुस्लिम दानिश्वर सालिम अंसारी ने कहा कि जो ग़रीब है, उनको देख कर साहिब-ए-हैसियत वालों को फ़ैसला लेना चाहिए कि सिर्फ़ हमारी ही बेटी नहीं है, बल्कि और भी जो बेटियां हैं, वह भी हमारी बेटियां हैं, ताकि समाज में हर किसी के शौक़-अरमान पूरे हो सकें. दीन की हिफ़ाज़त हो सके. क़ानून की हिफ़ाज़त हो सके और बरारबी का ताना-बाना सामने नस्बुलऐन हो सके. फ़िलहाल, जो निज़ाम-ए-चलन है, वो ग़लत है मुख़ालफ़त होनी चाहिए. मुस्लिम दानिश्वरों की मैगज़ीनों की हवाले से ये इशूज़ उठने चाहिए. ■

लखनऊ से जर्नलिस्ट व सोशल वर्कर ताहिरा हसन ने कहा कि मेरा यह मानना है कि उलेमा-ए-दीन ऐसे इशूज़ पर नहीं बोलते हैं. उनकी आवाज़ बेजा चीज़ों पर उठती है. मसलन, यह लिबास हराम है, वह पहनावा ख़राब है, फ़ोटो खिंचवाना हराम है, लड़कियों का बाहर निकलना व ऊंची तालीम हासिल करना अच्छा नहीं है, डबल बेड पर सोना हराम है, वग़ैरह-वग़ैरह. ग़रीब बच्चियों की शादी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, जिसे सभी जानते हैं. मेहनतकश बुनकर दम तोड़ रहा है.

आपदा पीड़ितों पर सर्दी की आफत

रेनु शर्मा

दैवी आपदा में मारे गए लोगों पर सर्दी की आफत दस्तक दे रही है. भयंकर सर्दी उत्तराखण्ड में दस्तक दे चुकी है, पर आपदा में मारे गए लोगों को आज तक छत नसीब नहीं हुई. कई पीड़ित तो टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं. हाल यह है कि सरकार अपने किए वादे के अनुसार, एक भी आपदा प्रभावित को प्री फेब्रीकेटेड (रेडीमेड मकान) अब तक उपलब्ध नहीं करा पाई है. प्रभावितों के लिए बनाए जाने वाले रेडीमेड मकान की राह में जमीन रोड़ा बनी है. आपदा के करीब पांच माह बाद भी शासन जमीन के झगड़े में उलझा है. यह हाल तब है, जबकि केंद्र सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि जल्द आपदा प्रभावित गांवों को वन भूमि की जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी. भ्यूंदार और पुलना गांव के लोगों के हाल बहुत

बुरे हैं. ये गांव विस्थापन की जद में हैं और इन्हें करीब 99 परिवारों के लिए अदद जमीन की तलाश है. इस कारण इन लोगों के मकान भी नहीं बन पा रहे हैं.

इसी तरह चौमासी और गोंदार के लोग हैं, जो वन भूमि से घिरे हैं और इन्हें भी एक घर बनाने के लिए सुरक्षित जमीन नहीं मिल पा रही है. भ्यूंदार गांव के विक्रम सिंह के मुताबिक, इनसे कहा जा रहा है कि सुरक्षित जमीन बताओ तो मकान बना दिए जाएंगे. गांव के लोग जोशीमठ में रहने को विवश है. गांव के लोगों को एकमुश्त पैसा ही दे दिया जाता तो भी बात बनती. शासन का कहना है कि मकान के लिए पैसा भी किस्तों में दिया जाएगा. शासन के अनुसार, एकमुश्त पैसा इसलिए नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इस योजना को फाइनेंस कर रहा है और फाइनेंस बैंक की शर्त पर होगा. ■

देवभूमि बनी घोटालों की भूमि

राजकुमार शर्मा

देवभूमि के नाम से जाना जाने वाला उत्तराखंड अब भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए जाना जाता है. उत्तराखंड में जिन लोगों पर भ्रष्टाचार से लड़ने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं के दामन दागदार निकले. जांचों की रस्मअदायगी जरूर हुई, लेकिन न तो किसी पर आंच आनी थी, न ही किसी पर आई. अलबत्ता कांग्रेस-भाजपा में नूराकुश्ती खूब लड़ी गई. बारी-बारी से सत्ता में रही भाजपा और कांग्रेस ने एक-दूसरे को बचाने का ही काम किया. करोड़ों खर्च के बावजूद न कोई दोषी कानून की गिरफ्त में आया और न ही किसी ने सबक लिया. राज्य की उम्र बेशक कम हो, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में इसने पुराने राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया. 13 सालों में दर्जनों घोटालों ने प्रदेश को पीछे धकेला. यहां भ्रष्टाचार में सियासी मिलीभगत का लंबा सिलसिला है. 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा कांग्रेस सरकार के 56 घोटालों का था.

भाजपा ने चुनाव में जनता से वायदा किया था कि सत्ता में आते ही आयोग गठित कर तीन महीने के भीतर जांच पूरी कराकर दोषियों को सजा देंगे. जांच आयोग गठित हुए, तीन करोड़ रुपया खर्च हुआ. न जांच पूरी हुई और न ही किसी को सजा मिली और 56 घोटालों का डर दिखाकर भाजपा ने अपने पांच साल पूरे कर डाले. 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्य मुद्दा भाजपा के पांच साल के घोटाले ही थे. कांग्रेस ने भी वायदा किया था कि सैफ विंटर गेम से लेकर महाकुंभ, सिटूर्जिया घोटालों के लिए अलग से जांच आयोग गठित होगा और छह महीने के भीतर दोषियों को चिन्हित कर अभियोजन चलाया जाएगा. पहले भाटी आयोग बना, आयोग के अध्यक्ष केवल राम भाटी को राजनीतिक कारणों से इस्तीफा देना पड़ा. उसके बाद उसकी जगह त्रिपाठी आयोग का गठन हुआ. इस मामले में कांग्रेस भी भाजपा की राह पर है. सत्ता में आए दो साल बीत गए. नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा. मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा घोटालों के आरोपी निशंक से गलबंहिया किए घूम रहे हैं. यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार का दंश झेल रहे राज्य को पेशे से जज रहे विजय बहुगुणा को जनता के साथ न्याय करने की जिम्मेदारी सौंपी थी. जज साहब अपने नामी-गिरामी पिता पहाड़ के चंदन हेमवती नन्दन के नाम पर भी कालिख उड़ेलने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं. भाजपा के प्रति उनकी मेहरबानी की वजह से जनता उनके लिए चोर-चोर मौसेरे भाई की कहावत कहती है.

राज्य का दून कचहरी स्थित शहीद उद्यान राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उन प्रदर्शनकारियों से पटा रहा, जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए कुर्बानी दी थी. आज वही लोग जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की चाची अंशी बहुगुणा को अपनी पहचान, सम्मान और पेंशन के लिए एक बार फिर धरने और प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है. इसके लिए आत्मदाह करने के लिए भी वे तैयार हैं, ताकि शायद इसके बाद मुख्यमंत्री की आंखें खुलें. उन्हें सबसे ज्यादा दु:ख इस बात का है कि अब उनका भतीजा उन्हें पहचानता भी नहीं है. जब दून में लोग जश्न की तैयारी कर रहे थे, तब अंशी चाची खुले आसमान में धरना दे रही थीं.

उत्तराखंड को अलग करने की मांग के पीछे बड़ी वजह पहाड़ के युवाओं को रोजगार न मिलना और पलायन रही. राज्य बनने के 13 साल बाद ये समस्याएं घटी नहीं और विकराल होती गईं. आज स्थिति यह है कि पहाड़ पर गांव के गांव खाली होकर खंडहर हो रहे हैं, जबकि सात लाख से अधिक युवा आज भी नौकरी की बाट जोह रहे हैं. राज्य बनने के बाद पहाड़ों में पूंजी निवेश और बेरोजगारी की स्थिति चौंका देने वाली है.

सरकार का उद्योग निदेशालय की एक रिपोर्ट यह कहता है कि उत्तराखंड में अब तक 7739 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ और 1,59,660 लोगों को रोजगार मिला. पर्वतीय जिलों की स्थिति दयनीय है. पहाड़ी जनपदों में रुद्रप्रयाग में 827 उद्योग लगे, जिनमें 2137 लोगों को रोजगार मिला. इसी तरह चंपावत में 752 उद्योगों में 1665 युवाओं को रोजगार मिला, जबकि बागेश्वर में 716 उद्योग लगे और 1510 लोगों को रोजगार मिला. अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी में बेरोजगारी का आंकड़ा 30 हजार से 60 हजार तक है. राज्य गठन के बाद पर्वतीय जिलों की पूरी तरह अनदेखी हुई. थोड़ा बहुत जो विकास हुआ, वह मैदानी जिलों हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून तक ही सिमटकर रह गया. जनता विकास को तरसती रही और इन 13 वर्षों में मंत्री और अफसर विदेशों की सैर करते रहे.

राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने शहीद स्थल पहुंचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वन अधिकार कानून लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पंडित दीनदयाल पार्क में तीन दिन से उपवास कर रहे महिला मंच के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को शहीद स्थल के अंदर प्रवेश न करने देने का ऐलान किया था. इसके लिए वे शहीद स्थल के गेट पर बैठ गईं. पुलिस से महिला मंच के करीब 25-30 महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया, जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने शहीद स्थल आए थे. राज्य आंदोलनकारियों ने स्थापना दिवस पर आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की तीव्र भर्त्सना की है. उन्होंने कहा कि राज्य के लिए लाठी-डंडे खाने वाले आंदोलनकारियों को स्थापना दिवस पर गिरफ्तार करना आंदोलनकारियों का अपमान है. ■

feedback@chauthiduniya.com

छात्र विरोधी है विश्वविद्यालय प्रशासन

मारकण्डेय प्रसाद सिंह

पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर पिछले दिनों गोरखपुर स्थित दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएसी प्रथम वर्ष की छात्रा कुमारी संध्या यादव सहित अन्य की पिटाई कर दी गई थी. छात्राओं की निर्मम पिटाई विश्वविद्यालय नियंता के इशारे पर पुलिस द्वारा की गई थी. जिसके बाद से ये छात्राएं उग्र आन्दोलन के लिए बाध्य हो गईं थीं, लेकिन सांसद योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद अब यह आंदोलन खत्म हो गया है. अब विश्वविद्यालय प्रशासन को बीएसी प्रथम वर्ष के छात्रों की मांगों के निस्तारण के लिए जरूरी पहल करनी है. इसी बीच एमए, प्रथम वर्ष, भूगोल की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन

के क्रियान्वयन को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्थगित करने की कार्रवाई से इस पूरे प्रसंग को एक नई दिशा में मोड़ दिया है. ज्ञात है कि एमए, प्रथम वर्ष, भूगोल का परीक्षा फल 11 अक्टूबर को घोषित किया गया था. इसमें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध लगभग सभी महाविद्यालयों को मिलाकर 95 प्रतिशत विद्यार्थी फेल कर दिए गए थे. विद्यार्थियों के आन्दोलन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन करवाया, जिसमें 85 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए. उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने अपने पुराने अंक पत्र जमा कर नये अंक पत्र भी प्राप्त कर लिए और इसी आधार पर वे अगली कक्षा में प्रवेश भी ले चुके हैं. ऐसी स्थिति में पुनर्मूल्यांकन स्थगित करने से सम्बन्धित विश्वविद्यालय प्रशासन की खबर ने जागरूक लोगों को हिलाकर रख दिया है. छात्र विरोधी विश्वविद्यालय प्रशासन के इस रवैया के बाद पूर्वांचल की छात्र राजनीति एक बार पुन: गर्माती नजर आ रही है. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामंत्री एवं कांग्रेस नेता राजेश तिवारी ने छात्र हित में विश्वविद्यालय प्रशासन से एमए प्रथम वर्ष भूगोल के चार प्रश्नपत्रों के स्थगित पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा है और ऐसा न होने पर आन्दोलन की चेतावनी दी है. दूसरी तरफ इस आदेश से पीड़ित एवं उसके समर्थन में उतरे विश्वविद्यालय से वरिष्ठ छात्र नेताओं सहित विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने आन्दोलन की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिए गए छात्र विरोधी निर्णय को देखकर कोई भी व्यक्ति हैरान हो सकता है. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परेशान करने के मामले पहले भी कई बार सामने आए हैं. जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती, तब तक प्रशासन का ध्यान उधर नहीं जाता है. प्रशासन की अपनी नीति क्या है? क्या प्रशासन ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पहले से कोई व्यवस्था बना रखा है? कुछ घटनाएं, जो आम छात्रों को नागवार गुजरती है कि आखिर इन सभी मुद्दों पर लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता? बहरहाल, आन्दोलनरत विश्वविद्यालय के छात्रों पर 21 नवम्बर को पुलिसिया कहर का सच जानने के लिए जिला प्रशासन सी-सीघटीवी फुटेज की मदद लेगा. छात्र उपद्रव से सहमा विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षाफल में व्यापक तौर पर विसंगतियां होना स्वीकार करते हुए इसकी भरपाई में लग गया है. छात्रों की समस्याओं को निजात दिलाने में विश्वविद्यालय प्रशासन कहां तक सफल होगा, यह तो समय ही बताएगा, पर छात्रों पर पुलिसिया कहर के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को ही पूर्णरूपेण जिम्मेदार माना जा रहा है. यह भी सच है कि अगर समय रहते विश्वविद्यालय प्रशासन विवेक से काम लिया होता तो इन घटनाओं से बचा जा सकता था.

सांसद योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों पर हुए लाठी चार्ज की निन्दा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है. गोरखपुर नगर निगम की मेयर सत्या पाण्डेय ने भी घटना की निन्दा करते हुए कहा है कि परीक्षा की गड़बड़ी दूर होने तक वह विद्यार्थियों के साथ हैं. समाजवादी पार्टी एमएलसी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार में डुबा है. छात्र हित को लेकर कुलपति गम्भीर नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मसूरी में तेंदुलकर बनाएंगे आशियाना

रेनु शर्मा

पिछले दिनों सचिन तेंदुलकर मसूरी में थे. मास्टर-ब्लास्टर पहाड़ों की रानी मसूरी में अपना आशियाना बनाना चाहते हैं. वह मसूरी के खूबसूरत नजारों और यहां के लोगों के व्यवहार से अभिभूत नजर आए. इनके मसूरी प्रेम को देखते हुए माना जा रहा है कि वह यहां आशियाना बना सकते हैं. सचिन ने मीडिया से कहा कि मसूरी का मौसम बेहद सुहावना है. यही कारण है कि वह यहां आते रहते हैं. उन्होने पहाड़ों की रानी मसूरी की मुक्त कंठ से सराहना कर के अपनी इच्छा जगजाहिर कर दी. उन्होंने मसूरी प्रवास को यादगार बताया.

सचिन का मसूरी में यह पांचवां प्रवास था. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वह मसूरी आए थे. मसूरी से रवाना होने से पहले सचिन ने होटल रूकबी मेनर, बोथवेल बैंक, सफाई कर्मचारी, पुलिस फोर्स समेत उनकी सेवा में लगे स्टाफ को ऑटोग्राफ दिए और उनके साथ फोटो खिंचवाई. ऑटोग्राफ और फोटो खिंचवाने में सचिन को इतना वक्त लग गया कि वे नाश्ता करना भूल गए. सचिन ने मीडिया के सामने जिलाधिकारी के विंटर कार्निवाल के न्योते को सीधे तौर पर नहीं स्वीकारा. सचिन ने इसके लिए दूसरा रास्ता निकाला. सूत्रों ने बताया कि सचिन ने अपने एक उत्तराखंडी फिल्म लेखक और कलाकार से संपर्क कर कार्निवाल का वीडियो तैयार करने कहा है, जिसके माध्यम से वह मसूरी में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाले विंटर कार्निवाल में शुभकामनाएं देंगे. पहली बार ऐसा हुआ कि सचिन के फैन कम और सुरक्षाकर्मी अधिक थे .विदाई के वक्त बोथवेल बैंक पर प्रशंसक गिने-चुने थे. पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की तादाद 25 से अधिक थी. इसके बाद सचिन तेंदुलकर मुंबई के लिए रवाना हो गए. जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने प्रशंसकों के साथ फोटो खिंचवाई और आटोग्राफ दिए.■

feedback@chauthiduniya.com

प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद के लिए गहमागहमी

यशपाल आर्य के इस्तीफे के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कुर्सी के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक गहमागहमी है. पौने दो साल से गुटीय संघर्ष में फंसी अध्यक्ष की कुर्सी के मुक्त होने के बाद एक बार फिर जंग तेज हो गई है. आम कार्यकर्ता अध्यक्ष की कुर्सी को लोकसभा और पंचायत चुनाव के नजरिये से देख रहा है. प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में दखल रखने वालों के लिए जीत, हार के रूप में मानी जा रही है. यही वजह है कि 'कांटों भरा ताज होने' के बावजूद कुर्सी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है. इस जंग में एक बार फिर गुटों में बटी कांग्रेस के बहुगुणा-हरीश गुट इस कुर्सी को अपने पाले में लाने की हर दांव खेल रहा है.

एक व्यक्ति एक पद के फार्मूले को अमल में आने के बाद सत्तारूढ़ दल में एकाएक सरगर्मी बढ़ गई है. दिल्ली में इस्तीफा देने के बाद देहरादून में आर्य के यमुना कालोनी स्थित मंत्री आवास पर दिनभर मीडिया व पार्टी कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा. माना जा रहा है कि आर्य की टीम के लिए उनका इस्तीफा लगभग अप्रत्याशित था. उनकी कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग आर्य के इस्तीफे को महज मीडिया का प्रचार करार दे रहे थे. देहरादून पहुंचकर आर्य की हामी के बाद कार्यकारिणी व समर्थकों को यकीन हुआ कि उन्होंने वास्तव में इस्तीफा दे दिया है. मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के अचानक दिल्ली से देहरादून पहुंचने के बाद उनके निवास पर समर्थक पहुंचे. बताया जाता है कि बहुगुणा ने समर्थकों को सिर्फ इतना कहा कि जो भी होगा, अच्छा होगा और कुछ घंटे बाद वापस दिल्ली लौट गए. सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री से उनके आवास पर पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट व पीसीसी उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी अलग-अलग बात की. दोपहर बाद पूर्व मंत्री बिष्ट ने विधानसभा पहुंचकर वित्त मंत्री डॉ. इंदिरा हृदयेश व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी से भेंट की. काबीना मंत्री डॉ. हृदयेश, प्रीतम सिंह, सुरेंद्र नेगी, सांसद प्रदीप टम्टा, पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह के साथ हीरा सिंह बिष्ट का नाम भी अध्यक्ष की कुर्सी के दावेदारों में जुड़ गया है. प्रीतम सिंह के बाद बिष्ट मुख्यमंत्री बहुगुणा के पसंद के दावेदार बताए जाते हैं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने को लेकर लंबे अरसे से लगाए जा रहे कयासों पर मौजूदा अध्यक्ष यशपाल आर्य ने ही विराम लगा दिया. विजय बहुगुणा सरकार में काबीना मंत्री आर्य ने अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा पार्टी हाईकमान को सौंप दिया. आगामी लोकसभा एवं पंचायत चुनाव से ऐन पहले आर्य के इस्तीफे से सूबाई सियासत गरमा गई है. प्रदेश अध्यक्ष पद से आर्य के इस्तीफे को आगामी लोकसभा चुनाव की चुनौती से जोड़कर देखा जा रहा है. कांग्रेस में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता के साथ आर्य के कार्यकाल में राज्य की पांचों संसदीय सीट कांग्रेस को मिली शानदार जीत ने आर्या को एक सफल नेता की श्रेणी में खड़ा करने के साथ ही सर्वमान्य नेता बना दिया था. आर्या के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ मायावती का दलित वोट पर पड़ने वाले असर को भी रोकने में सफलता प्राप्त की. इन सब के बाद भी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धान्त के कारण इन्हें पद छोड़ना पड़ा.

इस सिद्धांत का हवाला देकर लंबे अरसे से पार्टी के भीतर एक खेमा आर्य पर निशाना साधता रहा है. इस वजह से लंबे अरसे से अध्यक्ष बदलने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे. इन कयासों को तब और बल मिला, जब पार्टी के कई केंद्रीय नेताओं ने इसी तरह के संकेत दिए.

जानकार कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर लगातार खींचतान के माहौल से आजिज आ चुके आर्य इससे पहले दो बार इस्तीफे की पेशकश हाईकमान को कर चुके थे. बतौर अध्यक्ष छह साल का कार्यकाल पूरा कर चुके आर्य अपनी यह इच्छा सार्वजनिक रूप से जाहिर करने से नहीं चूके. राज्य की बहुगुणा सरकार द्वारा संगठन के लोगों को लालबत्ती का सम्मान न दिए जाने से आर्य सरकार में रह कर अपने सरकार के मुखिया से नाखुश चल रहे थे.

यही नहीं, सरकार और संगठन के बीच तालमेल में खिंचाव की नौबत भी आई. गाहे-बगाहे महत्वपूर्ण अवसरों पर उपेक्षा से आर्य खफा भी हुए. पार्टी के सामने लोकसभा से पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव की चुनौती है. इन चुनाव से ऐन पहले आर्य के इस्तीफे को पार्टी के लिए भी सियासी चुनौती से कम नहीं आंका जा रहा है. आर्य अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं. हाईकमान अब एक सफल अध्यक्ष की तलाश में है, जिसका व्यक्तित्व किसी तरह से आर्य से कम प्रभावी न हो.

रो पड़े आर्या

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले यशपाल आर्य इसे सामान्य घटनाक्रम बता रहे हैं. उनके भीतर कुछ असंतोष और दर्द भी है, जिसे वह मीडिया के सामने छुपा नहीं सके. इस्तीफे को लेकर आर्य से मिलने पहुंचे मीडिया ने जब उन्हें कुरेदा तो इस्तीफा देने का कारण तो एक व्यक्ति एक पद ही था. संगठन को महत्व न देने और कुछ कार्यकर्ताओं को सरकार में पद और लाल बत्ती न दिला पाने का मलाल भी सामने आया. दलित परिवार में जन्मे और एक आम कार्यकर्ता से इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी सुनाते हुए उनकी आंखें भर आईं. उनका कहना है कि पार्टी से उन्हें बहुत कुछ मिला है. इसके लिए वह सोनिया-राहुल गांधी को धन्यवाद देते हैं. आर्य के इस्तीफे पर बोलते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि यशपाल आर्य का इस्तीफा एक व्यक्ति एक पद के तहत है और इसे लेकर किसी तरह का कोई विवाद या नाराजगी नहीं है. बहुगुणा ने कहा कि आलाकमान के निर्देश थे कि आपदा के दौरान किसी को लाल बत्ती बांटना ठीक नहीं होगा. ■

राजकुमार शर्मा

feedback@chauthiduniya.com

श्री नरहेजी महाविद्यालय नरही (रसड़ा) बलिया, उत्तर प्रदेश की ओर से छात्रों, महाविद्यालय कर्मचारियों, अभिभावकों सहित समस्त नागरिकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

विजय कुमार सिंह
प्रबन्धक

डॉ. श्रीमती सुशीला सिंह
प्राचार्य

05491-231414, 221415, 9415248334, 9450083253, 9415319810, 9838391084

संचालित विषय/पाठ्यक्रम

स्नातक स्तर पर कला संकाय : हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, समाज शास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिक शास्त्र शिक्षा छात्र, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, पत्रकारिता, मध्यकालीन इतिहास, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेलकूद.
विज्ञान संकाय : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, सैन्य विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान.
स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय : बी.सी.ए., बी.टी.सी. पाठ्यक्रम, बी.पी.एड. पाठ्यक्रम.
स्नातकोत्तर स्तर पर : प्राचीन इतिहास, समाज शास्त्र, भूगोल, संस्कृत हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी एवं गृह विज्ञान.

अजय कुमार , लखनऊ ब्यूरो प्रमुख कार्यालय का पता : जे-3/2 डॉलीबाग़, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन -(0522) 2204678/09415005111

सपा प्रमुख के तेवरों ने अन्य नेताओं की जुबान भी तल्ख कर दी. राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता राम गोपाल यादव ने नेता जी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं. सांप्रदायिक ताकतें कहीं भी गड़बड़ी कर सकती थीं, किन्तु समाजवादी पार्टी की रैलियों में भारी भीड़ देखकर उनके हौसले पस्त हो गए हैं. देशभर में एक व्यक्ति विशेष को बहुत भाव दिया जा रहा था, लेकिन आजमगढ़, मैनपुरी और बरेली की रैलियों के बाद लोग समाजवादी पार्टी की ताकत को मानने लगे हैं.

कतर्निया में विदेशी पक्षियों और डॉल्फिन की अठखेलियों का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक

राकेश चन्द्र श्रीवास्तव

भारत–नेपाल सीमा स्थित अपने प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों के लिए दुनियाभर में विख्यात कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग में पर्यटकों व वन्य जीवन प्रेमियों का तांता लगा हुआ है. ठंड की आहट के साथ ही कतर्निया में साइबेरियन मेहमानों ने दस्तक दे दी है. इस वन्य प्रभाग में स्थित गेस्ट हाउस में पर्यटकों के लिए खास तौर पर बनाए गए थारू हटों में यहां आने वाले लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है. नेपाल की ओर आने वाली गेरूआ और कौड़ियाला नदियों में डॉल्फिन की उछाल तथा धूप का आनंद उठाने आने वाले मगरमच्छों व घड़ियालों को देखने वालों की भीड़ दिनभर जमा रहती है. साइबेरियन देशों के अलावा चीन व अन्य ठंडे देशों से 25 प्रजातियों के पक्षी भारतीय क्षेत्र के कतर्निया जंगल में प्रवास के लिए प्रतिवर्ष आते हैं. कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग भारत–नेपाल सीमा पर बहराइच जिले के नानपारा तहसील में स्थित है. तराई इकोसिस्टम का विशिष्ट उदाहरण यह प्रभाग लगभग 551 वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ है. जैव विविधता एवं बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 2003 में वन जीव प्रभाग कतर्निया घाट को 'प्रोजेक्ट टाइगर' में सम्मिलित किया गया है. कल–कल करती आकर्षक गेरूआ नदी में डॉल्फिन मछलियों के उछाल, विशालकाय मगरमच्छों, घड़ियालों तथा कछुए पर्यटको को लुभा रहे हैं. बड़े–बड़े घास के मैदानों, साल के घने वनों तथा जलीय क्षेत्रों को अपने में समेटे यह वन्य जीव प्रभाग जैव विविधता के मामले में अति समृद्ध क्षेत्र है. वृक्षों की शाखाओं पर आराम करते तेंदुए, कुलांचे भरते चीतल, पाढ़ा, बारासिंघे, सांभर, काकड़ तथा लम्बे थूथुन से वन भूमि खोदते जंगली सुअरों और वृक्षों की डालों पर झूलते बन्दरों और लंगूरों का अवलोकन पर्यटकों का मन मोह रहा है. वन जीवों के अवलोकन हेतु भ्रमण पर आए

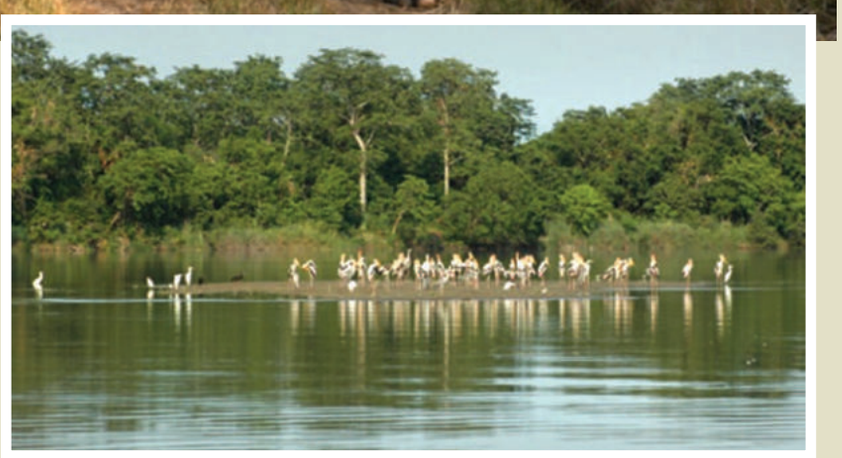

पर्यटकों को गेरूआ तथा कौड़ियाला नदियों के संगम से उत्पन्न घाघरा नदी पर बना गिरिजापुरी बैराज आकर्षित कर रहा है. ठंड की शुरुआत होते ही विदेशी तथा अप्रवासी जलीय पक्षियों का बसेरा गेरूआ नदी के साथ–साथ बैराज के जल में होता है जो इसकी सुन्दरता में चार चांद लगाता है. जलीय पक्षियों में लालसर, सुर्खाब, सींखपर, नीलसर, नकटा, गुगराल, काज, कुर्छिया, तथा छोटी मुर्गाबी आदि देखने को मिल रही हैं. जबकि मोर, जंगली मुर्गा, तीतर, धनेश, लगलग, बगुला, पनडुबी, सारस, गिद्ध, बाज, चील, उल्लू, छपका, नीलकंठ, कठफोड़वा, खंजन, जंगली मैना, जंगली कौवा, बुलबुल, सतबहिन, तोते आदि पर्यटकों को लुभा रहे हैं. गेरूआ नदी पार के वनों में मोटी खाल तथा नाक पर सींग वाले भारी भरकम गैंडे तथा हाथियों के झुंड स्वच्छंद विचरण करते दिखाई पड़ रहें है.

कतर्निया घाट अभयारण्य घोषित होने के बाद से ही पर्यटकों व वन जीव जन्तु प्रेमियों की निगाह में चढ़ चुका है. यही कारण है कि सर्दियां शुरू होते ही समूचे वन क्षेत्र में पर्यटको की आमद बढ़ जाती है. पर्यटकों के भ्रमण के लिए दो प्रशिक्षित हाथियों चंपा और जयमाला को लगाया गया है. जिसपर बैठक कर पर्यटक ठंड का आनंद ले रहे हैं.

कतर्निया के आकर्षण का आलम यह है कि वन क्षेत्र के आस–पास बसे ग्रामीणांचल बिछिया, निशानगाड़ा, मोतीपुर, मिहीपुरवा, कैलाशपुरी गिरजापुरी, कारीकोठ, बार्दिया व फकीरपुरी, नैनिहा, नयी बस्ती आदि गांवों में भी पर्यटक ठहर कर जंगल व नदी बिहार का आनंद ले रहे हैं. मेहमान पक्षियों के कलरव व हाथियों की चिघाड़ से समूचा वन क्षेत्र गूंज रहा है. वन विभाग के रिकार्ड के मुताबिक 2004–2005 में केवल 35 पर्यटक यहां आए थे. जो 2012 में बढ़ कर चार हजार हो गए थे. 2013 के शुरुआत में ही एक हजार पर्यटक वन क्षेत्र में आ चुके हैं. डब्लूडब्लूएफ के परियोजना अधिकारी दबीर हसन ने बताया कि साइबेरियन देशों के अलावा अन्य ठंडे देशो से सुर्खाब, पिनटेन, फिशलिंग टिल्स, लालसर, नीलसर, ब्राह्मीडक, कामनकूट पक्षी कतर्निया जंगल में प्रवास कर रहे हैं. यह पक्षी तीन माह तक यहां रहेंगे तथा गर्मी की दस्तक के साथ ही यह पक्षी पुन: हिमालय पार कर अपने देश वापस लौट जाएंगे. डीएफओ आशीष तिवारी ने बताया कि कतर्निया घाट संरक्षित वन क्षेत्र में स्थित तालाब, झील व नदियों में प्रवास करने वाले पक्षियों की सुरक्षा के लिए सभी रेंजों के वन क्षेत्राधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

लखनऊ

सपा सरकार की बदनीयती

संदीप कश्यप

प्याज भी खाया जूते भी, यह कहावत आजकल उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार पर सटीक ढंग से चरितार्थ हो रही है. जब सरकारें विधि द्वारा स्थापित कायदे–कानून को अनदेखा कर जनहित की बजाए वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर फैसले लेती हैं, तो ऐसी ही स्थिति आती है. ऐसे अलोकतांत्रिक फैसलों के खिलाफ न्यायपालिका को न चाहते हुए भी सरकार के काम में हस्तक्षेप करना पड़ता है. मामला हाल में ही अखिलेश सरकार के दो गलत फैसलों पर न्यायपालिका की असहमति से जुड़ा था. पहला मामला अखिलेश सरकार की 'हमारी बेटी उसका कल' योजना से और दूसरा मुजफ्फनगर–शामली दंगा पीड़ित मुस्लिम परिवारों को मुआवजा देने से संबंधित था. उक्त दोनों फैसले सपा सरकार ने

भेद–भाव से लिए थे और दोनों ही मामलों में फायदा और मुआवजा मुस्लिम परिवारों तक ही सीमित कर दिया था. बात पहले करते हैं मुजफ्फरनगर–शामली दंगों की. इन दंगों में दर्जनों लोगों की मौत और करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था. कई लोग डर के मारे अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो गए. हिंसा का तांडव लंबा चला था, लेकिन जब दंगा पीड़ितों और मृतकों को मुआवजा देने की बात आई तो राज्य सरकार ने 26 अक्टूबर के अपने शासनादेश में सभी दंगा पीड़ितों की बजाए सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही पांच लाख रुपये की मदद का ऐलान कर दिया. मुजफ्फरनगर दंगों की जांच पर पैनी नजर रख रहे सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह बात आई तो कोर्ट ने 21 नवंबर को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को भेद–भावपूर्ण तरीके से मुआवजा बांटने के लिए कड़ी फटकार लगाई और आदेश बदलने को कहा. इसके बाद अखिलेश सरकार ने 26 अक्टूबर के अपने शासनादेश में सुधार करते हुए सभी दंगा पीड़ितों को राहत का ऐलान किया.

इसी तरह से राज्य सरकार ने मुस्लिम परिवारों की दसवीं पास लड़कियों की आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह के लिए तीस हजार रुपये के अनुदान की घोषणा की थी. इस योजना से गैर मुस्लिम लड़कियों को दूर रखा गया था. सरकार के इस भेद–भाव पूर्ण रवैये के खिलाफ कुछ लोगों ने अदालत में जनहित याचिका दायर करके सरकार के फैसले पर रोक लगाने या बदलने का दबाव बनाया था. अदालती दबाव के बाद अखिलेश सरकार ने सभी धर्मों की लड़कियों को बीस हजार रुपये की आर्थिक मदद का आदेश पारित किया. यह सिर्फ दो मामले ही नहीं हैं. इससे पूर्व भी आतंक फैलाने को लेकर आरोपियों को छोड़े जाने की अखिलेश सरकार की कोशिशों, पुलिस भर्ती में आरक्षण जैसे तमाम मामलों आदि पर भी राज्य सरकार को न्यायपालिका से मुंह की खानी पड़ी है. अभी भी मुजफ्फरनगर और शामली के दंगों के बाद एक समुदाय विशेष के परिवारों के करीब पौने दो हजार शस्त्र लाइसेंस रद्द करने का मामला इलाहाबाद की उच्च अदालत में चल रहा है. इस मसले में भी अखिलेश सरकार की काफी फजीहत हो रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मिशन–2014 के लिए मुलायम की पाठशाला

रवि प्रकाश

समाजवादी पार्टी के छोटे–बड़े सभी नेता मिशन 2014 के लिए कमर कस कर मैदान में उतर पड़े हैं. शायद ही कोई दिन ऐसा होगा, जब सपा नेता चुनावी जंग जीतने के लिए न जुटते हों. कभी जनता के बीच, तो कभी कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा ही रहता है. अन्य नेताओं की तो बात दूर, पार्टी के 75 वर्षीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी दिल्ली का तख्त कब्जाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं. उनका एक पैर दिल्ली में तो दूसरा प्रदेश की राजनीति में धंसा रहता है. पिछले दिनों वे पार्टी मुख्यालय लखनऊ में जमे रहे. वह स्वयं तो मनोबल से लबरेज थे ही, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का भी उन्होंने पूरे मनोयोग से प्रयास किया. उनका कहना था कि देश की आज जो राजनीतिक स्थिति है, इसमें तीसरे विकल्प की संभावनाएं प्रबल हैं. इस विकल्प में समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका तय है, क्योंकि यह सबसे बड़ी पार्टी है और प्रदेश में भी इसकी बहुमत की सरकार है. दिल्ली में समाजवादी पार्टी की निर्णायक भूमिका के लिए ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के सांसदों की जीत जरूरी है. उन्होंने कहा कि समाजवादी इतिहास रचते हैं. रायबरेली से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समाजवादी राजनारायण ने ही पराजित किया था. जोखिम उठाने की समाजवादी पार्टी के इस चरित्र की वजह से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ. अब केंद्र की बारी है.

यादव ने पार्टी पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वे अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख की पुतली यानी दिल्ली की गद्दी पर अपना निशाना रखें. समाजवादी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी तो महंगाई खत्म होगी. समाज के वंचितों और कमजोर वर्ग को न्याय मिलेगा. एक बात तय है कि इस बार लोकसभा चुनावों के बाद न तो भाजपा की सरकार बनेगी और न ही कांग्रेस की. तीसरे मोर्चे की सरकार ही बनना तय है. यादव पार्टी मुख्यालय में समाजवादी पार्टी के सांसदों, विधायकों, लोकसभा प्रत्याशियों, प्रभारियों, जिला पंचायत अध्यक्षों, जिला/महानगर अध्यक्षों, महासचिवों, युवा प्रकोष्ठों, महिला सभा व पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला/महानगर

अध्यक्षों तथा प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों की क्लास ले रहे थे.

यादव ने कहा कि जब हमारी बहुमत की सरकार नहीं थी, तब हमने 39 सीटें जीती थीं, आज तो हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार है. जनता को ऐसी सुविधाएं कहीं नहीं दी गई हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार ने दी है. यादव ने कहा कि देश के कई दल भी उम्मीद करते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतकर आएगी और वे इसका साथ देंगे.

सपा प्रमुख के तेवरों ने अन्य नेताओं की जुबान भी तल्ख कर दी. राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता राम गोपाल यादव ने नेता जी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं. सांप्रदायिक ताकतें कहीं भी गड़बड़ी कर सकती थीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की रैलियों में भारी भीड़ देखकर उनके हौसले पस्त हो गए हैं. देशभर में एक व्यक्ति विशेष को बहुत भाव दिया जा रहा था, लेकिन आजमगढ़, मैनपुरी और बरेली की रैलियों के बाद लोग समाजवादी पार्टी की ताकत को मानने लगे हैं. उन्होंने कहा कि जिन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है, उनकी मदद सभी को मिलकर करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव तैयारी की समीक्षा से स्पष्ट है कि अभी इसमें और ज्यादा तेजी तथा काम की जरूरत है. प्रो. रामगोपाल यादव ने घोषणा की कि 14 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली सामाजिक न्याय रैली स्थगित कर दी गई है.

मौका चुनावी चर्चा का था तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सपा के प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते पूरे रौ में दिखे. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अब 120 दिन रह गए हैं. सरकार अपना काम कर रही है. इसकी उपलब्धियों की नकल दूसरे सूबे की सरकारें भी करने को बाध्य हैं. इन जनहितकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए. राज्य में बहुमत की सरकार है. इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा. बिजली उत्पादन के लिए ललितपुर और इलाहाबाद में बिजलीघर लग रहे हैं. घोषणा पत्र को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है. अखिलेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को एकजुटता के साथ जिताने का संकल्प लेना होगा. उन्होंने कहा कि अभी जो ताकतें टीवी और प्रिंट मीडिया में दिख रही हैं, वे ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं हैं. हमें संगठन के स्तर पर ऐसी तैयारी करनी है कि जनता के बीच समाजवादी पार्टी के पक्ष में अनुकूल राय और माहौल बन सके.

वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद आजम खां का लहजा स्वभाव के अनुसार तल्ख रहा. उनका कहना था कि सांप्रदायिक ताकतों ने हमें चुनौती दी है. ऐसे में हमें अपना लक्ष्य तय कर लेना है. हम दुविधा में नहीं रहें. हमारा रास्ता धर्मनिरपेक्षता का है, सांप्रदायिकता का नहीं. फासिस्ट ताकतों की चुनौती का सामना करते हुए समाजवादी पार्टी की बरेली रैली की विशालता ने साबित कर दिया कि जनता किसके साथ है. भाजपाई मुस्कराकर मिलें तो भी उन पर विश्वास नहीं करना. ये साजिशकर्ता लोग हैं. उन्होंने कहा कि जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं, वहां के लोग भी मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे देखना चाहते हैं. वही ऐसे शख्स हैं, जो धर्म से ऊपर देश को मानते हैं. वही सामाजिक न्याय दिलाने में सक्षम हैं और जो कमजोर हैं, उनका उन्हीं पर विश्वास है. मो. आजम खां ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में दिल्ली पर कब्जे के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
आवश्यकता है
संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि
चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.
E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120–6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627379